चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 03 अक्टूबर- 09 अक्टूबर 2016 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

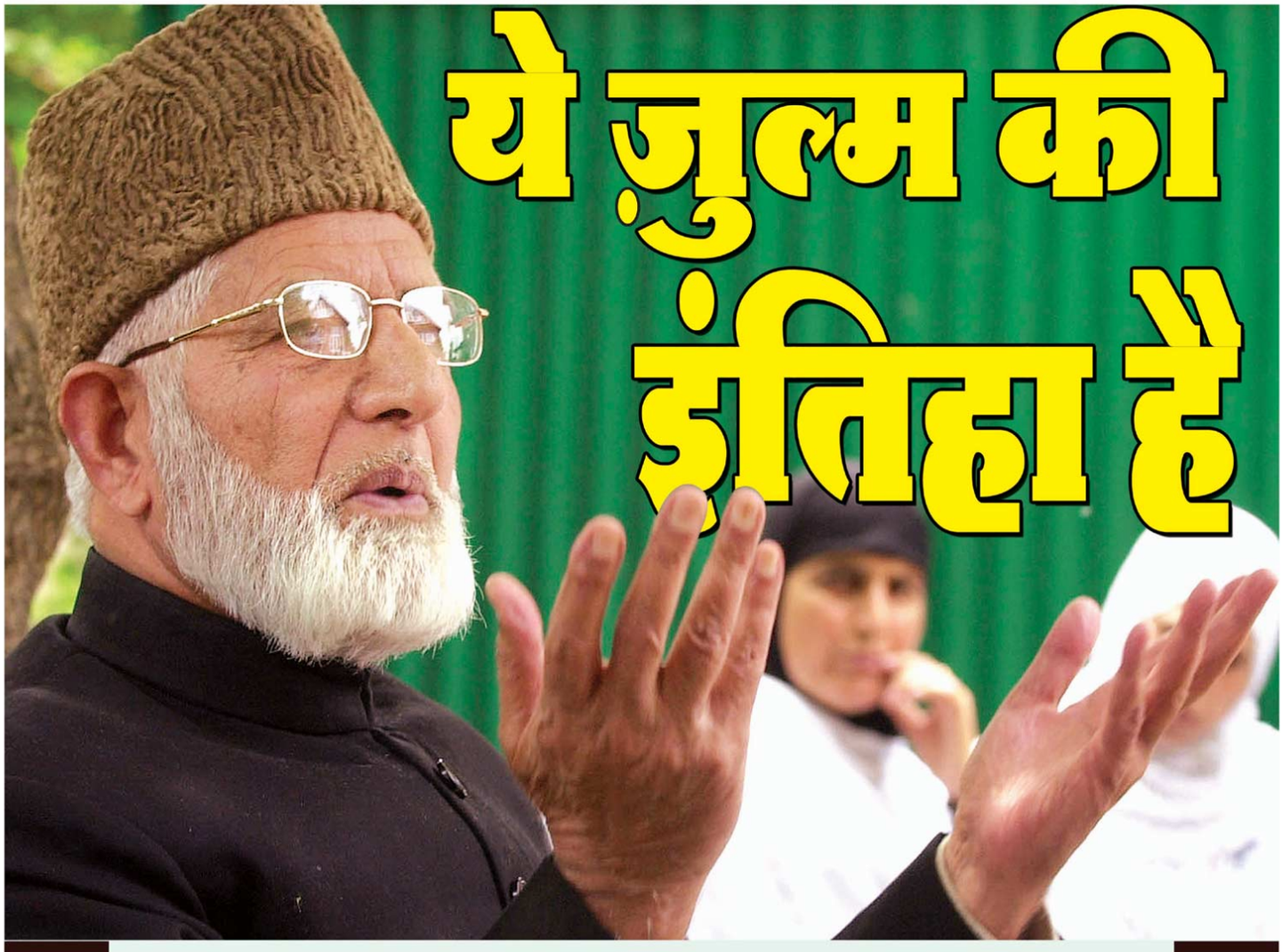

ये ज़ुल्म की इंतिहा है

दिल्ली से तीन वरिष्ठ पत्रकारों का दल कश्मीर की हक़ीक़त समझने और उसे देश के सामने लाने के लिए मध्य सितंबर में कश्मीर दौरे पर गया था. इस दल की अगुवाई चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय कर रहे थे और उनके साथ राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे और स्तम्भकार अशोक वानखेड़े थे. इस दल ने तहरीक़-ए-हुर्रियत के नेता सैयद अली शाह गिलानी से मिलने की कोशिश की. लेकिन पुलिस ने इस दल को इसकी अनुमति नहीं दी, जबकि ख़ुद गिलानी ने इस दल को अपने घर पर बातचीत के लिए निमंत्रित किया था. बहरहाल, इस दल ने उनसे कश्मीर यात्रा के दौरान ही फोन पर बातचीत की, जिसे यहां हू-ब-हू प्रकाशित किया जा रहा है.

संतोष भारतीय : जी, आदाब.

सैयद अली शाह गिलानी : आदाब, क्या आप ठीक हो?

संतोष भारतीय : जी, दुआ है सब. हमलोग कश्मीर के हालात को जानने और समझने के लिए यहां आए हैं. हमलोग आपसे बात करना चाहते थे. ये जानना चाहते हैं कि इतने बुरे हालात के बाद भी इतनी असंवेदनशीलता क्यों पैदा हो रही है? आपके पास हम कल आए थे, लेकिन पुलिस ने आने ही नहीं दिया.

सैयद अली शाह गिलानी : पुलिस ने आप लोगों को रोका. हमने आपके बयान देखे और आपके आर्टिकल्स पढ़े, जो बहुत ही रियलिस्टिक हैं. इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं.

संतोष भारतीय : कश्मीर के बारे में बताएं कि यहां क्या हो सकता है? मुल्क के सारे लोग क्या कर सकते हैं? दिल्ली से आए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से क्यों नहीं मिले आप? क्यों गुस्सा हो गए थे आप?

सैयद अली शाह गिलानी : कश्मीर के हल की जो पॉलिसी है, वो हिंदुस्तान के हाथ में है. जबतक वो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तबतक यहां सूरते हाल बिगड़ी रहेगी, जो आज आप यहां देख रहे हैं. ये आज की बात नहीं है. 1947 से कश्मीर में यही हो रहा है, यही सिलसिला चल रहा है. 1947 से यहां कत्ल हो रहे हैं, खून बहाया जा रहा है. मकान जलाए जा रहे हैं, अस्मत लूटी जा रही है. ये सब पिछले 70 साल से जारी है. हिंदुस्तान ने जम्मू-कश्मीर के साथ अपने वादे को कभी पूरा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो केवल ताक़त की बुनियाद पर यहां अपना राज क़ायम करना चाह रहे हैं. उनकी यहां के लोगों के साथ कोई हमदर्दी और मोहब्बत नहीं है, वो सिर्फ यहां की ज़मीन चाहते हैं और यहां जो कुदरती संसाधन हैं, उस पर अधिकार चाहते हैं, उसे लूटना चाहते हैं. इसके अलावा, उनका कोई मक़सद नहीं है. ऐसी हालत में कश्मीर भारत की एक कॉलोनी बन कर रह गई है. पूरे मुल्क में करीब 30 रियासतें हैं, लेकिन कोई ऐसी रियासत नहीं है, जहां आर्मी का इतना बड़ा ज़मावड़ा हो. ये सिर्फ हमारे कश्मीर में है. यहां लाखों सैनिक हैं और रोज इसमें इज़ाफ़ा हो रहा है. ऐसी हालत में लोग कैसे जीएंगे? हर जगह सेना लगा दिया गया है. सेना की छावनियों के साथ इंसान कैसे रह सकते हैं? हर दिन जुल्म होता है. इज्ज़तें लूटी जाती हैं. आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहां लोगों पर रोज गोलियां चलाई जा रही हैं. 11 हज़ार से ज्यादा लोग घायल हैं और इसमें रोज़ाना इज़ाफ़ा ही हो रहा है. इसमें कहीं कोई कमी होती नज़र नहीं आ रही है. आज के दिन ही देखिए, आज ईद है. आज के दिन कर्फ्यू है. ईद के दिन भी ये हाल रहा, तो आम दिनों में क्या हाल होगा, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है. ऐसे में, हिंदुस्तान ताक़त के नशे में है, उसी ताक़त की बुनियाद पर हमारे श्रीनगर पर जुल्म कर रहा है. हमारे पास कुछ नहीं है. न डंडा हमारे पास है, न गोलियां हैं, न बंदूक़ है और न ही पैलेट गन हमारे पास है. हमारे पास न कोई ऐसा हथियार है, जिससे हम उन पर हमला कर सकें, नुक़सान पहुंचा सकें. हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, जिससे हम उनका मुक़ाबला कर सकें या उन्हें मार सकें. लोगों को रोका जा रहा है आगे बढ़ने से, उस वक्त ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए पत्थर उठाते हैं, वरना हमारे पास कोई हथियार नहीं है. हिंदुस्तान जो है, वो पूरे जंगी हथियारों के साथ हमारे जवानों पर यलगार कर रहा है. अब इसका क्या किया जाए? हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है. सिर्फ हिंदुस्तान के हाथ में है. अब आप लोग यहां आए, यहां के हालात को ख़ुद अपनी आंखों से देखा और इसे आपने हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचाया, इसके लिए हम आपका एहसान मानते हैं. इसके लिए हम दिल की गहराइयों से आपलोगों का शुक्रिया अदा करते हैं. हिंदुस्तान का मीडिया यहां की तस्वीर को काट-छांट कर पेश कर रहा है. वो असली तस्वीर लोगों तक नहीं पहुंचा रहा है. आपलोग यहां आए, ख़ुद देखा कि क्या सूरते हाल है और फिर ज़िम्मेदारी के साथ इसे लोगों तक पहुंचाया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं.

सेना की छावनियों के साथ इंसान कैसे रह सकते हैं? हर दिन जुल्म होता है. इज्ज़तें लूटी जाती हैं. आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहां लोगों पर रोज गोलियां चलाई जा रही हैं. 11 हज़ार से ज्यादा लोग घायल हैं और इसमें रोज़ाना इज़ाफ़ा ही हो रहा है. इसमें कहीं कोई कमी होती नज़र नहीं आ रही है.

संतोष भारतीय : ये हमारा एहसान नहीं, फर्ज है. मैं यह पूछना चाहता हूं कि भारत के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनमें से किसी पर भी आपको भरोसा है कि वे आपलोगों के लिए कुछ सोचता हो या भरोसा बिल्कुल ख़त्म हो गया है?

सैयद अली शाह गिलानी : इसलिए कि जो भी लोग यहां आते हैं, जो भी यहां सूरते हाल पर दुख का इज़हार करते हैं, वो सबसे पहले ये कहते हैं कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है. ये लोग हक़ीक़त को नहीं देखते और समझते. वे हक़ीक़त पसंद रवैया अख्तियार नहीं करते. ओवैसी साहब बहुत तेज तर्रार बोलते हैं. उन्होंने भी कहा कि हां जम्मू कश्मीर में ज्यादतियां हो रही हैं, लेकिन (शेष पृष्ठ 2 पर)

कश्मीर का हल कश्मीर में है, दिल्ली या इस्लामाबाद में नहीं | P-3

जम्मू कश्मीर विधानसभा के सभी बिल दिल्ली से बनकर आते हैं | P-6

पुनर्विचार की ज़रूरत है | P-7

ये ज़ुल्म की इंतिहा है

पृष्ठ 1 का शेष

जम्मू–कश्मीर, हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट (अभिन्न हिस्सा) है. इसलिए जो भी लोग यहां आते हैं, हमारे साथ हमदर्दी का इज़हार करते हैं, लेकिन साथ ही कहते हैं कि हिंदुस्तान का यहां जो क़रज़ा है, उससे कंप्रोमाइज (समझौता) नहीं किया जा सकता है. ऐसे हाल में, हमारे दुख–दर्द का, उसका सहना, उसका बर्दाश्त करना और हमारा जो असल मसला है, उस पर तवज्जो देने वाला अभी तक हिंदुस्तान में हमारे ध्यान में नहीं आया है. हां, एक ख़ातून हैं, अरुंधति राय और दूसरे हैं गौतम नवलखा वगैरह, यही दोनों हैं, जो यहां के लोगों के जो जज्बात हैं, जो डिमांड हैं, 1947 से लेकर आज तक यहां के 6 लाख से ज्यादा लोगों ने जो क़ुर्बानियां दी हैं, अस्मतें लूटती रही हैं, इसका उनको एहसास है. उनको एहसास है कि जम्मू–कश्मीर के लोगों को अपना हक़ दिया जाना चाहिए, ताकि वो अपने मुस्तक़बिल (भविष्य) का फ़ैसला कर सकें. हमने ये भी कहा है कि हिंदुस्तान रेफरेंडम कराए और अगर लोग हिंदुस्तान के हक में फ़ैसला करेंगे, तो हम उसका भी एहतराम करेंगे. तब हम हिंदुस्तान को तस्लीम करेंगे. हमें किसी दूसरे मुल्क में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है. किसी दूसरे मुल्क से हमें कोई मुहब्बत नहीं है. हमें दुनिया के सारे इंसानों का इंसानी रिश्ते का एहतराम है. चाहे उसका रंग क्या हो, उसकी ज़ुबान क्या हो, उसका मज़हब क्या हो, उसका पेशा क्या हो, इन सारी चीजों से ऊपर उठकर हम इंसानों का एहतराम करते हैं और हर इंसान के लिए हमारे दिलों में बहुत मोहब्बत है. लेकिन हिंदुस्तान हमारे जज्बातों की कद्र नहीं करता है. ये आज की बात नहीं है. 1947 से लेकर आज तक. 1947 में जब पाकिस्तान बना, तो जो दूरदराजों में मुसलमान रहते थे, उनको कहा गया कि आप जम्मू आएं और हम आपको पाकिस्तान भेज देंगे. तो वहां 6 लाख मुसलमान जमा हो गए, जिनमें 5 लाख मुसलमानों को जिनमें औरतें भी थीं, बच्चे भी थे, ख़ूबसूरत लड़कियां भी थीं, उनको अगवा किया गया और उन्हें शहीद कर दिया गया. और गुज़िश्ता बरसों में एक लाख मुसलमान शहीद हो गए हैं. 6 हज़ार से ज्यादा ख़वातीनों की अस्मत लूटी गई है. 7600 ऐसी क़ब्रें हैं, जिनके बारे में पता ही नहीं है कि किन्हें दफनाया गया है. हज़ारों की तादाद में यहां के मकानात जलाए गए या ब्लास्ट किए गए. आज भी हज़ारों की तादाद में हमारे लोग जेलों में हैं. हमारी पार्टी तहरीक–ए–हुर्रियत के एक नेता हैं, डॉ. गुलाम मोहम्मद बख्श साहब, छह साल गुजार चुके हैं तिहाड़ जेल में. इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम यह है कि आपके पास पाकिस्तान से पैसे आते हैं. हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा वकील है, राम जेठमलानी साहब उनके केस की पैरवी करते हैं. उनका कहना है कि यह बिल्कुल बेबुनियाद केस है. छह साल कैसे गुजरे? उनके केस के लिए 125 गवाह खड़े कर दिए गए. 125 में से अबतक सिर्फ 25 ने ही गवाही दी है. यानी

उन्हें 15–20 साल जेल में ही सड़ाएंगे और बाद में कहेंगे कि उनका कोई क़सूर नहीं है. यही सूरते हाल है. इसी तरह 18 साल के बाद एक शख्स को रिहा किया गया. यहां लाल बाजार में दो युवाओं को 14 साल के बाद रिहा किया गया. इतने सालों बाद ये कह कर कि आपका कोई क़सूर नहीं है. आप अंदाज़ा कीजिए ये ज़ुल्म की इंतिहा है. इस तरह का ज़ुल्म और जब्र कहीं नहीं हो रहा है, जैसा हिंदुस्तान की तरफ से यहां के लोगों पर किया जा रहा है.

अभय दुबे : गिलानी साहब, अभी आपने कहा कि हिंदुस्तान के किसी पॉलिटिकल लीडर पर आपको भरोसा नहीं है. आपके जेहन में ऐसा कोई नाम नहीं आ रहा है, जो कश्मीर की समस्या को हल करने के लिए आगे बढ़ेगा. तो मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक नेता इस क़ाबिल नहीं रह गए हैं, तो सिविल सोसायटी के लोगों के जरिए ही कोई पहल क्यों नहीं की जा सकती है? अभी आपने जैसे गौतम नीलखा का नाम लिया. और भी सिविल सोसायटी में बहुत से लोग हैं, जो कश्मीर के मसले पर कोई स्वतंत्र पहल शुरू कर सकते हैं.

सैयद अली शाह गिलानी : तो लेते क्यों नहीं हैं? आप फरमाते हैं, पहल ले सकते हैं, लेकिन वो पहल करते क्यों नहीं हैं.

हमने कहा और लिखा भी है कि जंग के बाद भी मसाइल बातचीत से ही हल होते हैं, लेकिन जब हकीकत को माना जाए. हिंदुस्तान इस बात को तस्लीम करे कि जम्मू–कश्मीर इज ए डिसप्यूटेड टेरीटरी और फिर इस मसले का हल चाहे, तब हम बातचीत करेंगे. हम बातचीत के लिए तैयार हैं.

अभय दुबे : अगर आपलोगों की तरफ से कोई प्रस्ताव जाए तो...

सैयद अली शाह गिलानी : हमारी जो बुनियादी मांग है, वो राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन है, जिसका नेहरू ने सबसे पहले वादा किया था. यहां श्रीनगर आकर उन्होंने ये वादा किया था कि वो अपनी फौज वापस बुलाएंगे और यहां के लोगों को अपनी मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने का मौक़ा देंगे. अगस्त 1952, संसद में जाकर आप देख भी सकते हैं रिकॉर्ड को. उन्होंने कहा है कि हमने जम्मू–कश्मीर के लोगों से वादा किया है, पाकिस्तान के लोगों के साथ भी ये वादा है और आलमी बिरादरी के साथ भी है. फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं जबरी शादियों का खवादार नहीं. ये रिकॉर्ड है. और फिर 1948 में ये मामला हिंदुस्तान संयुक्त राष्ट्र में लेकर गया था कि जम्मू–कश्मीर हमारा हिस्सा है, वहां क़बायली वगैरह आ रहे हैं. उन्हें वहां से हटाया जाए और हमें जम्मू–कश्मीर पर नियंत्रण करने का मौक़ा दिया जाए. लेकिन वहां हिंदुस्तान की बातों को तस्लीम नहीं किया गया. वहां पाकिस्तान की बातों को भी देखा गया और फिर कहा गया कि जम्मू–कश्मीर एक डिसप्यूटेड टेरीटरी है और जम्मू–कश्मीर के लोगों को राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन का हक़ दिया जाए. इसके बाद से 18 क़रारदाद को पास किया गया है और जिस पर हिंदुस्तान ने दस्तख़त किए हैं. हमारा यही कहना है कि भाई आपलोगों ने 18 क़रारदाद पर दस्तख़त किए हैं, आप उन पर अमल क्यों नहीं करते हैं? आप जैसा कह रहे हैं कि कोई ऐसा लीडर है, जो हमारे दर्द को समझता है और हमारे साथ हमदर्दी रखता है, लेकिन अबतक तो कोई सामने नहीं आया है.

अशोक वानखेड़े : कोई भी मसला हो, तो उसका हल कहीं न कहीं बातचीत से शुरू होती है. अगर बातचीत नहीं होगी, तो मामले में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है?

सैयद अली शाह गिलानी : मैं यह कहना चाहूंगा कि 150 बार से ज्यादा बातचीत हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, दिल्ली और श्रीनगर के बीच. फिर क्यों कोई नतीजा सामने नहीं आया आजतक? इसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान कहता है कि बातचीत करेंगे, लेकिन कहता है कि जम्मू–कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. अब उसके बाद मसले–कश्मीर पर बातचीत की क्या सूरत बनेगी? हमने कहा और लिखा भी है कि जंग के बाद भी मसाइल बातचीत से ही हल होते हैं, लेकिन जब हक़ीक़त को माना जाए. हिंदुस्तान इस बात को तस्लीम करे कि जम्मू–कश्मीर इज ए डिसप्यूटेड टेरीटरी और फिर इस मसले का हल चाहे, तब हम बातचीत करेंगे. हम बातचीत के लिए तैयार हैं.

संतोष भारतीय : आपने हमसे बातचीत की. हम लोग यहां से जाकर इस पूरी बातचीत को देश के सामने रखेंगे.

सैयद अली शाह गिलानी : हमें बहुत ख़ुशी होगी कि अगर आपसे मिलने का मौक़ा मिले और आपलोगों को मुझसे मिलने की इजाजत दी जाए और आप हमसे मिलें. यहां की जो हालत है, उसे आप लोग ख़ुद जांच कर हक़ीक़त पसंद लोगों तक पहुंचाएंगे तो ये आपका जम्मू–कश्मीर के मज़लूम लोगों के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा.

संतोष भारतीय : बहुत–बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए.

सैयद अली शाह गिलानी : शुक्रिया. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 08 अंक 31
03 अक्टूबर– 09 अक्टूबर 2016

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)

सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060, +91–8451050786, +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

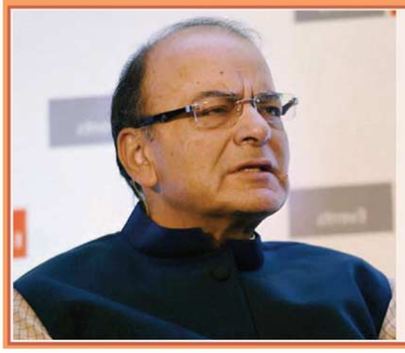

जीएसटी परिषद में कौन जाएगा

भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के बाबू नए नवेले वस्तु एवं सेवा कर परिषद सचिवालय में महत्वपूर्ण पदों पर जाने वाले हैं. ये बाबू और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधिकारी आईएएस अधिकारियों की तुलना में जीएसटी लागू करने में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे. ये आश्वासन आईआरएस अधिकारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दिया गया है. जीएसटी के लिए सामान्य उत्साह दिखाई देने के बावजूद, आईआरएस एसोसिएशन ने पहले जीएसटी परिषद सचिवालय के गठन का विरोध किया था, क्योंकि इसमें रिक्तियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा भरा जाना था. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 सितंबर को जीएसटी परिषद के पदेन सचिव के तौर पर सचिव (राजस्व) को नामित किया था और सीबीईसी के चेयरमैन को स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया था. राजस्व सचिव आमतौर पर एक आईएएस अधिकारी होता है. मंत्रिमंडल ने सचिवालय के लिए एक अतिरिक्त सचिव और चार आयुक्त के पद सृजन को मंजूरी दी थी. काउंसिल टैक्स की दर, जीएसटी में छूट दी गई वस्तुओं पर फैसला करेगा. एसोसिएशन ने मांग की थी कि परिषद सचिव सीबीईसी में सदस्य (जीएसटी) हो. हालांकि मंत्री ने यह नहीं कहा है कि कैसे सरकार ने इस मांग को समायोजित करेगी, फिर भी प्रतिनिधिमंडल उनके जवाब से संतुष्ट नजर आया. लेकिन नियुक्ति, प्रोन्नति और कुछ नई घोषणाओं के नए दौर का इंतजार अभी भी है. ■

सबसे बड़ा फेरबदल

हरियाणा में भाजपा सरकार ने इस साल राज्य में जातिगत दंगों के बाद प्रकाश सिंह समिति की कई सिफारिशों को शायद नजर अंदाज कर दिया है. इसकी जगह सरकार ने अपनी ही पार्टी के लोगों, मंत्रियों, विधायकों और सलाहकारों की राय को गंभीरता से लिया है. शायद अपने कार्यकाल के सबसे बड़े फेबदल के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 26 अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया है. इस फेरबदल में मुख्य विभागों के बॉस जैसे बिजली, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, स्वास्थ्य, वित्त, आबकारी एवं कराधान, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और श्रम सहित कई विभाग शामिल है. सूत्रों का कहना है कि फेरबदल की अफवाहें तब उड़ी, जब सरकार ने विधायकों और सलाहकारों के साथ बातचीत कर के फीडबैक लेना शुरू किया. प्रभावित बाबुओं में अतिरिक्त सचिव, पावर, आर के गुप्ता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक्साइज, अनुराग रस्तोगी, खाद्य एवं आपूर्ति के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्याम सुंदर प्रसाद और वित्त के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल शामिल है. दिलचस्प बात यह है कि राज्य सरकार ने कम से कम दो साल के कार्यकाल पूरा होने से पहले कई अधिकारियों को स्थानांतरित कर न्यूनतम कार्यकाल नीति की अनदेखी की है. उदाहरण के लिए स्वास्थ्य में पिछले दो साल में चार अतिरिक्त मुख्य सचिव थे. इस बीच यह पता नहीं चला है कि क्या सरकार जातिगत दंगों के दौरान कर्तव्य की उपेक्षा के लिए प्रकाश सिंह पैनल द्वारा दोषी पाए गए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी या नहीं. ■

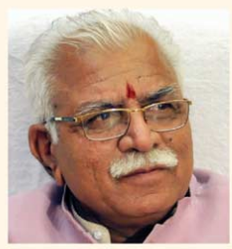

नया सेबी चेयरमैन कौन

सरकार ने सेबी के चेयरमैन यू के सिन्हा के उत्तराधिकारी की खोज शुरू कर दी है, जिनका कार्यकाल अगले साल फरवरी में खत्म हो जाएगा. सिन्हा सेबी प्रमुख के रूप में सबसे लंबे समय तक काम करने वाले चेयरमैन रहे. 2011 में उन्हें तीन साल के लिए नियुक्त किया गया था. बाद में उन्हें दो साल का विस्तार और फिर एक साल का विस्तार पिछली फरवरी में दी गई थी, क्योंकि सरकार किसी नाम को अंतिम रूप नहीं दे सकी थी. सूत्रों का कहना है कि 1976 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी के उत्तराधिकारी का चयन फिनांसियल सेक्टर रेगुलेटरी अप्वायंटमेंट सर्च कमेटी के मुखिया कबिनेट सचिव पीके सिन्हा की सिफारिश पर की जाएगी. हालांकि सरकार ने इस पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, फिर भी सर्च पैनल किसी अन्य व्यक्ति का नाम भी आगे कर सकती है, यदि वो मानती है कि उक्त व्यक्ति इस पद के लिए योग्य है. पिछले बार, वायदा बाजार आयोग के चेयरमैन रमेश अभिषेक, भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य और राष्ट्रपति भवन में अतिरिक्त सचिव थॉमस मैथ्यू सेबी चेयरमैन के पद की रेस में सबसे आगे थे.■

कश्मीर का हल कश्मीर में है दिल्ली या इस्लामाबाद में नहीं

कश्मीर में समस्या का हल कश्मीर में है, दिल्ली या इस्लामाबाद में नही. लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, गाड़ी को स्टार्ट करने वाले दिल्ली और इस्लामाबाद वाले हैं. रास्ता कहां जाना है, ये मैं (कश्मीर) बताता हूं. लेकिन आप गाड़ी तो स्टार्ट करें न. आप गाड़ी को स्टार्ट ही नहीं करना चाहते हैं. मुझसे कहते हैं, कहां जाना है. मेरी राय में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत आवश्यक है और शायद बातचीत में ही मसले के हल की चाबी है. अगर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हो जाती है, तो जैसा कि मेरा मानना है कि सभी दरवाज़े खुल जाएंगे. संचार के रास्ते, सहमति के रास्ते, अच्छाई के रास्ते हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेंगे. हमारी एक ही समस्या नहीं है. हमारी भारत और पाकिस्तान की सरकारों के साथ कई समस्याएं हैं, जिनका हल निकालना होगा. बुद्धि से निकालना है. आप बुद्धि को अगर छुट्टी दे देंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा.

प्रोफेसर अब्दुल ग़नी बट
(लेखक हुर्रियत के वरिष्ठ नेता हैं)

एक परिप्रेक्ष्य (पर्सपेक्टिव) में अपनी बात रखूंगा. जब एक परिप्रेक्ष्य में बात होती है तो उसमें आपको राजनीति के साथ-साथ इतिहास का भी ध्यान रखना पड़ता है. राजनीति और इतिहास के साथ-साथ मनोविज्ञान का भी ख्याल रखना पड़ता है. कश्मीर का जो विवाद है, इसके तीनों पहलू हैं. इसमें इतिहास, राजनीति और सबसे बड़ी बात ये कि मनोविज्ञान का भी एक पहलू है. कश्मीर की एक सामूहिक मनोवैज्ञानिक पहचान है. राजनीति और इतिहास दोनों के संदर्भ में कश्मीर के इस सामूहिक मनोवैज्ञानिक पहचान को समझना होगा.

मैं आपको एक बात बताऊं. वह इसलिए नहीं कि मैं कोई भाषण देना चाहूंगा, बल्कि इसलिए कि बात को समझा जाए. आगे बढ़ना है और जब आगे बढ़ना होता है, तो बात को समझना पड़ता है. जब आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो बात को आप समझें या न समझें, कुछ भी नहीं होगा. लेकिन जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे, बात को समझना चाहेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं और अपनी मंजिल पा सकते हैं. मैं उसी इरादे से, उसी नीयत से, उसी सोच से आगे बढ़ने के लिए आपसे बात कर रहा हूं. जब आप (यानी भारत) आए, कश्मीर आए, आप घनगरज के साथ आए. जब आप कश्मीर आए तो बंदूकों के धमाकों और लोकतंत्र के शोरगुल के साथ आए. इसका असर यहां की सामूहिक चेतना (कलेक्टिव कॉन्शसनेस) पर पड़ा. सबने इसे देखा. सबने इसे पाया. सबने इसे सहा. अभी मैं एक कड़वी सी बात कर रहा हूं, लेकिन ये कड़वी बात आपको सुननी पड़ेगी. क्योंकि मेरा ख्याल है कि आप भारत की सोच का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. आप हिंदुस्तान की सोच को कुछ बतलाना चाहते हैं, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी. आपको पता है कि हिंदुस्तान बंदूक की घनगरज के साथ कश्मीर में दाखिल हुआ. जम्हूरियत की शोर के साथ आपने नारे लगाएं, आपने वादे किए, लोकतांत्रिक वादे किए कि हम इस घनगरज के खात्मे के बाद आपसे पूछेंगे, आप क्या चाहते हैं? कहां जाना चाहते हैं? हमारे साथ रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान जाना चाहते हैं? ये न सिर्फ उस वक्त हुआ, जब कश्मीर को आपके नाम वक्फ किया गया, यानी जब महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र (इन्स्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन) पर हस्ताक्षर किया. उस वक्त भारत के गवर्नर ने महाराजा हरि सिंह को एक पत्र लिखा कि जैसे ही हालात सामान्य हो जाएंगे, हम इस मसले को लेकर जनता के पास जाएंगे. हम जनता की राजनीतिक इच्छाओं को बहाल करेंगे, चाहे वो हमारे साथ रहना चाहते हों या नहीं. हम ऐसा करेंगे. इसी को मैं लोकतंत्र का शोर कहता हूं. अब देखें कि कितना ज़बरदस्त विरोधाभास है. जब आप इन विरोधाभासों के साथ ऐसी हालत में पहुंचते हैं, आप कहते हैं, जो होना था हो गया, तो इसका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि कश्मीर की जो सामूहिक आत्मा है, वो आत्मा जख्मी हो गई है. मेरे विचार से उसे बड़ा गहरा जख्म लगा है. उस सामूहिक आत्मा को आपको समझना पड़ेगा. हमारे पूर्वज हिन्दू थे. उन्होंने एक संवाद के दौरान इस्लाम को चुना इसलिए मैं एक धर्मांध नहीं हो सकता. ये धर्म परिवर्तन एक बौद्धिक स्तर के संवाद के दौरान हुआ. और इसके मायने ये हुए कि बिल्कुल खुशी-खुशी सब कुछ हो रहा था. कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं. उसमें हमारी माएं, बहनें और बेटियां शामिल नहीं थीं. मगर जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि कश्मीर का जो इतिहास है, वो भाईचारे का इतिहास है. उसके जो गुण हैं, उसमें एकता है, विरोधाभासों के साथ एकता, अलग-अलग धार्मिक मान्यताओं के साथ एकता. इसे हम धार्मिक मानवतावाद कहते हैं. हम धार्मिक मानवतावाद के पथ प्रदर्शक थे, लेकिन हमारी बदनसीबी यह कि हमारी आत्मा को एक और गहरा जख्म लग गया. भारत और पाकिस्तान दोनों कश्मीर मामले में उलझ गए. अब जाहिर है कि मैं (यानी कश्मीर) छोटा, हिंदुस्तान बड़ा. पाकिस्तान के मुकाबले मैं (यानी कश्मीर) छोटा, पाकिस्तान बड़ा. अब तो स्थिति ही पूरी तरह से बदल गई है. भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति बन गए हैं. अब तो जम्मू और कश्मीर राज्य में दो परमाणु शक्ति संपन्न देश उलझ गए. अब तो मेरा (कश्मीर का) हुलिया ही बिगड़ सकता है. अब तो मेरी (कश्मीर की) नस्ल ही खत्म हो सकती है. अब तो शायद कश्मीर की वजह से पूरा दक्षिण एशिया क्षेत्र ही भस्म हो सकता है. अब तो मैंने (कश्मीर समस्या) एक बड़ा आयाम ले लिया है. भारत और पाकिस्तान जब अपने उपमहाद्वीपीय विडंबनाओं को लेकर कश्मीर में उलझ गए तो यहां की सामूहिक आत्मा को एक और जख्म लगा. एक तीसरा ज़ख्म भी लगा. वो ज़ख्म ये था कि जवाहरलाल नेहरू, जो एक महान लोकतांत्रिक व्यक्ति थे, इतने उदारवादी थे कि हिंदू धार्मिक नेता उन्हें हिंदू ही नहीं समझते थे. उन्होंने कहा था कि अगर जम्मू-कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इसे लेकर मुझे दुख जरूर होगा, लेकिन मैं इस फैसले को स्वीकार करूंगा. यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय और जम्मू-कश्मीर की जनता से मेरा वादा है. ये 1950 के दशक की बातें हैं. फिर 1954 में जवाहरलाल नेहरू सरकार में गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने एक बयान दिया. उस बयान का ये मतलब था कि हिंदुस्तान अब इस मसले को लेकर संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद में जाने के वादे से मुकर रहा है. सुरक्षा परिषद ने इस झगड़े को कायम रखने के लिए प्रस्ताव (रिजॉल्यूशन्स) पेश किये हैं. उन्होंने इसको खत्म करने के लिए प्रस्ताव नहीं बनाए. इसलिए बनाए कि इनमें झगड़ा बना रहे और ये लोग आपस में लड़ते रहें क्योंकि ये तो हमारे गुलाम थे, हम इनके बादशाह थे. अब हमको निकलना पड़ा. इनको आराम से नहीं बैठने देना, तो कुछ ऐसा हुआ कि ऐसे प्रस्ताव आ गए कि उनपर अमल भी नहीं हुआ और यहां की स्थिति बदलती रही. अमेरिका और पाकिस्तान में रक्षा समझौता हो गया. इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब जनमत संग्रह नहीं होगा. लिहाज़ा, अंदर ही अंदर यहां की रूह एक और ज़ख्म खा गई. यह जख्मी रूह है, जो आपसे बात कर रही है. आपने जब इलाज ढूंढा, वो मेरे पेट का इलाज ढूंढा. आपने जब इलाज ढूंढा वो मेरी जेब का इलाज ढूंढा. मेरी जेब में आपने रुपया-पैसा डाला, मेरे पेट में आपने चावल डाला, गेहूं डाला, लेकिन मेरी जो जख्मी आत्मा थी, उसकी तरफ आपने कभी ध्यान नहीं दिया. नतीजा ये हुआ कि कश्मीरी, जो धार्मिक मानवतावाद का प्रचारक था, उसने बंदूक उठा लिया.

अगर कश्मीर की समस्या को समझना है तो ऐसे समझना चाहिए कि आप मेरे भौतिक आयाम का हल निकाल रहे हैं, मेरा जो आध्यात्मिक आयाम है उसे आप देखना ही नहीं चाहते हैं. इससे कुछ नहीं होगा. मेरी जिंदगी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तत्वों का मिश्रण है.

तो अब स्थिति को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं. राजनीतिक और ऐतिहासिक तौर पर कश्मीर मसला विभाजन के भंवर जाल से पैदा हुआ. उस इतिहास को दोहराने से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन बात को समझना पड़ेगा. इनमें दो-तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं. पहला, भारत और पाकिस्तान के बीच शक्ति संतुलन बहाल हो गया है. भारत जितना शक्तिशाली है, पाकिस्तान भी उतना ही शक्तिशाली है. यह संख्या या आकार की वजह से नहीं, बल्कि परमाणु शक्ति की वजह से है. मेरी जो समझ है, उसके मुताबिक मैं कह सकता हूं कि भारत और पाकिस्तान कभी जंग नहीं लड़ सकते. लेकिन जो बात मुझे परेशान करती है, वह यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों लगातार युद्ध की हालत में हैं. यानी जब आप युद्ध की हालत में हों, तब आप युद्ध नहीं करते हैं, लेकिन आप युद्ध की स्थिति में उलझे रहते हैं. तब आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपकी आत्मा में, गलियों में, सरकारी कार्यालयों में, सीमा रेखा पर और सब जगह युद्ध जैसी स्थिति चल रही होती है. और मेरे ख्याल में युद्ध की स्थिति परमाणु युद्ध से ज्यादा खतरनाक होती है. इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा. दूसरा, कश्मीर उबाल पर है और इस उबाल में शायद मैं आपको दिखाई ना दूं. मेरा बेटा दिखाई देगा, मेरे बेटे का बेटा दिखाई देगा, शायद उसका बेटा भी दिखाई देगा. मैंने एक बच्चे को देखा है. शायद आपने भी देखा हो, वो छह साल का है. वह गुलेल हाथ में लिए हुए है. वहां कोई फौज नहीं है, कोई सीआरपीएफ नहीं है, कोई कश्मीर पुलिस नहीं है. कुछ नहीं है. लेकिन वो एक बंद दुकान के बाहर बैठा है. मैं उसके अंदाज को देख रहा था, उसके स्टाइल पर गौर कर रहा था और उसकी छोटी सी, मासूम सोच को भी परख रहा था. तभी मैंने ये सोचा कि ये झगड़ा अब उम्र के लिहाज से 80 साल और बढ़ गया है. यह बच्चा तो अभी छह साल का है. अगर उसकी नब्बे साल उम्र रखी जाए, तो कब तक चलेगा ये झगड़ा? अब आप इसे यूं समझें कि छोटे लड़के व नौजवान पंद्रह साल, सोलह साल, अठारह साल, बीस साल के मैदान में हैं. इससे इस झगड़े की उम्र 80 साल और बढ़ गई है. जब ये नौजवान आते हैं न मैदान में तो ये तर्क की बुनियाद पर नहीं आते हैं, बल्कि ये भावनाओं की बुनियाद पर आते हैं. भावनाएं आपको कभी-कभी पागलपन की सीमा तक पहुंचा देती हैं. इसमें कभी-कभी कुछ खराबियां भी हो जाती हैं और उन खराबियों के नतीजे में जो भागीदारी होती है, वो बहुत गहरी होती है. एक और दाग, एक और घाव, एक और जख्म. पैलेट गन से आपने मेरे बेटे की आंख की रोशनी छीन ली. दूसरा कहता है कि उसने ये रोशनी खोई, आपका भविष्य बेहतर बनाने के लिए. मैंने ये सर कटते देखा, जो आपका सर बुलंद देखने के लिए कटा. ये सबक़ पढ़ाया जा रहा है कश्मीर में. तो कश्मीर में जो उबाल है, इसके आयाम को भी लेना पड़ेगा. मेरा ये ख्याल है कि बहुत गहराई के साथ देखना होगा, इसमें गुस्से की कोई बात नहीं. आप गुस्सा न करें, मैं भी गुस्सा नहीं करूंगा. गुस्सा किया तो कहां जाएंगे? कोई रास्ता नहीं है. कोई मंजिल नहीं है. एक बात जरूर है कि अगर हम इसको समझ पाएं तो रास्ता दिखाई देगा. सीधा, समतल और मंजिल तक पहुंचने वाला रास्ता दिखाई देगा. अभी जो कश्मीर में हो रहा है, वह गुस्सा है. इधर से भी गुस्सा है, उधर से भी गुस्सा है. ये गुस्सा कहां ले जाएगा, इसका अंदाजा तो आप कर सकते हैं, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है. तो एक तो जंग की हालत से निकलना होगा. दूसरे, इस उबाल से निकलना होगा.

अब तीसरी बात आती है. व्यावहारिक स्तर पर जो गठजोड़ बन रहे हैं, उनको भी देखना पड़ेगा. आप चीन को जानते हैं, आप अमेरिका को जानते हैं, आप भारत को जानते हैं, आप पाकिस्तान को जानते हैं, आप ईरान को जानते हैं, आप अफगानिस्तान को जानते हैं, आप मध्य पूर्व को जानते हैं, आप मध्य एशियाई देशों को जानते हैं, आप अफ्रीका को जानते हैं. लेकिन जो गठजोड़ बन रहे हैं, एक तो ये कि वो परस्पर विरोधी हैं. तभी तो मुझे दिख रहा है कि दुनिया के दो सबसे अधिक शक्तिशाली देश चीन और अमेरिका दक्षिण एशिया के मामलों में लिप्त हैं. यह बहुत महत्वपूर्ण और खतरनाक क्षेत्र है. यहां झगड़े भी हैं. उसमें एक झगड़ा कश्मीर का भी है. अगर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है, तो हमारा काम तमाम हो जाएगा. क्योंकि चीन के अपने लक्ष्य हैं, अमेरिका के अपने लक्ष्य हैं. हमारा कोई लक्ष्य दिखाई ही नहीं देता है, बावजूद इसके कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को गाली दें. इस हालत से भी निकलना पड़ेगा. भारत को भी और पाकिस्तान को भी. किसी सूरत में भी निकलना पड़ेगा. नहीं तो मेरा ख्याल है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक संकट में घिर जाएंगे. फिर न राधा नाचेगी और न बांसुरी बजेगी. एक-दो लम्हे में हमारा काम तमाम हो चुका होगा. हमें तीन बड़ी मुसीबतों से निकलना होगा. कैसे निकलेंगे? अगर मैं ये कहूं कि लड़ाई लड़ेंगे, तो ये तो एक और मुसीबत है. हमें लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें गुस्सा छोड़ना होगा. इस से निकलने के लिए हमें सूझ-बूझ और समझदारी से काम लेना होगा. तीन चीजें मुझे दिख रही हैं. एक, यथार्थवाद, दूसरा कल्पनाशीलता, तीसरा समायोजन. इन्हीं तीन चीजों को लेकर हम इस मुसीबत से निकल सकते हैं. कैसे निकलें, शुरू कैसे करें? शुरू करने के लिए जो चीज़ बहुत जरूरी है, शायद अपरिहार्य है, वह है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सार्थक और व्यापक बातचीत. उस बातचीत का भारत और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा सकारात्मक परिणाम दिखेगा, उससे कश्मीर में एक खुशगवार तब्दीली आ जाएगी. कश्मीर के हालात में सुधार दिल्ली और इस्लामाबाद के हाथों में है, जम्मू-कश्मीर में नहीं है. दिल्ली और इस्लामाबाद को दक्षिण एशिया के वृहत हित के लिए एक दूसरे के संपर्क में रहना चाहिए. मुझे ऐसा लग रहा है कि कश्मीर अब दक्षिण एशिया के भविष्य के साथ जुड़ चुका है. इस क्षेत्र के दो शक्तिशाली देश भारत और पाकिस्तान से जुड़ चुका है. अब इनके बीच संघर्ष कितना खतरनाक हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान बातचीत शुरू करें. उसका जो खुशगवार नतीजा आएगा, वो ये कि कश्मीर में लोग समझेंगे कि अब कुछ हो रहा है. कुछ मूवमेंट हो रही है. तो ये सब ठीक हो जाएगा यहां.

भारत और पाकिस्तान दोनों कश्मीर मामले में उलझ गए. अब जाहिर है कि मैं (यानी कश्मीर) छोटा, हिंदुस्तान बड़ा. पाकिस्तान के मुकाबले मैं (यानी कश्मीर) छोटा, पाकिस्तान बड़ा. अब तो स्थिति ही पूरी तरह से बदल गई है. भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति बन गए हैं. अब तो जम्मू और कश्मीर राज्य में दो परमाणु शक्ति संपन्न देश उलझ गए. अब तो मेरा (कश्मीर का) हुलिया ही बिगड़ सकता है. अब तो मेरी (कश्मीर की) नस्ल ही ख़त्म हो सकती है. अब तो शायद कश्मीर की वजह से पूरा दक्षिण एशिया क्षेत्र ही भस्म हो सकता है.

दूसरा, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू होगी, तो हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली वालों से बात करेंगे, हम पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान वालों के साथ बातचीत करेंगे. हम दोनों की भलाई की बात करेंगे. हम भारत और पाकिस्तान दोनों जगहों के लोगों को प्यार करते हैं. इसका कोई गलता अंदाज़ा न लगाया जाए और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, जैसा मैंने कहा था कि हम धार्मिक मानवतावाद का, मेल-मिलाप का प्रतिनिधित्व करते हैं. मैं दिल्ली के लोगों से प्यार, मोहब्बत और गंभीरता से बात करता हूं. तो इन चीजों को देखना होगा. अगर मैं पाकिस्तान जाऊंगा, तो वहां भी वही करूंगा. मैं उनसे दृढ़ता व मेल-मिलाप से बात करूंगा, ताकि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आएं और दक्षिण एशिया के हालात को स्थिरता दे सकें. इसमें हमारा योगदान भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत सकारात्मक होगा. कश्मीर से संबंधित कुछ बातें आप से अभी नहीं करूंगा, जिसका मुझे अफसोस है. मुझे करना चाहिए था, लेकिन पहले इस पर मुझे थोड़ा सोचना है. हम धार्मिक मानवतावाद के पथ प्रदर्शक की अपनी भूमिका को फिर निभाएंगे. यह भारत और पाकिस्तान के साथ-साथ तमाम दक्षिण एशिया पर हमारा कर्ज़ है और शायद यह हमारे भविष्य की पीढ़ी का भी कर्ज है. हम नहीं चाहते कि हमारी अगली पीढ़ी को एक ऐसा क्षेत्र मिले जो तनावपूर्ण हो. हम आने वाली पीढ़ियों को एक समृद्ध और शांतिपूर्ण भविष्य देना चाहते हैं. हम एक ऐसी रणनीति पर काम करेंगे जिससे एक शांतिपूर्ण, समृद्ध दक्षिण एशिया का निर्माण होगा.

नेहरू द्वारा रायशुमारी के वादे से मुकरने के बारे में पूछे जाने पर प्रोफेसर बट ने कहा, मेरा ख्याल है कि इस सवाल में निहित खतरों के मद्देनजर इसमें उलझना ही नहीं चाहिए. क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा मिशन है. अगर आप अपने आपको इतिहास का कैदी बनाएंगे, तो आप उससे निकल नहीं पाइएगा. हमें अंधकार से उजाले की ओर जाना है. मैं टनेल के उस पार अपनी आंखों से रोशनी देख रहा हूं. आप इन तारीखी गुत्थियों में मत उलझिए.

कश्मीर में हालिया उबाल का हल कश्मीर में है, दिल्ली या इस्लामाबाद में नही. लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, गाड़ी को स्टार्ट करने वाले दिल्ली और इस्लामाबाद वाले हैं. रास्ता कहां जाना है, ये मैं (कश्मीर) बताता हूं. लेकिन आप गाड़ी तो स्टार्ट करें न. आप गाड़ी को स्टार्ट ही नहीं करना चाहते हैं. मुझसे कहते हैं, कहां जाना है. मेरी राय में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत आवश्यक है, और शायद बातचीत में ही मसले के हल की चाबी है. अगर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हो जाती है, तो जैसा कि मेरा मानना है कि सभी दरवाज़े खुल जाएंगे. संचार के रास्ते, सहमति के रास्ते, अच्छाई के रास्ते हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेंगे. हमारी एक ही समस्या नहीं है. हमारे भारत और पाकिस्तान की सरकारों के साथ कई समस्याएं हैं, जिनका हल निकालना होगा. बुद्धि से निकालना है. आप बुद्धि को अगर छुट्टी दे देंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा.

इन दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू नहीं होने का ज़िम्मेदार कौन है, तो मेरा जवाब होगा कि मैं कभी-कभी सूफी शायर जलालुद्दीन रूमी को पढ़ता हूं. वे कहते हैं कि एक सूफी एक ही लम्हे में महानता की गद्दी पर विराजमान हो सकता है. मुझ जैसा आदमी भूत में खो जाता है और आगे की नहीं सोचता है. वह अपना जीवन लगा देता है, लेकिन कहीं नहीं पहुंच पाता है. मेरी सलाह है कि इन सवालों को अपने दिमाग से निकाल दें, जो हुआ सो हुआ, अब आगे की सोची जाए. ये मेरा मशवरा है.■

(यह आर्टिकल श्रीनगर दौरे पर दिल्ली से गईं तीन सदस्यीय पत्रकारों की टीम के साथ प्रोफेसर अब्दुल ग़नी बट की बातचीत पर आधारित है)

जम्मू-कश्मीर को तीन हिस्सों में बांटना

आरएसएस का दीर्घकालिक एजेंडा है

तारिक़ हमीद कर्रा

आज की तारीख में कोई भी चाहे छोटा हो, बड़ा हो, लोकप्रिय हो, अलोकप्रिय हो, मेनस्ट्रीम राजनीतिज्ञ जितने भी हैं, वे सब अप्रासंगिक हो गए हैं और अनफॉरच्यूनेट पार्ट इसमें ये है कि पहले भी ऐसी स्थितियां यहां पर उभरी हैं, चाहे 2008 हो, 2010 या 2013 हो, उस समय भी थोड़े समय के लिए मेनस्ट्रीम का स्पेस कम हो जाता था, लेकिन समय के साथ वो रिवाइव भी होती थी. अलबत्ता एक फर्क होता था, इन स्थितियों में भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हमेशा रिलीवेंट रहती थी. ऐसी स्थिति में वो एक पॉजीटिव रोल अदा कर पाते थे. अनफॉरच्यूनेटली इस बार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी इररेलीवेंट हो गई, जो एक बेहतर संकेत नहीं है. हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को इस आंदोलन में एक बफर की भूमिका निभानी चाहिए. अब उसी का नतीजा है कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि आज के दौर में ये एक नेताविहीन आंदोलन है. कश्मीर मसले को हल करना हमारे हाथ में नहीं है. अलबत्ता, हम इसमें सहायता जरूर करेंगे. हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों पर एक दबाव बनाएंगे कि वे जंग की जगह इस मसले का हल बातचीत के जरिए निकालें.

श्राइन बोर्ड का जो मसला हुआ, जो इकोनॉमिक सेंक्शन्स कहिए या इकोनॉमिक ब्लॉकेड, इससे कश्मीर की साइकी को एक बार फिर धक्का लगा. हमारी लाइफलाइन बस यही एक टनल है, यही एक रास्ता है. ब्लॉकेड लगा दिया, बच्चों का दूध यहां बंद हो गया, जीवन रक्षक दवाएं यहां बंद कर दीं, हमारा राशन वगैरह जो भी कुछ है, बंद हो गया. पहले जब मिलिटेंसी शुरू हुई थी, तब अनजाने में लोग कहते थे कि रावलपिंडी चलो, ट्रेनिंग लेने के लिए. अब राजनीतिक रूप से जागरूक लोग कहते हैं मुजफ्फराबाद चलो. अगर जम्मू और दिल्ली के लोग इकोनॉमिक ब्लॉकेड करेंगे तो हमारे पास दूसरा रास्ता है, जो मुजफ्फराबाद जाता है.

भाजपा की विचारधारा के खिलाफ होने के बाद भी मुफ्ती साहब ने अलायंस कर लिया. आज का ये अनरेस्ट जो आप देख रहे हैं, उसकी बुनियाद अगर पड़ी है तो इस अलायंस की वजह से. लोगों ने इस अलायंस को कबूल नहीं किया. रिलीजियस एफिनिटी की वजह से लोगों ने इसे कबूल नहीं किया. कश्मीरियत का जो एसेंस है, वो सेक्युलर है. कश्मीरी कभी फैनेटिक नहीं रहा है. कश्मीरी कभी कम्युनल नहीं रहा है. यह वह कश्मीर है, जिसके बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि एक रे ऑफ होप है, क्योंकि जम्मू में 1947 में ढाई लाख मुसलमान मारे गए और कश्मीर में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं मरा. उसके बाद 1952 में, जब श्यामाप्रसाद मुखर्जी आए, पांच लाख मुसलमानों को पुश आउट किया गया, जिसमें करीब डेढ़-दो लाख लोग उस दिन मारे गए. अब हम आर्टिकल 370 को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, वे उसको एरोगेट करने की बात करते हैं. यहां पर लोग कहते हैं बीजेपी का एजेंडा हिंदुत्व का है. अगर मुझसे पूछा जाए, हिंदुत्व आपके जीने का एक तरीका है. जो बीजेपी और आरएसएस ने यहां पर शुरू किया है, वह हिंदुत्व नहीं है. उनका ये कहना कि ईसाइयों के इतने मुल्क हो गए, मुस्लिमों के इतने मुल्क हैं, बौद्ध के इतने मुल्क हैं, हिंदुओं का सिर्फ एक मुल्क है और उसमें भी मुसलमान रह रहे हैं और मुसलमानों की आबादी इतनी बढ़ रही है. यह खतरनाक है.

आप कश्मीरी से क्या उम्मीद करते हैं? एक तरफ से आप उसको इतना पीट रहे हैं, इतना मार रहे हैं. हर मुसलमान से आप आतंकवादी की तरह व्यवहार कर रहे हैं. पिछले दो-तीन साल में जहां-जहां कश्मीरी छात्र पढ़ते थे, उनका क्या हाल किया गया? आपका ऐसा ही व्यवहार रहा तो कश्मीर को बचाए रखना बहुत मुश्किल है. वाजपेयी जी कश्मीर के लिए बहुत सम्माननीय नेता थे. याद रखिए, तीन हमला करने के बाद भी अकबर नहीं जीत पाया कश्मीरी से. कितना दबाएंगे आप. अगर मोदी जी को ये ख्याल है कि वो क्रश कर रहे हैं कश्मीरियों को, इकोनॉमिकली सप्रेस कर रहे हैं कश्मीरियों को, तो ये उनकी गलतफहमी है. अब कश्मीरी भी सीख गया है कि इस स्थिति में कैसे जिंदा रहना है? आपके मोहल्ले में एक हफ्ता क्या, तीन दिन कर्फ्यू लग जाए, आप लोगों के फाके लगेंगे. अब कश्मीरी फाके से नहीं मरता. आपको ये मानना होगा कि कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है. जम्मू-कश्मीर के लोगों के पास दोहरी नागरिकता है. पहले कश्मीरी और तब इंडियन. हमारा एक संविधान है. कितने अन्य राज्यों के पास दो झंडे हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर के पास है.

श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने कहा था एक निशान, एक प्रधान, एक विधान. क्यों उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया. अगर जम्मू-कश्मीर विवादित नहीं है तो फिर क्यों दो संविधान, दो झंडे हैं. आप यहां जमीन नहीं खरीद सकते, क्योंकि आप यहां के स्थायी निवासी नहीं हैं. दिल्ली के लॉ मेकर्स से पूछिए कि क्यों 69 साल बाद भी ये सब जारी है? अगर बीजेपी में इतनी ताकत है तो इसे खत्म करे. संवैधानिक और कानूनी दोनों तरीकों से भारत सरकार के साथ जो संबंध है, जो लिंक है, वह आर्टिकल 370 है. जिस दिन आर्टिकल 370 समाप्त हुआ, कश्मीर उस दिन खुद ब खुद आजाद हो जाएगा. क्यों नहीं किसी एक ने भी ऐसा रास्ता निकाला कि आर्टिकल 370 आप पार्लियामेंट से समाप्त करा सके. पाकिस्तान को आप इतनी बड़ी-बड़ी धमकियां देते हैं, चीन को क्यों नहीं देते. क्योंकि चीन से डरते हैं आप? चीन के पास आपका इतना हिस्सा है, आपने आज तक कभी चीन को चैलेंज किया? हर चीज को आप पाकिस्तान के साथ जोड़ रहे हैं. ठीक है, पाकिस्तान ही कर रहा है, मान लेते हैं. तो फिर पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है या आप कंट्रोल कर रहे हैं.

आप हमेशा कश्मीर की बात करते हैं, कभी तो कश्मीरियों के बारे में भी बात करिए. कश्मीरी के बारे में बात नहीं करेंगे. फिर भी हम कहते हैं कि हम लोग बेशर्म हैं या तो बेगैरत हैं. इसके बावजूद हम इस राष्ट्रीय झंडे को उठाए हुए हैं. भारतीय लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं. अभी तक हिंदुस्तान में कितने प्रदर्शन हुए. अभी की सरकार के दौरान जाट आंदोलन हुआ. कितनी पैलेट गन चली वहां. सारी अर्थव्यवस्था को तोड़कर उन्होंने रख दिया. आपके यहां पटेल आंदोलन हुआ कितने पैलेट गन और लाशें गिरा दीं आपने वहां. अभी बेंगलुरू में देख लीजिए कोई बुलेट चला, कोई एक आदमी मारा गया. हिंदुस्तान की बाउंड्रीज पर देख लीजिए. उत्तर पूर्व, नागा, बोडो, झारखंड, मणिपुर और छत्तीसगढ़ कहां नहीं अलगाववादी हैं? जब आप उनके साथ बिना किसी शर्त के बात करते हैं, गैर मुल्कों में जाकर बात करते हैं, तो आप कश्मीरी से क्यों नहीं बात कर सकते? उनको कहते हैं कि संवैधानिक ढांचे के तहत, वो संवैधानिक ढांचे को ही चुनौती दे रहे हैं. आपके कहने का मतलब है कि तुम संवैधानिक ढांचे के तहत बात नहीं करता चाहते.

आप कश्मीरी से क्या उम्मीद करते हैं? एक तरफ से आप उसको इतना पीट रहे हैं, इतना मार रहे हैं. हर मुसलमान से आप आतंकवादी की तरह व्यवहार कर रहे हैं. पिछले दो-तीन साल में जहां-जहां कश्मीरी छात्र पढ़ते थे, उनके साथ क्या हाल किया गया? आपका ऐसा ही व्यवहार रहा तो कश्मीर को बचाए रखना बड़ा मुश्किल है.

आप कहते हैं हम तो उनको कहते हैं भारतीय संवैधानिक ढांचे के तहत करिए, वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं. हम गिलानी साहब के घर जाकर चार घंटे इंतजार किए, लेकिन उन्होंने दरवाजे नहीं खोले. हम क्यों दरवाजा खोलें. आप अपने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का भी पिछला कार्य देख लीजिए. गिलानी साहब को आपके लिए दरवाजा क्यों खोलना चाहिए? वह आपसे साधारण सा सवाल पूछ रहे हैं. आप पिछले तीन सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का कार्य देख लीजिए. क्या नतीजा निकला? एक ने भारत सरकार से पांच सिफारिश की, तो वो कूड़ेदान में डाल दी गई. हिंदुस्तान के लोगों को यह नहीं पता है कि कभी कोई सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जम्मू-कश्मीर गया और उसने कुछ सिफारिश की थी. दूसरे ने यह सुझाव दिया कि इंटर लोकेटर भेज दीजिए. उसके बाद दिलीप पडगांवकर, राधा कुमार और बाकी सभी लोग यहां एड़ियां रगड़-रगड़कर लोगों के पास पहुंचे और बात की. एक तो वापस चला गया, जिससे किसी ने बात नहीं की.

राजीव गांधी ने कहा था कि लेस दैन आजादी, एनिथिंग. उसके बाद वाजपेयी जी ने इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत की बात की. इन दो महीनों में तो आपने कोई इंसानियत नाम की चीज दिखाई नहीं. कश्मीरियत को आपने अपनी हैवानियत से पैरों तले रौंद दिया. जम्हूरियत आप कहते हैं तो फिर आप लोगों से पूछिए कि किस जम्हूरियत की बात आप कर रहे हैं जो आपको सूट करे या जम्हूरियत का कोई सही मतलब भी है. आप पहले इंसानियत दिखाओ. इंसानियत का आपने दिवाला निकाल दिया कश्मीर में. मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं मेनस्ट्रीम राजनीतिज्ञ हूं, लेकिन ऐसा ही रहा तो मुझे नहीं पता कि कितनी देर मैं मेनस्ट्रीम का रहूंगा. ये है स्थिति.

मैंने मुफ्ती साहब से कहा था कि आप धर्मनिरपेक्ष गठबंधन बनाइए, तो उन्होंने कहा कि नंबर कहां है. मैंने कहा कि ग्रैंड अलाइंस, नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस के साथ मिल कर बनाइए. उन्होंने कहा कि हमारा जो एजेंडा है, इंडो-पाक के रिलेशन को आगे चलाने का है. अगर हम कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, तो सरकार भाजपा की है हमें इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा. इंडो-पाक रिलेशन्स जहां है, वहीं रुका रहेगा और हालात खराब होंगे. लेकिन हमें कुछ हासिल हुआ, बल्कि हालत और खराब हो गई.

कश्मीर में सैलाब के 14 महीने बाद भी क्या हाल रहा? उत्तराखंड में 24 घंटे में सब कुछ हो सकता है. नेपाल में भूकंप आया तो आपके सभी लोग और आपकी पूरी सरकार वहां पहुंच गई और वो कह रहे थे कि हमें नहीं चाहिए आपकी मदद. तो कश्मीर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? आपकी इंश्योरेंस कंपनियों ने यहां अपनी दुकानदारी शुरू कर दी. भारत सरकार ने कभी ये, तो कभी वो बहाना बनाया. मुफ्ती साहब ने जब मोदी जी से निवेदन किया कि साहब, भारत को बड़े भाई की तरह पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर अपने संबंध ठीक करने चाहिए. उसके बाद मोदी ने मुफ्ती साहब से सार्वजनिक रूप से कह दिया कि मुझे कश्मीर पर किसी की सलाह की जरूरत नहीं है. मुफ्ती साहब ने इस बात से अपमानित महसूस किया और सात नवंबर को यह कहा और 7 जनवरी को दो महीने बाद उनकी मौत हो गई. इसके बाद उसी मोदी ने, जब गुजरात की घटना हुई और वाजपेयी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि उनको अपना राजधर्म निभाना चाहिए, ऐसा अपमानित किया मुफ्ती साहब को. मोदी को याद रखना चाहिए था कि सार्वजनिक रूप से जो प्रेस के सामने अपमानित होता है, तो वो अंदर ही अंदर मर जाता है. मुफ्ती साहब अपमानित हुए थे.

सेल्फ स्टाइल, हाइपर नेशलिस्ट चैनल जो चल रहे हैं, वे सब पाकिस्तान की ही मदद कर रहे हैं. अर्णव गोस्वामी इज डूइंग वेरी गुड सर्विस टू द पाकिस्तान. पता नहीं वह पाकिस्तानी एजेंट है या हाइपर नेशनलिस्ट है. न्यूज एक्स, जी, आज तक, टाइम्स नाऊ सब. हिंदुस्तान के बाहर एक इंडिया की ये क्रेडिबिलटी थी कि यह एक सेक्युलर स्टेट है. आप उस क्रेडिबिलटी के साथ खेल रहे हैं. मेरी नजर में ये सारा जिम्नास्टिक खेल आरएसएस का ही सेट किया हुआ है. उनका डिजाइन है राज्य को तीन हिस्सों में बांटना. इसके लिए वे खेल खेल रहे हैं. हर जगह आरएसएस ने अपनी शाखाएं खोलनी शुरू कर दी है. सीधे-साधे लोगों को पकड़ा है, उनको पैसे दे रहे हैं और शाखाएं खोल रहे हैं. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बड़गाम जिले में किसी गांव में वहां केवल एक अकेला घर है और भाजपा के साथ जुड़ गया है, उसको जाने कितना पैसा दिया गया है. उसको कहा गया, तुम भाजपा का नहीं, भारत का झंडा लगाओ अपने छत पर. दिल्ली बेस्ड न्यूज चैनल भेजे गए और कोई कश्मीरी चैनल नहीं. उसने कहा कि हम हिन्दुस्तानी हैं, हम अकेले हैं, हमारा सामाजिक बहिष्कार किया गया, हमारे घर कोई आता नहीं, लेकिन हम हिंदुस्तानी थे, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी रहेंगे और हिंदुस्तानी मरेंगे. अभी उसके घर के चारों तरफ सीआरपीएफ के लोग उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं. इतनी छोटी-छोटी चीजें कर भारतीय दर्शकों को बेवकूफ बना रहे हैं. इतना झूठ बोल रहे हैं. इसीलिए हम जैसे लोगों के लिए सियासत इबादत है. मेनस्ट्रीम के साथ रहकर, गद्दार का नाम अपने माथे पर लेकर, इंडियन एजेंट का नाम लेकर, फिर भी ये सुलूक हो तो फिर या तो हम बहुत ही बेशर्म हैं या बहुत ही बेगैरत. ■

(लेखक श्रीनगर से पीडीपी के सांसद थे, जिन्होंने मौजूदा कश्मीर समस्या के मद्देनजर लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. दिल्ली से आए तीन सदस्यीय पत्रकारों के दल से श्री कर्रा ने कश्मीर समस्या के सिलसिले में बातचीत की, जिसे उन्हीं के शब्दों में यहां प्रकाशित किया जा रहा है.)

feedback@chauthiduniya.com

हिंदुस्तान की जनता के ख़िलाफ़ नहीं हैं कश्मीरी

ज़फर इक़बाल मनहास

मैं पिछले दिनों दिल्ली में था. वहां मेरी एक थिंक टैंक से बात हो रही थी. उस थिंक टैंक के सभी लोग दक्षिणपंथी थे. मैंने उनसे कहा कि एक बार किसी शख्स की कोई चीज खो गई और वह उसे खोज रहा था. तब तक वहां एक व्यक्ति और आ गया और वह उसकी मदद करने लगा. उसने कहा कि तुम्हारी चीज कहां खो गई है, तो उसने कहा कि अंदर कमरे में खो गई. इसके बाद दूसरे व्यक्ति ने कहा, कमाल हो गई तुम्हारी चीज कमरे में खोई है और तुम कमरे के बाहर सड़क पर खोज रहे हो. उसने कहा, क्या करूं? कमरे के अंदर अंधेरा है, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि इस रोशनी में तुम सारा जीवन खोजते रह जाओगे और खोई हुई चीज कभी नहीं मिलेगी. जहां पर चीज खोई है, वहां खोजनी चाहिए. मेरा मानना है कि कश्मीर का मसला कश्मीर में नहीं, दिल्ली की गर्दिश में खो गया है. आप कश्मीर में जितनी मर्जी हो समाधान खोज लो. इस मसले का हल दिल्ली में है, अगर वो हल करना चाहे.

कश्मीर कोई छोटी कांस्टिट्एंसी नहीं है जो इसकी तरफ आप ध्यान नहीं देते हैं. जब यहां जंग शुरू होती है, पत्थर मारे जाते हैं, बंदूक चलती है, तो दिल्ली में बैठा हर शख्स सोचता है कि ये लोग अप्रासंगिक हो गए हैं, अब इनसे क्या बात करनी है. आप जिन्हें प्रासंगिक (रिलेवेंट) कहते हैं, वो बात कर नहीं सकते, क्योंकि वो इस स्थिति में हैं नहीं. उनमें से कोई शेख मोहम्मद अब्दुल्ला नहीं है, जो अपनी मर्जी से अच्छी या बुरी बात कर सके या अच्छा या बुरा फैसला ले सके. गिलानी अपने स्टैंड से बाहर चले जाएं, ही विल बी नो मोर, यासीन एक सूत इधर से उधर हो जाएं, तो ही विल बी नो मोर. जब आप अपने आदमी के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, तो दुश्मन से कैसे करेंगे.

यह ठीक है कि गिलानी पाकिस्तान मांगते हैं, यासीन आजादी मांगते हैं, उमर साहब स्वायत्तता मांगते हैं. यानी, सब कुछ न कुछ मांगता है. दिल्ली से कुछ भी दिया नहीं जा रहा है. गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मैंने कहा कि आपने 6 घंटे संसद में कश्मीर पर चर्चा की, लेकिन वहां से पीओके निकला या बलूचिस्तान निकला. चर्चा कश्मीर पर हो रही थी कि वहां अशांति और मारधाड़ क्यों? उन्होंने कहा कि अब क्या करें? मैंने कहा, फिलहाल इतना ही कीजिए, प्रधानमंत्री से कहिए कि वे एक स्टेटमेंट दें कि हम धारा 370 का आदर करते हैं और अगले पचास साल तक हम इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, तो अंदर की सांस अंदर और बाहर की सांस बाहर हो गई. दूसरा स्टेटमेंट इसी के साथ जोड़ दीजिए कि जम्मू-कश्मीर के पास जो स्वायत्तता है, उससे हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे. होता ये है कि सीबीएम (कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स) के नाम पर पैसा देते हैं, सड़क देते हैं, बिजली देते हैं. कश्मीरी कहता है कि उसके लिए हमने वोट डाले हैं. हर कश्मीरी को चुनाव के समय जब पूछा जाता है तो वह साफ कहता है कि वह रोटी, कपड़ा, मकान के लिए इसमें हिस्सा ले रहा है. वो जब ये कहता है हमें जो मार पड़ रही है, एक लाख जो मर गए, उसके बदले में मैं कुछ और मांग रहा हूं. रोटी, कपड़ा, मकान से अलग.

मेरी अपनी सोच है, जरूरी नहीं है कि आप सहमत हों या हुर्रियत वाले मेरे साथ सहमत हों. मैंने कहा कि मैं ज़फर इक़बाल मनहास पाकिस्तानी नहीं हूं, अगर कोई मेरे टुकड़े-टुकड़े कर दे तो भी मैं पाकिस्तान के साथ नहीं जा सकता. मैं आजादी भी नहीं मांगता हूं. आजादी इसलिए नहीं मांग रहा हूं कि मैं ग्राउंड रिएलिटी को देखता हूं. मैं जम्मू और लद्दाख को साथ जोड़ता हूं. जमीनी हकीकत ये है कि आज के दिन कश्मीर की समस्या भारत सरकार के हाथ से निकल चुकी है और यह मसला भारत के 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के डोमेन में चला गया है.

1970 में सिर्फ शेख अब्दुल्ला को नीचा दिखाने के लिए जमात-ए-इस्लामी के साथ कांग्रेस ने हाथ मिलाया. उनको 6 सीटें और 30 हजार रुपये चुनाव लड़ने के लिए दिए. मुझे पता है कि इधर से मुफ्ती मोहम्मद सईद, अब्दुल गनी लोन और मौलवी अंसारी थे और उधर से गुलाम नबी नीशहरी, सैफुद्दीन और हकीक गुमाल नबी थे. मेरा कहने का मतलब है कि उनको कोई पाला, तो उन्होंने पाला. इस विंग का कोई मुकाबला यहां कर सकता था, तो सेक्यूलर जमात कर सकती थी, वो नेशनल कांफ्रेंस कर सकती थी, शेख अब्दुल्ला कर सकते थे.

फारूक अब्दुल्ला आ गए थे. उसने क्या गुनाह किया था? फारूक अब्दुल्ला ने इतना गुनाह किया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया. 1984 में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने आकर चिल्लाया कि फारूक अब्दुल्ला अगर जीत गया, तो जम्मू-कश्मीर पाकिस्तान बन जाएगा. उसने इतना किया था कि सभी विपक्ष को एकजुट किया. इससे हिंदुस्तान मजबूत हो रहा था. 1984 में एक साल भी उस सरकार को इन्होंने चलने नहीं दिया, उसको रातोंरात बर्खास्त कर दिया. जब इन्होंने इस सरकार को हटाया, तो उस समय फारूक अब्दुल्ला जब सड़क पर निकलता था सब्जी खरीदने के लिए तो लगभग दो हजार लोग जमा हो जाते थे. उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने सती साहनी से कहा कि लिखो मेरी किताब, उस किताब का नाम रखो माई डिसमिसल. उसमें उन्होंने कहा कि तौबा मेरी तौबा. मैं भी बेवकूफ था, मेरा बाप भी बेवकूफ था. वह कहता है कि, मुझे लगता था कि यहां लोग अपना नेता चुनते हैं, लेकिन मैं बेवकूफ था. यहां जो चुना जाता है वह दिल्ली से और अब मैं दिल्ली से पंगा कभी नहीं लूंगा. उसके बाद फारूक अब्दुल्ला हार मानकर एक तरफ चल गया, लेकिन इसके बाद कश्मीरी एक बार फिर टूट गया. लोगों के अंदर बौखलाहट आ गई. दिल्ली ने यह सुनिश्चित कर लिया कि फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस के साथ गठबंधन कर ले. फिर बंदूकें भी आ गईं. खैर बंदूक के पीछे पाकिस्तान भी था. मेरे कहने का मतलब है कि आप लोगों (दिल्ली) ने कितना विश्वासघात किया.

कहने का मतलब है सारी समस्या इसीलिए है कि भारतीय कांस्टीट्यूशन का असर यहां कम हो गया है या सिकुड़ गया है या इनएक्टिव हो गया है. मैं हमेशा अपने विधायक साथियों से कहा करता था कि मुझे एक खतरा है, तो वो हंसते थे. मैंने कहा, मैं उस दिन से डर रहा हूं, जब 2010 और 1990 से भी बुरे हालात होंगे. लोग बाहर निकल आएंगे, आर्मी इनकी पिटाई करेगी. ये अपनी हार का बदला लेने के लिए अपने से कमजोर टारगेट को ढूंढेगा, उस रोज हम कहां जाएंगे. तब हर आदमी हम पर हंसता था. एक दिन दिल्ली में था. एक सीनियर अफसर मुझसे मिले. उन्होंने पूछा कि क्या स्थिति है? मैंने कहा, स्थिति बहुत खराब है, वह इतनी जोर से हंसे कि चाय उनकी कमीज पर गिर गई. कहा, तुम कश्मीरी हमें डराते हो. अब न कभी 2010 होगा, न 1990 होगा. मैंने कहा कि अभी डायरी निकालो, लिखो इसी 2016 में न हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और कश्मीर भी.

अगर आप देखें तो पाएंगे कि इस देश में मुस्लिम अल्पसंख्यक, गलत हो या सही, बहुत डरा हुआ है. और वो डर कश्मीर में पिछले एक साल से जमा हो रहा था. मुफ्ती साहब की बेइज्जती हुई. प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे किसी की सलाह नहीं चाहिए. बिजली प्रोजक्ट देने थे वो नहीं दिए. बीफ का मसला बीजेपी ने खड़ा किया. कोर्ट में बीजेपी के लोग गए. फ्लैग का पंगा कांग्रेसियों ने नहीं किया 1987 तक. मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं. मैं केवल इतिहास बता रहा हूं. यह सब जमा होता गया. फिर बुरहान वानी भी एक बहाना हो गया. मैं बोल रहा था कि पहली बार कोई आतंकवादी(मिलिटेंट) मरता है, तो 60 से 70 हजार लोग जमा हो जाते हैं. कहीं पर कोई कार्रवाई मिलिटेंट के खिलाफ होती है, तो औरतें बच्चे आ जाते हैं तो इसे समझने की जरूरत है कि ये क्या है?

मुझसे एक बार एस दुल्लत ने पूछा था कि क्या हो रहा है चुनाव का. मैंने कहा कि फारूक साहब की पार्टी जीतेगी या मुफ्ती साहब की पार्टी जीतेगी, आप तो हार गए. उन्होंने कहा क्या बचकानी बात कर रहे हो, वो जीते तब भी हम जीते और वो जीते तब भी हम जीतेंगे. इस पर हमने कहा कि यही तो रोना है. उन्होंने कहा, कैसे? दोनों ने दिल्ली के खिलाफ कश्मीरी से वोट मांगा है, किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ वोट नहीं मांगा है. किसी ने पाकिस्तानी को गाली नहीं दी, दोनों ने दिल्ली को गाली दी. बस फर्क इतना है कि किसी ने कहा, ये बड़ा एजेंट है और दूसरे ने कहा, यह दिल्ली का बड़ा एजेंट है. जब तक हम एजेंट के रूप से बाहर आकर हिंदुस्तानी नहीं बनेंगे और उसके लिए वो माहौल खड़ा नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी.

सच यह है कि दिल्ली के साथ यहां एक ही फीसद लोग हैं. आज कश्मीर में दिल्ली के पास इसके सिवाय कुछ भी नहीं है. एमजे अकबर आजकल बड़े चाचा बने हैं भाजपा के. उन्होंने अपनी किताब कश्मीर-बिहाइंड वेल्स में लिखा है कि जब तक शेख अब्दुल्ला की कब्र पर पहरा है, तब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा. मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप कश्मीरियत में अमन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यहां पाकिस्तान कमजोर हो तो उसके लिए आपको यहां पर कश्मीरियत को मजबूत करना होगा. लेकिन कश्मीरियत वो जिसे हम कश्मीरियत कहते हैं. वो नहीं जिसे कश्मीरी पंडित कश्मीरियत कहता है या दिल्ली में बैठकर लोग कश्मीरियत की नई परिभाषा बना रहे हैं. कश्मीरियत को यहां बचाना होगा. हमें कश्मीरियों को यह विश्वास दिलाना होगा कि यहां उसकी पहचान को कोई खतरा नहीं है. चाहे यह सही हो या गलत, लेकिन हर कश्मीरी को लगता है कि उसकी पहचान को खतरा पैदा हो गया है. इतिहास के कार्यों से उसे यही लगता है कि दिल्ली किसी न किसी सूरत में उसके बहुसंख्यक चरित्र को बदलने में लगी है. यहां की डेमोग्राफी को बदलना चाहती है. इस चीज को उनके दिमाग से निकालना है. अब यह चीज तेजी से बढ़ी है, जो खतरनाक है.

पहले यह था कि दिल्ली में बैठकर यह सोचा जाता था कि कश्मीरी अलग-थलग पड़ गया है, कैसे उसे दूर किया जाए. मुझे एक समस्या यह नजर आती है कि हिंदुस्तान का नागरिक कश्मीरी से अलग-थलग हो गया है. अगर ऐसा हो जाए और ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो फिर क्या होगा. कश्मीरी कहां जाएगा. जिधर जाएगा, मार खाएगा, वापस आएगा. जब वापस आएगा, कहां जाएगा. मार खाएगा, खुदकुशी करेगा, बुरहान वानी बनेगा या बंदूक उठाएगा, जहर खाएगा या मरेगा या मारेगा. अगर इसके लिए हैदराबाद, महाराष्ट्र, कर्नाटक की जमीन तंग हुई तो फिर क्या होगा? इसलिए हमने यह सब बातें आपके सामने रखीं. आप जानें और समझें कि आखिर मसला क्या है और कश्मीरी के दर्द को समझें. अब वक्त आ गया है कि कश्मीरियों को बाहर लाया जाए और खुली फिजा में बोलने दिया जाए. हिंदुस्तान की जनता को कम से कम बताएं कि कश्मीरी हिंदुस्तान की जनता के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन दिल्ली से कश्मीर की जनता को बहुत शिकायत है. ■

(लेखक पीडीपी एमएलसी हैं और दिल्ली से गए तीन सदस्यीय पत्रकारों के दल से उन्होंने कश्मीर मसले पर अपनी निजी राय साझा की. उनकी राय, उन्हीं के शब्दों में यहां प्रकाशित की जा रही है)

feedback@chauthiduniya.com

जम्मू-कश्मीर विधानसभा

सभी बिल दिल्ली से बनकर आते हैं

दिल्ली से गए तीन सदस्यीय पत्रकारों के एक दल ने कश्मीर की सिविल सोसाइटी से भी बातचीत की. इसी कड़ी में कश्मीर सिविल सोसाइटी की एक प्रतिनिधि हामिदा नईम ने कश्मीर मसले पर अपनी बेबाक राय रखी, जिसे उन्हीं के शब्दों में यहां प्रकाशित किया जा रहा है.

कभी भी जम्मू-कश्मीर में फ्री डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं हुआ, इट वॉज ऑलवेज मैनुपुलेट. 1977 में यहां एक चुनाव हुआ था, तब केंद्र में मोरारजी की सरकार थी. उन्होंने उस वक्त साफ-सुथरा चुनाव करवाए थे. वही सिर्फ एक चुनाव था, जो बेहतर तरीके (फेयर) से हुआ. 1996 के बाद से पिछले 30 साल में हमें काफी नुकसान हुआ. यहां की शांति भंग की गई. सेना ने गांव के गांव, शहर के शहर जला दिए. यहां भारी संख्या में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले सामने आए. इतना होने के बाद भी भारत की प्रतिक्रिया क्या रही? उसने फिर एक ऐसी सरकार जम्मू-कश्मीर पर थोप दी, जिसे शायद ही कभी 5 फीसद वोट मिला हो. अनगिनत कश्मीरियों की कुर्बानी के बावजूद हम पर फारूक अब्दुल्ला की सरकार लाद दी गई. इससे सिर्फ मानवीय ही नहीं, हमारे मान-सम्मान की भी क्षति हुई. औरतों के साथ बलात्कार हुए. हजारों घर तबाह कर दिए गए. आपको शायद पता हो क्रैक डाउन ऑपरेशन के बारे में. इसमें क्या-क्या हुआ? क्रैक डाउन ऑपरेशन में सब मर्दों को एक मैदान में जमा करते थे. घरों में जाते थे और सब तहस-नहस कर देते थे, लूट-खटोस करते थे. मैं इसे डिस्ट्रॉय (विनाश) ऑपरेशन कहती हूं. घर में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते थे और मर्दों को घर के बाहर रखते थे. शायद आपने वह नहीं देखे हैं. वह ऑपरेशन 15 साल तक चला. कश्मीरी साइकी (दिमाग) को इस तरह नुकसान पहुंचाया गया, इस तरह जख्मी किया गया कि वह हिंदुस्तान के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता. ये सब होने के बाद जब यहां महीनों तक कर्फ्यू रहा, फिर आपकी वही स्ट्रेटजी रही. उसके बावजूद, वही फ्रॉड सरकार. लोकतांत्रिक सरकार होने का दुनिया में ढिंढोरा पीटते हैं. जब वह लोकतांत्रिक सरकार आती है, फिर वह एक नया प्रस्ताव पास करती है, ऑटोनॉमी (स्वायत्तता) की. स्वायत्तता का यह प्रस्ताव आजादी चाहने वालों के एजेंडे को चुराने के लिए लाते हैं. वह प्रस्ताव दो तिहाई बहुमत से पास हुआ. राज्य विधान सभा में जितने भी कानून बनते हैं, वो असल में दिल्ली से तैयार होकर आते हैं. हम समझते नहीं हैं, वे रोज कहते हैं कि ये बिल आया, वो बिल आया है असेंबली में. ये ऐसे बिल होते हैं, जिनका दूर-दूर तक लोगों से कोई वास्ता नहीं होता है. ये सारे बिल कश्मीरी लोगों को कमजोर बनाने के लिए होते हैं. विधान सभा में अचानक बिल आते हैं. ये बिल एजेंसीज बना कर लाती हैं और कहती हैं कि इसे पेश करो. उसमें जो रीयल लेजिसलेशन होता है जनता के सशक्तिकरण के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, ऐसा आज तक हमने नहीं देखा. मैं ये बात बिना किसी विरोधाभास के कह सकती हूं. कोई भी बिल कश्मीरी लोगों को सशक्त बनाने के लिए या गुड गवर्नेंस के लिए कभी नहीं होता है.

जब हमारे जवानों ने बंदूकें उठाईं, तब बड़े-बड़े राजनीतिक पंडित आए और बोलने लगे कि आप लोकतांत्रिक तरीके से लड़ो. आपको सब कुछ मिलेगा, बंदूक छोड़ दो, आपको सब कुछ मिलेगा. हिंदुस्तान आपको सब कुछ देगा. अब लोगों ने बंदूकें भी छोड़ दी हैं. 2008 में लोगों ने शांतिपूर्ण विरोध किया. 2010 और अब 2016 में विरोध हो रहा है. मैं खुद गवाह हूं. उस दिन 10 से 12 लाख लोग आए थे. मैं खुद उस दिन देखने गई. उस दिन मुझे लगा कि कश्मीर में आजादी है. उस दिन खुद लोग आए थे और अपने आपको संभाल रहे थे, खुद ईदगाह जा रहे थे. कोई कम्प्यूजन नहीं हुआ. हिंदुस्तान में कोई मेला होता है, तो उसमें भगदड़ मच जाती है. लेकिन यहां 12-14 लाख लोग एक जगह आते हैं, आप देख सकते हैं कि वे किस तरह व्यवहार करते हैं. उस समय लोगों को लगा कि वे आजाद हैं. मैंने वे क्षण देखे हैं. मैं उस क्षण के बारे में बताना चाहती हूं, जो मैंने देखा कि जब अगले दिन 12 से 15 लाख लोग सड़कों पर आए तो कंप्लिटली क्रैकडाउन किया गया. आपने कश्मीरियों को साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, सोशली कमजोर करने का काम किया. आप जब कर्फ्यू उठाते हैं, तो लोग कहते हैं कि हम अब बाहर निकलना चाहते हैं. उनको लगता है कि ये है आजादी. यही स्ट्रेटजी इन्होंने आज तक चलाई. आज लोग समझ चुके हैं. आज जब कर्फ्यू हटाया गया, तो कई बाहर नहीं निकला क्योंकि ये सभी स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो चुकी है. डर और आतंक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है. लेकिन, आज लोग इस सब से तंग आ चुके हैं.

जब फारूक अब्दुल्ला आए तो एक नया विवाद खड़ा किया गया. यहां यात्रा होती थी बड़ी शांति से. 10 हजार लोग आते थे. कश्मीरी उनकी अच्छी तरह से मेहमाननवाजी करते थे, कोई परेशानी नहीं होती थी. हम उसमें जाते थे. आने-जाने वाले यात्रियों का स्वागत करते थे. उन्होंने इसे भी पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा बना दिया. इस यात्रा का भी राजनीतिकरण कर दिया. उन्होंने एक ट्रस्ट, अमरनाथ यात्रा ट्रस्ट (श्राइन बोर्ड) बनाया. इसे सरकार से अलग किया और इसमें पहले पंडितों को रखा. गवर्नर इसके प्रमुख हैं. इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं को मोबलाइज किया. उन्होंने कहा कि हम आपको फ्री राइड में ले जा रहे हैं कश्मीर. यहां आपको मालूम होना चाहिए कि ये एरिया इकोलॉजिकली (पर्यावरणीय दृष्टि से) बहुत संवेदनशील है. लोग गंगोत्री जाते हैं. वहां पर्यावरण और कानून के हिसाब से हर दिन केवल 150 यात्रियों को जाने दिया जाता है और यहां 50-50 हजार लोग रोज आते हैं. ये हमारी इकोलॉजी को खत्म करने के लिए किया गया. इस पर भी हमने आवाज उठाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी. इसमें दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक एक्स्ट्रा कॉन्सटीट्यूशनल बॉडी बन गई है. यह अब राज्य सरकार पर निर्भर नहीं है. यह स्वतंत्र रूप से काम करती है. पिछली बार उन्होंने इसके सारे मेंबर्स दिल्ली के बनाए. पंडित को भी नहीं रखा. अब यह पूरा का पूरा भारतीय श्राइन बोर्ड हो गया है. अब उन्हें लालच हो गई है. उन्होंने अमरनाथ नगर का प्लान बनाया था कि सब कुछ स्वतंत्रतापूर्वक होगा और एक राज्य के भीतर एक अलग स्टेट बन जाएगा. उस समय, 2008 में हमने एक तहरीक चलाई. वो तहरीक हमने उस समय इसलिए चलाई कि अमरनाथ नगर, एक राज्य के भीतर एक आत्मनिर्भर राज्य बन जाता. हमने इस पर आंदोलन इसलिए किया कि हम इसके लिए जमीन नहीं देंगे क्योंकि हम जानते हैं कि इससे पूरा कश्मीर सांप्रदायिक आधार पर बांट दिया जाएगा. इसलिए, हमने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया.

राजनीतिक प्रक्रिया और लोकतंत्र के नाम पर हमें डिसइंपावर (कमज़ोर) किया गया है. पीडीपी सरकार ने कहा कि हमारे पास एजेंडा ऑफ अलायंस है. एजेंडा ऑफ अलायंस में है कि हम कश्मीर समस्या के समाधान के लिए बातचीत को आगे बढ़ाएंगे. हम ये करेंगे, वो करेंगे. पहले उन्होंने भाजपा के खिलाफ़ वोट हासिल किया. उसके बाद सरकार बनाने के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया.

ध्यान देने वाली बात है कि अमरनाथ मंदिर को एक मुसलमान ने ही खोजा था और मलिक पूजा-पाठ भी वही करवाते थे. मुझे याद है कि बचपन में जब साधु-संत आते थे, तो घर-घर जाकर भिक्षा मांगते थे और लोग उनको भिक्षा भी देते थे. उस पैसे से उनका जीवन चलता था. जुलूस निकलता था, जैसे छड़ी मुबारक, इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों साथ-साथ चलते थे. रास्तों पर जो लंगर होते थे, वो मुसलमान लगाया करते थे, चाहे बेशक वो पैसा लेते रहे होंगे. ये सारी चीजें एक मिली-जुली संस्कृति को दिखाती हैं. पहले यात्री जो जाते थे, उन्हें मुसलमान घोड़े और यहां तक कि अपने कंधों पर भी ले जाते थे. लेकिन अब जो हुआ, वो पूरी तरह से मामले को सांप्रदायिक रूप दे दिया गया. एक तो पहले मलिक को बेदखल किया गया और एक बार पैसा देकर उन्हें हटा दिया गया. मंदिर है, तो फिर वहां कोई मुसलमान नहीं रह सकता है. अब वहां पर साधु रखा गया है. ठीक है. अब लंगर को बड़े-बड़े उद्योगपति स्पांसर करते हैं और जो ठेका लेने वाले ठेकेदार हैं, वहां जगह-जगह फ्री में खाना मिलता है. लेकिन एक मुस्लिम को लंगर का ठेका लगाने की अनुमति नहीं है. जो वहां के हिंदू हैं, वही ठेका लेते हैं. यानी, मिली-जुली संस्कृति खत्म हो गई. अब जो घोड़े वाले हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है, यहां झगड़ा होता है, जो पहले कभी नहीं देखा गया था. अब यह कर दिया गया कि अमरनाथ यात्रा का आयोजन हिंदू करेगा. इस तरह इस यात्रा को साम्प्रदायिक बना दिया गया और मुसलमानों की भूमिका को समाप्त कर दिया गया. कहने का मतलब यह कि इसमें साम्प्रदायिक राजनीति कहां से आई? यह एक श्राइन था, जिसको एक स्टेट चलाता था. स्टेट से अब इसे अलग कर दिया गया. इसे एक स्वतंत्र बोर्ड बना दिया गया, जो स्टेट गवर्नमेंट के तहत नहीं है और सारे निर्देश दिल्ली से लेता है. हमने बार-बार कहा कि यात्रियों के आने के नियम को रेगुलराइज करो, जैसे आपने गंगोत्री में किया क्योंकि यह भी पर्यावरणीय हिसाब से काफी संवेदनशील इलाका है. वहां पर आप चिंता दिखाते हो. यहां, इस जमीन की भी चिंता करो. गंगोत्री में जो ग्लेशियर है, वह बहुत पीछे चला गया. वहां पर लोगों की चहल-पहल और वार्मिंग के कारण ऐसा हुआ, लेकिन यहां के बारे में कोई नहीं सोचता.

अब इस सरकार ने पिछले दो सालों में क्या किया है? पंचतरनी तक एक अलग रास्ता वहां से निकाल रहे हैं. इसका मतलब है कि लोगों को यह भी समझ में आए कि आप इसे एक अलग हिंदू नगर बना रहे हैं. नितिन गडकरी जब सड़क एवं परिवहन मंत्री बने, उन्होंने जम्मू-कश्मीर सरकार से कहा कि आप जवाहर टनल से दाएं और बाएं इतनी जमीन एक स्वतंत्र निकाय को हस्तांतरित करो, ताकि हम उसे यात्रा के लिए विकसित कर सकें. कश्मीरी पंडितों ने अपनी एक योजना सरकार को बताई, जिसमें वो अपना एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, जवाहर टनल के दाएं से लेकर अमरनाथ गुफा तक. आप अमरनाथ श्राइन बोर्ड बिल पढ़िए. उसमें लिखा है कि वे एयरपोर्ट बना सकते हैं, वे रेलवे लाइन बिछा सकते हैं, अस्पताल बना सकते हैं, पावर स्टेशन बना सकते हैं. इसके लिए केवल श्राइन बोर्ड को राज्य सरकार को एक आवेदन देना है कि हमें फलाने जगह इतनी जमीन चाहिए. और राज्य सरकार को यह करना है, लेकिन पैसा उनका अपना होगा. हमने कभी अमरनाथ यात्रा की मुखालफत नहीं की. जैसे इजरायल आउट आफ नो व्हेयर बना, उसी तरह ये श्राइन बोर्ड बना. नहीं तो, 185 साल से अमरनाथ यात्रा का संचालन मुसलमान करता था. जिस समय इस गुफा की खोज हुई थी, उस वक्त एक समझौता हुआ था कि उसमें जो चढ़ावा आएगा उसके तीन हिस्से होंगे. एक हिस्सा मलिक लेगा, दूसरा धर्मस्थ लेंगे और तीसरा मट्टन के पंडे लेंगे. मट्टन अनंतनाग के पास एक जगह है. एसके सिन्हा जो यहां के गवर्नर थे, उन्होंने मलिक को एक बार पैसा देकर बेदखल कर दिया. पता नहीं मलिक को हटाने के बाद कुछ पैसे दिए या नहीं, यह किसी को पता नहीं है. लेकिन कहा जाता है कि उसको कुछ पैसे देकर हटा दिया गया. कश्मीर का गवर्नर भी हिंदू के बजाय कोई और हो ही नहीं सकता.

मेरे कहने का मतलब है कि जबसे हमने ये तहरीक जोर-शोर से चलाई, तबसे उन्होंने क्या-क्या चाल चली. मैं यह कहना चाहती हूं. यह किसी स्टेट में नहीं हो सकता है कि आप एक ऐसा एक्स्ट्रा कॉन्सटीट्यूशनल बॉडी बनाएं जो सरकार से पूरी सहायता ले, लेकिन उसकी कोई जिम्मेदारी राज्य सरकार के प्रति न हो. एक छोटा सा उदाहरण है. जैसे, वैष्णो देवी के लिए या अमरनाथ दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस है. इससे मिला सारा पैसा श्राइन बोर्ड को जाता है. सवाल है कि एयर स्पेस किसका है? क्या श्राइन बोर्ड, नहीं. फिर, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या भारत के किसी अन्य राज्य में ऐसा उदाहरण है?

कुल मिला कर मैं ये बताना चाह रही हूं कि किस तरह असेंबली के जरिए लोगों को कमजोर बनाने की कोशिश की गई? राजनीतिक प्रक्रिया और लोकतंत्र के नाम पर हमें डिसइंपावर (कमजोर) किया गया है. पीडीपी सरकार ने कहा कि हमारे पास एजेंडा ऑफ अलायंस है. एजेंडा ऑफ अलायंस में है कि हम कश्मीर समस्या के समाधान के लिए बातचीत को आगे बढ़ाएंगे. हम ये करेंगे, वो करेंगे. पहले उन्होंने भाजपा के खिलाफ वोट हासिल किया. उसके बाद सरकार बनाने के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया. ये एजेंडा ऑफ अलायंस सब बकवास था, भ्रम था. अब वो धीरे-धीरे कश्मीरी लोगों को जमीन के मामले में भी कमजोर बनाने के रास्ते पर चल रहे हैं. इसके लिए उनके पास कई प्लान हैं और उन्होंने इस पर काम भी शुरू कर दिया है. ऐसी ही योजना है शेल्टर फॉर होमलेस. इसमें 20 हजार करोड़ रुपये, 5 लाख शेल्टरलेस (घर विहीन) लोगों को घर बनाने के लिए रखा गया है. यानी, जो बेघर हैं, उन्हें वहां बसाएंगे. जिन सैनिकों ने हम पर अत्याचार किए, उनके लिए भी कॉलोनी बना रहे हैं. आप इसके लिए जमीन दे रहे हैं. कश्मीरी पंडितों के लिए इन्क्लेव बनाने की बात है. ■

feedback@chauthiduniya.com

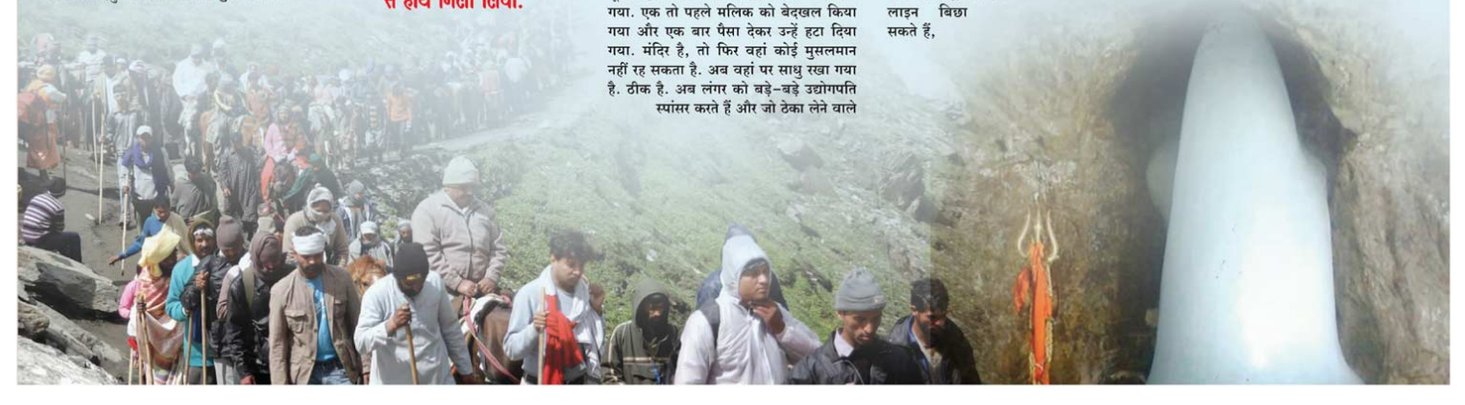

पुनर्विचार की ज़रूरत है

दोनों देशों के बीच संवैधानिक संपर्क की जो बात प्रधानमंत्री ने की, वह आज के संदर्भ में काफी दिलचस्प है. यह नहीं मानना चाहिए कि पाकिस्तान हमेशा ऐसे विचार को नकारता ही रहेगा. आख़िरकार, हर देश अपने आर्थिक मसले और सुरक्षा को लेकर सबसे अधिक चिंतित रहता है. क्या इसमें कोई शक है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक संवैधानिक संपर्क से इन दोनों देशों को सुरक्षा और आर्थिक तरक्की की गारंटी नहीं मिलेगी? इसके अलावा, शेख अब्दुल्ला भी इसी लाइन पर सोच रहे हैं, जिससे इस स्थिति के लिए एक नई आशा जागती है. इसलिए अगर सख़्त पोजिशन को छोड़ दिया जाए, तो एक ऐसे सही समाधान निकलने की उम्मीद की जा सकती है, जिससे भारत, पाकिस्तान और कश्मीर के लोग भी संतुष्ट हों. एक स्टेट्समैन को यही काम करना है.

जयप्रकाश नारायण
(15 मई 1964 को हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित आर्टिकल)

कश्मीर पर मेरे हाल के एक आर्टिकल से तीव्र विवाद पैदा हुआ. यह ठीक भी है, क्योंकि भावनात्मक तनाव के निकल जाने के बाद मिजाज शांत हो जाना चाहिए. इससे एक ऐसे सवाल के प्रति तार्किक दृष्टिकोण पैदा होती है, जिससे यह उपमहाद्वीप पिछले 17 सालों से जूझ रहा है. इस सवाल पर तत्काल फिर से विचार किए जाने की जरूरत है. मैंने इस आर्टिकल में सिर्फ कुछ तर्क रखे हैं, कुछ निवेदन किए हैं. जिनलोगों ने भी मुझे देशभक्ति पर क्रोधित होकर उपदेश दिए हैं, वे उस सत्य की ओर देखना ही नहीं चाहते, जिधर मैंने ध्यान खींचने की कोशिश की थी.

अभी भी, मेरी इच्छा इस विवाद को लंबा खींचने की नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं कि इससे जुड़े उन सभी लोगों को मदद मिलेगी, जिनके इस मुद्दे पर अपने-अपने विचार हैं, लेकिन हाल में कुछ चौंकाने वाले बयान और खतरनाक मनोवृत्ति सामने आए हैं. इसलिए यह जरूरी है कि इनमें से कुछ चिंताजनक मुद्दों पर विस्तार से बात की जाए और संभव हो, तो एक रचनात्मक रास्ता तलाशा जाए.

जब मैंने अपने आर्टिकल में इस शोरगुल के बारे में लिखा था, तो मुझे इस तरह की संगठित मनोवृत्ति, जो उन्मत व असहमत स्वर के खिलाफ करीब-करीब हिंसक थी, का अंदाजा था. दिल्ली में शेख अब्दुल्ला के आगमन पर लोगों का उन्माद उसी तरह का था, जिसकी वजह से राष्ट्रपिता को कुर्बान किया गया था. दुखद रूप से संसद ने खुद इस तरह की असहिष्णुता को बढ़ावा देने में मदद दी. कुछ संसद सदस्यों की मानसिकता का पता इसी से चलता है कि एक समय केंद्रीय मंत्री रहे और अब के यूपी कांग्रेस अध्यक्ष एपी जैन ने कथित तौर पर कहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिनकी राय मुझसे अलग है और जिस तरह की बात लगातार श्री नारायण कर रहे हैं, उससे उनका धैर्य जवाब दे सकता है.

मुझे नहीं मालूम कि श्री जैन किस तरह की धमकी देना चाहते हैं, शायद वे और उनके मित्र मुझे जेल भेजना चाहते हैं. व्यक्तिगत तौर पर मैं ऐसे किसी भी कदम का स्वागत करूंगा और इस अवसर का फायदा आराम करने और अध्ययन के रूप में उठाऊंगा. लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब श्री जैन जैसे व्यक्ति इस तरह की बात कर सकते हैं, तब तो कोई उन्मादी युवा किसी की हत्या भी करने की सोच सकता है.

जब मैंने दिल्ली की एक जनसभा में इसे बताने का जिक्र किया, तो राज्यसभा में मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे लिए सुरक्षा की मांग की, बजाए इस गंभीर मुद्दे और इसके खतरे पर विचार करने के. (मुझे सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है). क्या मैं यह कह सकता हूं कि इस हालात को सुधारने के लिए माननीय संसद सदस्य खुद के व्यवहार में ही थोड़ी सहिष्णुता और धैर्य दिखाएं.

इस विवाद के क्रम में दिए गए बयानबाजी में कांग्रेस के 27 सांसद (कांग्रेस सचिव समेत महत्वपूर्ण सदस्य) निश्चित तौर पर बाजी मार ले जाएंगे. सबसे पहले तो उनकी तरफ एक बात सामने आती है, नैतिक और मानवीय मूल्यों पर कानून की सर्वोच्चता की. एक विधायिका के रूप में सांसदों को कानून की प्रकृति और सीमा को समझना चाहिए, क्योंकि वे ही कानून बनाते हैं, खत्म करते हैं और उसमें संशोधन करते हैं. मानवीय मामलों में कानून का महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है. नैतिकता और मानवीय मूल्य अंत में कानून पर भारी पड़ते हैं.

नैतिक क्या है, यह किसी एक व्यक्ति के विचार की बात नहीं है. यह पहचानना मुश्किल नहीं है कि आज के दौर में क्या नैतिक है और क्या मानवीय है. यह महात्मा गांधी ही थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राजनीति को आध्यात्मिक बनाने के लिए झोंक दिया. यह दुखद है कि जिस संगठन को गांधी जी ने बनाया, उसी के ज्यादातर सदस्य आज नैतिकता और मानवतावाद का तिरस्कार करते नजर आ रहे हैं.

कश्मीर मुद्दे पर बात करते हैं. यह कैसे हुआ कि वे लोग अधिकारपूर्वक यह बोल सके कि कश्मीर के लोगों को अब और अधिक आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं मिल सकता है. आगे वे कहते हैं कि क्या आजादी मिलने के बाद अमेरिका के राज्यों ने आत्मनिर्णय की बात की? इसका जवाब कांग्रेस के सांसदों को बेहतर पता होगा. फिर ऐसी घबराहट क्यों?

जनता, जिसकी याद्दाश्त कमजोर होती है, उसे समझाया गया कि कश्मीर के मसले पर आत्मनिर्णय की बात जयप्रकाश नारायण के दिमाग की उपज थी. इस बारे में मुझे रिकार्ड दुरुस्त करने दीजिए. जब विभाजन की बात हुई, तब यह तय हुआ कि हिंदू और मुस्लिम आबादी की बहुलता वाले क्षेत्र के आधार पर बंटवारा होगा और राजशाही वाले राज्यों को भारत और पाकिस्तान में से किसी को चुनने का विकल्प मिलेगा. बंबई या बिहार में किसी भी तरह के जनमत की बात थी ही नहीं.

इसलिए जब महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर का विलय भारत में किया, तो फिर किसी शंका के लिए कोई जगह बची ही नहीं. लेकिन यहां एक रोड़ा था. अधिग्रहण को स्वीकार किया जाना था. उसी वक्त आत्मनिर्णय की बात को घुसाया गया. 27 अक्टूबर 1947 को अधिग्रहण को स्वीकार करते हुए लार्ड लुइस माउंटबेटेन ने महाराजा हरि सिंह को उसी तारीख को एक पत्र लिखा. पत्र में लिखा था कि आपके द्वारा उल्लेखित विशेष परिस्थितियों में मेरी सरकार, भारत में कश्मीर के विलय को स्वीकारती है. यदि किसी राज्य का अधिग्रहण विवादित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में अधिग्रहण के सवाल पर निर्णय राज्य के लोगों की इच्छा के आधार पर लिया जाएगा. इसलिए मेरी सरकार चाहती है कि जैसे ही कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य हो और आक्रमणकारी बाहर कर दिए जाएं, तब राज्य के अधिग्रहण के सवाल को लोगों की राय से सुलझाया जाना चाहिए.

इसके कुछ दिनों बाद (2 नवंबर 1947) को श्री नेहरू ने एक प्रसारण में गवर्नर जनरल के आश्वासन को स्पष्ट शब्दों में रेखांकित किया. इसमें उन्होंने कहा है कि-

हमने इस अधिग्रहण को स्वीकार करने का निर्णय लिया है और हवाई जहाज से सेना को भेजा है. लेकिन हमने एक शर्त रखी है कि शांति-व्यवस्था कायम होने के बाद अधिग्रहण पर कश्मीर के लोगों द्वारा विचार किया जाएगा. हम संकट की स्थिति में और कश्मीरी लोगों को सुने बिना इसको अंतिम रूप नहीं देना चाहते हैं. आखिरकार, कश्मीरियों को ही निर्णय लेना है. मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी यह नीति है कि जहां कहीं भी किसी राज्य के अधिग्रहण को लेकर विवाद हो, वहां राज्य के लोगों को निर्णय लेना है. इसीलिए हमने कश्मीर के अधिग्रहण के दस्तावेज में इस शर्त को डाल दिया.

बाद में, इसी प्रसारण में प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने यहां स्पष्ट किया कि-

हमने साफ कर दिया है कि कश्मीर के भाग्य का फैसला कश्मीर के लोगों को करना है. हमारे इस वादे का समर्थन महाराजा ने भी किया है और यह वादा न सिर्फ कश्मीरियों, बल्कि पूरी दुनिया से है. हम इससे पीछे नहीं हट सकते और न ही हटेंगे. हम शांति व्यवस्था बहाल होने के बाद यूएन जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था की निगरानी में जनमत संग्रह के लिए तैयार हैं. हम जनता के निर्णय को स्वीकार करेंगे. इससे अधिक संतोषजनक और न्याययुक्त क्या बात होगी?

शीशे की तरह साफ इस स्थिति को देखने के बाद आज यह देख कर आश्चर्य होता है कि कैसे ये लोग इस मसले पर उत्तेजना दिखा रहे हैं.

बाद में यह कहा गया कि अधिग्रहण में जो शर्त जोड़ी गई थी, उसका पालन हुआ. कैसे, जब 1956 में कश्मीर की संविधान सभा ने एक संविधान को अपनाया, जिसमें यह कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और रहेगा. यह सब कुछ शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के तीन साल बाद हुआ. लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान सभा के निर्णय को जनमत संग्रह के बराबर नहीं माना जा सकता है, जिसकी बात खुद प्रधानमंत्री ने की थी.

महाराजा की ओर से कानून के तहत अधिग्रहण होने के बाद, शेख अब्दुल्ला और नेशनल कांफ्रेंस ने इस अधिग्रहण को स्वीकार कर लिया था. ये सब निर्विवाद था, लेकिन अभी भी अधिग्रहण में जोड़ी गई शर्त को प्रभाव में लाया जाना बाकी था. कश्मीर के लोगों की भावना की जगह खुद शेख अब्दुल्ला या नेशनल कांफ्रेंस नहीं ले सकती.

एक दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि पाकिस्तान ने एसईएटीओ और सीईएनटीओ ज्वॉयन कर लिया था और अमेरिका की तरफ से उसे भारी मात्रा में हथियार की आपूर्ति की गई और बाकी घटनाओं की वजह से स्थिति बदल गई और ऐसे में जनमत संग्रह की पेशकश ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकती थी. लेकिन यह भुला दिया गया था कि वह वादा पाकिस्तान से नहीं, बल्कि कश्मीर के लोगों से किया गया था. पाकिस्तान की गलती के लिए कश्मीर को सजा नहीं दी जा सकती है.

इन सब बातों से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एक सही और रचनात्मक तरीका यही होगा कि कश्मीरियों को आत्मनिर्णय के अधिकार से वंचित न रखा जाए या ये कहा जाए कि आपने अपने आत्मनिर्णय के अधिकार का इस्तेमाल कर लिया है. इसकी जगह तार्किक रूप से ये बताना चाहिए कि आज के संदर्भ में इस अधिकार का इस्तेमाल कैसे अव्यावहारिक है.

निम्नलिखित चार तथ्यों को सामने रखा जाना चाहिए. कैसे पाकिस्तान ने अतिक्रमण किया हुआ है और वह इसे खाली भी नहीं करना चाहता, जनमत संग्रह का गंभीर असर भारत और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों पर पड़ सकता है, जनमत संग्रह से आगे जम्मू और कश्मीर राज्य की अखंडता पर असर पड़ सकता है और इस सब की वजह से भारत के डिफेंस (रक्षा) पर गंभीर असर हो सकते हैं. शेख अब्दुल्ला या कोई भी कश्मीरी नेता इन तथ्यों को खारिज नहीं कर सकते क्योंकि वे भी भारत की भलाई ही चाहते हैं.

इसलिए मेरा विनम्र आग्रह है कि अधिग्रहण अंतिम और अटल है, इसे लेकर चल रहे इस गरमा-गरम बहस को किनारे रखिए. शेख अब्दुल्ला के साथ बैठिए व्यावहारिक रास्ता तलाशिए. यदि हम यह समझते हैं कि अंतिम रास्ता यही है कि शेख अब्दुल्ला भी इस अधिग्रहण को अंतिम और अटल मान लें, तब तो फिर हमें उन्हें जेल भेजना पड़ेगा. लेकिन एक आपसी सहमति वाला रास्ता तलाशना है, तो किसी को भी अपनी पोजिशन छोड़ने की जरूरत नहीं है. सबके लिए महत्वपूर्ण यह समझना है कि सिर्फ अपने पोजिशन से चिपके रहने से रास्ता नहीं निकलने वाला है. हम कितना भी कह लें कि अधिग्रहण अंतिम और अटल है, दुनिया इसे नहीं स्वीकारती. आजाद कश्मीर अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है, सीजफायर लाइन अभी भी है, दोनों तरफ की सेनाएं आमने-सामने हैं. भारत और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक डर के साये में जी रहे हैं. कश्मीर में असंतोष है इसलिए भविष्य में हम अपने इस रुख से क्या हासिल कर लेंगे या अब तक हमने क्या हासिल किया है? दूसरी तरफ शेख अब्दुल्ला लगातार आत्म निर्णय के अधिकार की बात कर रहे हैं और हालात इसकी मंजूरी नहीं देती.

इसलिए हर किसी को अपने पोजिशन पर बने रहते हुए एक व्यावहारिक रास्ता तलाशना चाहिए. हमें याद रखना चाहिए कि अल्मेस लोरेन में तीन जनमत संग्रह हुए थे और आज यह कहां है, इसकी फिक्र कोई नहीं करता.

मैं नहीं सोचता कि किसी को भी मालूम है कि समाधान क्या हो सकता है. फिर भी कुछ सकारात्मक बातें कही जा सकती हैं. पहला तो ये कि हरेक पक्ष के मन में समाधान तलाशने की एक ईमानदार इच्छा होनी चाहिए. दूसरा, जैसा कि एक अंग्रेज राजनेता ने कहा है कि कुछ भी व्यवस्थित नहीं हुआ है, अगर वह सही से व्यवस्थित नहीं किया गया है, को याद रखना चाहिए. जाहिर है, यह जानना आसान नहीं है कि इस उलझे हुए मुद्दे का सही समाधान क्या है, फिर भी यह हरेक पक्ष को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए. इसलिए, समाधान ऐसा हो, जो भारत, कश्मीर के लोगों और पाकिस्तान को भी संतुष्ट करने वाला हो.

कश्मीर समाधान के संदर्भ में शेख अब्दुल्ला का भारत-पाक की सहमति पर जोर देने से जनता के बीच गुस्सा पनपा है और जनता यह मानने लगी है कि शेख का झुकाव पाकिस्तान की तरफ है. ऐसा मानना गलत है. दरअसल, शेख अब्दुल्ला यह सोचते हैं कि अगर पाकिस्तान को इस मसले में पार्टी नहीं बनाया गया, तो इसका समाधान निकालना मुश्किल है. कश्मीर का सवाल ही पाकिस्तान की तरफ से आया है और यह भारत ही है, जिसने यूएन में पाकिस्तान को पार्टी बनाया. इसके अलावा, शेख अब्दुल्ला यह भी मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का भविष्य इस पर भी निर्भर करता है कि वे दोनों दोस्त हैं या दुश्मन.

कश्मीर समाधान के संदर्भ में शेख अब्दुल्ला का भारत-पाक की सहमति पर जोर देने से जनता के बीच गुस्सा पनपा है और जनता यह मानने लगी है कि शेख का झुकाव पाकिस्तान की तरफ है. ऐसा मानना गलत है. दरअसल, शेख अब्दुल्ला यह सोचते हैं कि अगर पाकिस्तान को इस मसले में पार्टी नहीं बनाया गया, तो इसका समाधान निकालना मुश्किल है. कश्मीर का सवाल ही पाकिस्तान की तरफ से आया है और यह भारत ही है, जिसने यूएन में पाकिस्तान को पार्टी बनाया. इसके अलावा, शेख अब्दुल्ला यह भी मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का भविष्य इस पर भी निर्भर करता है कि वे दोनों दोस्त हैं या दुश्मन.

यह एक ऐसा विचार है, जिस पर देश में ज्यादा विरोध नहीं होगा और इसे प्रधानमंत्री का भी समर्थन हासिल है. लोकसभा में एक साहसिक और स्टेट्समैन जैसे भाषण में, (विदेश मामलों पर चल रही एक बहस के जवाब में) श्री नेहरू ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान नजदीक आएंगे, यहां तक कि संवैधानिक तरीके से भी. लेकिन इससे पाकिस्तानी प्राधिकारी वर्ग नाराज होगा. इसलिए, वे खुद ही इस बात की घोषणा करेंगे कि हमारे समक्ष शांति से जीने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. यह भाषण उस वक्त दिया गया था, जब देश गहन सांप्रदायिक भावना से गुजर रहा था. ऐसे में यह भाषण देना बहुत ही साहस का काम था.

दोनों देशों के बीच संवैधानिक संपर्क की जो बात प्रधानमंत्री ने की, वह आज के संदर्भ में काफी दिलचस्प है. यह नहीं मानना चाहिए कि पाकिस्तान हमेशा ऐसे विचार को नकारता ही रहेगा. आखिरकार, हर देश अपने आर्थिक मसले और सुरक्षा को लेकर सबसे अधिक चिंतित रहता है. क्या इसमें कोई शक है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक संवैधानिक संपर्क से इन दोनों देशों को सुरक्षा और आर्थिक तरक्की की गारंटी नहीं मिलेगी? इसके अलावा, शेख अब्दुल्ला भी इसी लाइन पर सोच रहे हैं, जिससे इस स्थिति के लिए एक नई आशा जागती है. इसलिए अगर सख़्त पोजिशन को छोड़ दिया जाए, तो एक ऐसे सही समाधान निकलने की उम्मीद की जा सकती है, जिससे भारत, पाकिस्तान और कश्मीर के लोग भी संतुष्ट हों. एक स्टेट्समैन को यही काम करना है.

अपनी बात खत्म करने से पहले मैं कश्मीर के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता की ओर भी नज़र घुमाना चाहता हूं. बाकी चीजों के अलावा, कश्मीर हमारे धर्मनिरपेक्ष मूल्य के लिए भी एक बेहतरीन उदाहरण है. यही कश्मीर, जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है, हिन्दू सांप्रदायिकता की घृणित तरक्की का निमित्त बना. यह सब राष्ट्रवाद की आड़ में हो रहा है. भारत एक हिंदू बहुल देश है और ऐसे में भारतीय राष्ट्रवाद की आड़ में हिन्दू सांप्रदायिकता का उभार कठिन नहीं है. इसलिए, यह अत्यंत आवश्यक है कि जो भी लोग धर्मनिरपेक्षता में यकीन रखते हैं, वे इसकी (धर्मनिरपेक्षता) रक्षा करें. कश्मीर भारतीय धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण क्यों है और इसका क्या अर्थ है? मैं समझता हूं कि भारतीय लोगों ने अपने गैर सांप्रदायिक नजरिए का सबूत दिया है. तभी कश्मीर के मुस्लिम, जो वहां बहुमत में हैं, ने पाकिस्तान (मुस्लिम बहुल) के बजाए भारत जैसे देश में शामिल होना पसंद किया, जो हिन्दू बहुल होते हुए भी धर्मनिरपेक्ष देश है. लेकिन कश्मीर में मुस्लिमों को बलपूर्वक भारत के साथ रखना क्या हमारी धर्मनिरपेक्षता है? और आज भी एक बड़ी मानसिकता ऐसी है, जो अपने राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष आधार की रक्षा के लिए कश्मीर को भारतीय संघ के भीतर बनाए रखना चाहते हैं, अगर जरूरी हो, तो बलपूर्वक भी.

इसलिए, मैं प्रधानमंत्री से गंभीरता से यह अनुरोध करता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य कांग्रेसी नेता सावधानीपूर्वक अपनी पार्टी में पनप रही इस कैंसरकारी प्रक्रिया की ओर ध्यान दें. जो स्थितियां बन रही हैं, उसके हिसाब से जनसंघ और कांग्रेस दोनों एक ही तरह के हो गए हैं. कुल मिलाकर लोगों की सोच सही है. अगर नेहरू सही दिशा में साहसिक नेतृत्व देने के लिए तैयार हैं, तो जनता उनका साथ देगी. अगर इस तरह की कोई घटना नहीं घटती है, तो मुझे भय है कि भारत के सेकुलर बुनियाद को एक बड़ी क्षति पहुंचेगी.■

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

रक्षा मंत्रालय ख़ुद संभालें प्रधानमंत्री

क्या हम ज़मीन चाहते हैं? क्या हमें कश्मीर में और अधिक भूमि की जरूरत है? हमारे देश में पर्याप्त जमीन है. हम एक नैतिक रुख अपनाना चाहते हैं. भारत दुनिया में एक उभरती हुई शक्ति है, जबकि पाकिस्तान नहीं है. इस अंतर को समझना पड़ेगा. दुनिया भारत की ओर साझेदारी व आर्थिक सहयोग के लिए देख रही है. लिहाज़ा हमें अपनी ताक़त और ज़िम्मेदारी दिखाते हुए नपी-तुली प्रतिक्रिया देनी होगी, न कि रक्षा मंत्री की तरह गैरजिम्मेदराना बयान देकर, जो वे हर दूसरे दिन देते रहते हैं. आज उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि ज़ाहिर है उड़ी में कुछ न कुछ गलती हुई है. यह किस तरह का बयान है? एक स्कूली बच्चा भी इस पर हंसेगा. हमारी शुभकामनाएं प्रधानमंत्री के साथ हैं, वे मामले को अपने हाथ में लें.

कश्मीर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है. इस संबंध में विभिन्न मोर्चों पर क़दम उठाने की ज़रूरत है. सबसे पहले तो ये कि वहां ज़मीनी स्तर पर जो हो रहा है, वह किसी तरह स्वीकार्य नहीं है. पहले उन्होंने पठानकोट की घटना अंजाम दी, फिर उड़ी में हमला किया. हमारे सैन्य शिविरों पर पाकिस्तान के हमलों से हमारी कमजोर रक्षा तैयारियों का पता चलता है. यह कहना मुश्किल है कि हमारा मनोबल नीचा है या असल समस्या पर नेतृत्व से चूक हो रही है. लेकिन जो बात स्पष्ट है, वह यह कि मनोहर परिकर एक बहुत अकुशल रक्षा मंत्री साबित हुए हैं. यदि अपनी पार्टी को किरकिरी से बचाना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी को इस मंत्रालय को खुद अपने हाथों में ले लेना चाहिए. हालांकि यह भी बेहतर होगा कि किसी ऐसे मज़बूत व्यक्ति को यह मंत्रालय सौंपा जाए, जो भारत और उसकी राजनीति की बेहतर समझ रखता हो. मनोहर परिकर गोवा के लिए बेहतर हैं, जो भारत का एक छोटा सा हिस्सा है. उन्हें फिर से गोवा का मुख्यमंत्री बना देना एक बेहतर फैसला होगा. गोवा में चुनाव होने वाले हैं और यह उनकी पार्टी के लिए एक बुद्धिमत्तापूर्ण कदम होगा. लेकिन मैं यहां बीजेपी की संभावनाओं पर बात नहीं कर रहा हूं. रक्षा मंत्रालय को निश्चित रूप से एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है. या तो यह मंत्रालय एक मजबूत वैकल्पिक नेता को दिया जाए या स्वयं प्रधानमंत्री इसे संभालें. सुरक्षा बलों के तीनों प्रमुख अपनी अच्छी तैयारी और उच्च मनोबल के लिए जाने जाते हैं. जाहिर है, पिछले दो वर्षों में कुछ न कुछ गलत ज़रूर हुआ तभी तो हम उन्हें इस हालत में पा रहे हैं. जितनी जल्दी इस प्रवृत्ति को ठीक किया जाए, उतना ही बेहतर होगा.

अगला सवाल कश्मीर की वास्तविक समस्या का है. समस्या दो सतहों पर है, जिनमें से एक है कश्मीर में पाकिस्तान का हस्तक्षेप. नियंत्रण रेखा की अच्छी तरह से निगरानी की जाए तो इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है. नियंत्रण रेखा के अपने क्षेत्र में वे क्या करते हैं, यह उनका मुद्दा है. नियंत्रण रेखा के हमारे क्षेत्र में युवाओं में काफी गुस्सा है. केंद्र सरकार ने लगातार उन्हें नहीं समझने की गलती की है. हर कोई अपने साथ न्यायपूर्ण व्यवहार की इच्छा रखता है. उमर अब्दुल्ला जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि कश्मीर का भारत में विलय (मर्जर) नहीं हुआ था, बल्कि भारत के साथ उसका केवल एक्सेशन हुआ था. इस बयान के बाद पूरा सत्ता केंद्र उनके ऊपर ऐसे हमलावर हुआ, जैसे उन्होंने कोई अपराध किया हो. यहां तक कि इसके बाद उन्होंने खुद अपने बयान की गंभीरता को कम करने की कोशिश की. हालांकि उन्होंने जो भी कहा, वह सच था और यही तथ्यात्मक स्थिति भी है. दूसरी देशी रियासतें भारत में पहले सम्मिलित (एक्सीड) हुई थीं, बाद में उनका विलय (मर्जर) हुआ था, जबकि जम्मू-कश्मीर भारत में सम्मिलित हुआ, लेकिन उसका विलय कभी नहीं हुआ. यह कुछ शर्तों के साथ भारत में शामिल हुआ था. ये शर्तें संविधान के आर्टिकल 370 में दर्ज हैं. आरएसएस और भाजपा समेत उसके सहयोगी इस विडंबना को नहीं समझ पा रहे हैं कि 370 की समाप्ति की मांग कर वे कश्मीर पर अपने कानूनी दावे को छोड़ना चाहते हैं. दरअसल पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान बिना किसी कानूनी अधिकार के कब्ज़ा किए हुए है. यदि आप आर्टिकल 370 समाप्त कर देंगे तो आपकी स्थिति भी पाकिस्तान जैसी हो जाएगी. दूसरी तरफ यदि आर्टिकल 370 को सख्ती से लागू किया जाता है तो आपके क्षेत्र वाले कश्मीर पर आपका दावा स्थापित होगा, साथ ही पाक अधिकृत कश्मीर पर भी आपका दावा मज़बूत हो जाएगा. लिहाज़ा यह वक़्त की ज़रूरत है कि कश्मीर के लोगों को आश्वस्त किया जाए कि 370 उस वक्त तक लागू रहेगा, जब तक कश्मीर की जनता चाहेगी.

दरअसल कश्मीर समस्या के समाधान के लिए जितेन्द्र सिंह पीएमओ में राज्य मंत्री पद के लिए उचित नहीं हैं. चूंकि वे भाजपा से जुड़े हैं इसलिए उन्हें कोई और मंत्रालय दे देना चाहिए और कश्मीर मामले पर उन्हें अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए. वो कोई अच्छा काम नहीं कर सकते. कश्मीर में हमारी स्थिति कानूनी, नैतिक और राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो जाएगी. दरअसल हम उन लोगों की बातों को साबित करेंगे, जो कहते हैं कि हमने सैन्य बल से कश्मीर को अपने पास रखा हुआ है. इस धारणा को दूर करने के लिए और कश्मीर में आपकी मौजूदगी कानूनी, नैतिक और राजनीतिक रूप से करने के लिए यह साबित करना होगा कि केंद्र सरकार और महबूबा सरकार 370 को लेकर प्रतिबद्ध हैं.

जब 1975 में शेख अब्दुल्ला दोबारा मुख्यमंत्री बने थे, तब एक समझौता हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि 1953 (जब शेख साहब गिरफ्तार हुए थे) और 1975 के बीच जो भी कानून कश्मीर में लागू किये गए, उनकी समीक्षा की जाएगी. लेकिन यह कभी नहीं हो सकी. यह समीक्षा अब भी हो सकती है. जम्मू और कश्मीर असेंबली 1953 और 1975 के बीच राज्य में लागू सभी कानूनों की समीक्षा कर सकती है और जो कानून वे नहीं चाहते, उन्हें केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर से हटा सकती है. राज्य का अपना चुनाव आयोग हो सकता है. आर्टिकल 370 के तहत एक तर्कसंगत स्वायत्तता देने में कोई बुराई नहीं है. आर्टिकल 370 के तहत राज्य की रक्षा, विदेश नीति और संचार की ज़िम्मेदारी केंद्र की है, इसका मतलब है कि कश्मीर भारत का अंग रहेगा. स्थानीय रूप से वहां के लोग और अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं. तो इसमें आपत्ति क्या है? दूसरी तरफ इस आरोप में सच्चाई ज़रूर है कि आज कश्मीर में किसी दूसरे राज्य से कम स्वायत्तता है. यहां के मामलों में सेना की बड़ी भूमिका है जो देश के किसी दूसरे हिस्से में नहीं है. लिहाज़ा सरकार कश्मीर को ताक़त के बल पर अपने साथ रखने की धारणा को समाप्त करने के लिए क़दम उठाती है तो यह भारत के लिए अच्छा होगा.

तीसरा हिस्सा पाकिस्तान का है. उनके प्रधानमंत्री ने संयुक्तराष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कहा कि वे शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी सेना के दबाव में उन्होंने यह भी कहा कि दक्षिण एशिया में तब तक शांति नहीं आ सकती, जब तक कश्मीर समस्या का समाधान नहीं हो जाता. यह

> हमारी सेना एवं सशस्त्र बल इस धारणा को दूर कर सकते हैं. आखिरकार, भारत और पाकिस्तान की सेनाओं का एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति एक ही है. स्वतंत्रता के बाद वे अलग हुए थे. वे एक दूसरे की क्षमताओं, एक दूसरे की मानसिक शक्तियों और कमजोरियों को भली-भांति समझते हैं. लेकिन मुझे वर्तमान स्थिति ठीक नहीं लग रही है. सरकार ऐसे बात कर रही है, जैसे सीमा समस्या, पठानकोट, उड़ी की घटनाएं सेना के मामले हैं. यदि सेना मनोहर परिकर जैसे व्यक्ति के नेतृत्व में है, तो देश को भगवान ही बचाए!

क्या बकवास है! कश्मीर इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि जिसकी वजह से दक्षिण एशिया में शांति नहीं स्थापित हो सकती. दरअसल यह उनकी गलत अवधारणा है. भारत की सेना ठान ले, तो बल का प्रयोग कर पाक अधिकृत कश्मीर हासिल किया जा सकता है. लेकिन दोनों तरफ के परमाणु हथियारों को देखते हुए यह एक बेहतर समाधान नहीं होगा. लेकिन पाकिस्तान की परमाणु क्षमता को हकीकत से अधिक प्रचारित किया गया है. ऐसा कहकर मैं जंग का सुझाव नहीं दे रहा हूं या किसी परमाणु युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं. हर्गिज नहीं! लेकिन हमारी अच्छाइयों, न्यायप्रियता और बातचीत जारी रखने की इच्छा को हमारी कमजोरी नहीं समझी जानी चाहिए. पाकिस्तान अपने चेहरे पर कई चेहरे पहनता है. कठोर रुख अपनाना होता है तो सेना बात करती है, दोस्ताना माहौल बनाना हो तो लोकतांत्रिक दल बात करते हैं. आतंकवाद फैलाना होता है तो कुछ मौलाना या हाफिज सईद जैसे कुछ आतंकवादी बात करते हैं. हमें एक ऐसी रणनीति बनानी होगी, ताकि इन सभी चेहरों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा सके. पाकिस्तान के साथ हमें अपने राजनयिक संबंध बरक़रार रखने चाहिए. लेकिन हमारे आपसी वार्ता के प्रस्ताव को वे यह समझने की भूल करते हैं कि हम डर गए हैं. प्रधानमंत्री को सेना के कमांडरों के साथ बैठक करनी चाहिए. हमारी सेना एवं सशस्त्र बल इस धारणा को दूर कर सकते हैं. आखिरकार, भारत और पाकिस्तान की सेनाओं का एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति एक ही है. स्वतंत्रता के बाद वे अलग हुए थे. वे एक दूसरे की क्षमताओं, एक दूसरे की मानसिक शक्तियों और कमजोरियों को भली-भांति समझते हैं. लेकिन मुझे वर्तमान स्थिति ठीक नहीं लग रही है. सरकार ऐसे बात कर रही है, जैसे सीमा समस्या, पठानकोट, उड़ी की घटनाएं सेना के मामले हैं. यदि सेना मनोहर परिकर जैसे व्यक्ति के नेतृत्व में है, तो देश को भगवान ही बचाए!

दूसरी ओर कश्मीर में छात्र न केवल सत्तारूढ़ पार्टी, बल्कि विपक्ष से भी बातचीत करने को तैयार नहीं हैं. यह बहुत दुख की बात है. सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अपना सा मुंह लेकर रह गया. कोई न कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए. सरकार को नागरिक समाज का प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए, जिसमें कुलदीप नैय्यर, राम जेठमलानी जैसे लोग शामिल हों और जिनसे वे बच्चे बात करें. जब तक कश्मीर समस्या को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, समस्या का हल नहीं निकल सकता. बहरहाल जिस तरह आरएसएस और भाजपा इस समस्या को देखते हैं, समस्या इसमें भी है. वे अपनी जुबान से तो नहीं कहते, लेकिन वे चाहते हैं कि कश्मीर को हड़प लिए जाए, जो उपनिवेशवाद है. आधुनिक भारत में यह नहीं होता. मैं नागरिक समाज के ऐसे लोगों से मिला हूं, जो उनके विचार के हैं, वे लोगों को मारने में विश्वास करते हैं.

क्या हम ज़मीन चाहते हैं? क्या हमें कश्मीर में और अधिक भूमि की जरूरत है? हमारे देश में पर्याप्त जमीन है. हम एक नैतिक रुख अपनाना चाहते हैं. भारत दुनिया में एक उभरती हुई शक्ति है, जबकि पाकिस्तान नहीं है. इस अंतर को समझना पड़ेगा. दुनिया भारत की ओर साझेदारी व आर्थिक सहयोग के लिए देख रही है. लिहाज़ा हमें अपनी ताक़त और ज़िम्मेदारी दिखाते हुए नपी-तुली प्रतिक्रिया देनी होगी, न कि रक्षा मंत्री की तरह गैरजिम्मेदराना बयान देकर, जो वे हर दूसरे दिन देते रहते हैं. आज उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि ज़ाहिर है उड़ी में कुछ न कुछ गलती हुई है. यह किस तरह का बयान है? एक स्कूली बच्चा भी इस पर हंसेगा. हमारी शुभकामनाएं प्रधानमंत्री के साथ हैं, वे मामले को अपने हाथ में लें. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

अशांत कश्मीर का हल क्या है

हारून रेशी ने अपनी कवर स्टोरी कश्मीर से खाली हाथ लौटे नाकाम सिपाही (19 सितंबर- 25 सितंबर 2016) में जम्मू-कश्मीर से लौटे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की चर्चा की है. हारून रेशी ने सही कहा कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जम्मू-कश्मीर में शांति बहाली की दिशा में कोई कदम उठाने में नाकाम रहा. केंद्र सरकार का कहना है कि कश्मीर में जो स्थिति है उसके लिए पाकिस्तान ज़िम्मेदार है और सरकार का दावा है कि उसने यहां पर अशांति फैलाने के लिए करोड़ों रुपये भेजे हैं. लेकिन सरकार के पास रॉ जैसी खुफिया एजेंसियां हैं, लेकिन सरकार असहाय नजर आ रही है, क्योंकि वह इसका अभी कोई सबूत पेश नहीं कर सकी. लेकिन यह खबरें जरूर आई हैं कि पीओके के इटली में रह रहे कुछ लोग कश्मीर में हिंसा भड़काने के लिए अलगाववादियों को पैसा दे रहे हैं. लेकिन अगर यह रकम कश्मीर आई और उपद्रवियों में बांटी गई, तो अब तक सरकार ने किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया. सरकार कश्मीर में अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए झूठ बोल रही है. अब तक इस तरह के कई प्रतिनिधिमंडल कश्मीर जा चुके हैं और उसने अपनी रिपोर्ट अब तक केंद्र में रही सरकारों को सौंपा है. लेकिन इसके नतीजे में न तो कश्मीर का मसला हल हो सका और न ही कश्मीर में स्थायी शांति स्थापित हो सकी.

-अशरफ अली, *उन्नाव, उत्तर प्रदेश.*

पुलिस का अमानवीय चेहरा

आलेख-टीआई परिवार के साथ पुलिस की बेरहमी (19 सितंबर-25 सितंबर 2016) पढ़ा. पुलिस के द्वारा पुलिस के परिवार की पिटाई की खबर पढ़कर आश्चर्य हुआ. अभी तक यही खबरें आ रही थीं कि पुलिस ने किसी व्यक्ति या किसी महिला की बेरहमी से पिटाई की. पुलिस के जुल्म की कहानी कोई पुरानी नहीं है और हमेशा से पुलिस आम जनता पर कहर ढाती रही है. पुलिस के द्वारा महिलाओं को इतनी बुरी तरह से पीटना कहां का न्याय है? टीआई की पत्नी और बेटी के साथ

इतनी निर्दयता, तो असहाय जनता के साथ क्या होता होगा यह देखकर पुलिस की सच्चाई सामने आती है. पुलिस आम जनता की रक्षा के लिए होती है. अगर जनता के रक्षक की जगह भक्षक बन जाए, तो आखिर जनता हो रहे जुल्म के खिलाफ कहां आवाज उठाएगी?

- मनीष चौहान, *सतना, मध्य प्रदेश.*

कश्मीरियों की मांग

कमल मोरारका ने अपने आलेख शिमला समझौता और इंदिरा-शेख समझौता ही कश्मीर समस्या का समाधान है (19 सितंबर- 25 सितंबर 2016) में बिलकुल सही कहा है कि वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच एक समझौता हुआ था. कांग्रेस ने बहुमत होने के बावजूद शेख को सरकार की बागडोर सौंप दी थी. इस समझौते को शेख-इंदिरा समझौते के नाम से जाना जाता है. इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि कश्मीर में चुनाव द्वारा सरकार बनेगी. साथ ही 1953 और 1975 के बीच कश्मीर में लाए गए सभी कानूनों पर कश्मीर सरकार द्वारा विधानसभा में समीक्षा होगी और दिल्ली के साथ विचार-विमर्श के बाद उसपर उचित कार्रवाई होगी. कश्मीर घाटी में अशांति है. भारतीय सेना या भारत सरकार यह कह सकती है कि पाकिस्तान यहां अशांति फैला रहा है. लेकिन जब तक आप की अपनी आबादी, अपने लोग नाराज न हों, कोई दूसरा उसका फायदा नहीं उठा सकता. इसलिए कश्मीरियों से बात करने और उनकी समस्याओं को दूर करने की जरूरत है.

-प्रभाकर कुमार, *मुंगेर, बिहार.*

वादे पर अमल नहीं हो पाया

जब तोप मुकाबिल हो-कश्मीर में विश्वास का संकट है (19 सितंबर- 25 सितंबर 2016) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया कश्मीरियों के मन में भारतीय संसद के प्रतिनिधिमंडल के प्रति अगर गुस्सा है तो इसमें नाजायज क्या है? क्योंकि अब तक कई प्रतिनिधमंडल कश्मीर गए और कई वादे करके आए, लेकिन उन वादों को आज तक पूरा नहीं किया गया. कश्मीर के लोगों में अगर भारत के प्रति गुस्सा है कि उनसे जितने वादे किये गये उनपर कोई अमल नहीं हुआ तो इसमें नाजायज क्या है? अपनी मांग उठाना क्या देशद्रोह है, लेकिन वे बातें सरकार में बैठे लोगों को समझ में नहीं आती है, जैसे पिछली सरकार में बैठे लोगों को समझ नहीं आई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि कश्मीरियों से बात करें और उनके दर्द को समझें. प्रधानमंत्री को चाहिए कि कश्मीरियों से अब तक जितने वादे किए गए हैं उनको पूरा करें जिससे उनके अंदर के विश्वास को जीता जा सके.

- गौरव गुप्ता, *दानापुर, बिहार.*

वक़्फ़ की ज़मीन पर कब्जा

वक्फ को मुसलमान ही डुबा रहे हैं (19 सितंबर- 25 सितंबर 2016) शीर्षक से लिखे अपने आलेख में लेखक एयू आसिफ ने बताया है कि किस प्रकार मुस्लिम धर्मगुरु ही वक्फ की जमीन पर कब्जा जमाया हुए हैं और उस जमीन का फायदा उठा रहे हैं. वक्फ की जायदाद आम लोगों और गरीबों की भलाई के लिए एक बेहतरीन और कारगर जरिया होती है. भारत में कुल 60 लाख एकड़ जमीन पर 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ जायदाद है. इन जायदादों की व्यवस्था अगर बेहतर तरीके से की जाए तो विशषज्ञों का कहना है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के हर क्षेत्र के पिछड़ेपन को आसानी से दूर किया जा सकता है. लेकिन इस पर मुस्लिमों का हितैषी बताने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ही कब्जा जमाया हुआ है. बार-बार मुस्लिमों की आवाज उठाने वाले धर्मगुरु वक्फ की जमीन पर कब्जे को लेकर कुछ भी नहीं बोलते.

-रमेश शर्मा, *अलीगढ़, उत्तर प्रदेश.*

पाठकों से...

सुधी पाठक, चौथी दुनिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स-आलेखों पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं. आप अपनी बेबाक राय, सुझाव हमें डाक/ईमेल द्वारा भेज सकते हैं. आप हमारी आंख-कान-नाक हैं. जहां तक आपकी पहुंच है, वहां तक हमारी नज़र जाना संभव नहीं है. अख़बार को बेहतर बनाने में आपके सुझाव-विचार हमारी मदद करेंगे. हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11,
गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)-201301, उत्तर प्रदेश.
Email: feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

प्रधानमंत्री जी, कश्मीर और पाकिस्तान दो अलग सवाल हैं

भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपनी सीमा पर है. अधिकतर वे लोग जो फेसबुक पर हैं, वे सभी चाहते हैं कि पाकिस्तान पर फौरन हमला कर दिया जाए और उसे सबक सिखाया जाए. सबक सिखाने का मतलब पाकिस्तान का बड़ा भू–भाग, जहां आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं, उसे भारतीय सीमा में मिलाने का फैसला लिया जाए. सरकार के लिए भी एक चिंता की बात है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनाव अभियान के दौरान देश से ये वादा कर चुके हैं कि कमजोर सरकार की वजह से पाकिस्तान से हमेशा मात मिलती रहती है और अगर मजबूत सरकार होगी या जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे, उस समय पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुछ करने की जुर्रत नहीं कर पाएगा. आज वे सारे वादे हवा में कपूर की तरह काफूर हो गए हैं इसलिए शायद सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि छोटा ही सही, लेकिन भारत की सशस्त्र प्रतिक्रिया पाकिस्तान को दी जाए.

कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिनमें हमारे देश के कुछ संपादक शामिल हैं, उनका ये मानना है कि पाकिस्तान से तो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कश्मीर के लोगों को सबक सिखाया जाए. एक संपादक ने मुझे कहा कि कश्मीर में ठोकना चाहिए. कुछ चैनल लगातार पाकिस्तान से युद्ध की वकालत कर रहे हैं और अगर इनके बस में हो तो बिना एक पल गंवाए ये पाकिस्तान पर हमला कर दें. सोशल मीडिया और चैनल मिलकर देश में युद्ध के प्रति उन्मादी वातावरण बना रहे हैं. यह अलग बात है कि कुछ तो ऐसा है जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है.

कश्मीर का सवाल, कश्मीर की समस्याएं और कश्मीर की तकलीफ अलग है और पाकिस्तान की समस्या अलग है और पाकिस्तान के व्यवहार का सवाल अलग है. पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वहां की कमजोर सरकार भारत के खिलाफ अपनी धरती से होने वाले आतंकवादी अभियानों को रोक नहीं पा रही है. शायद राजनीतिक नेतृत्व अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कश्मीर के सवाल को जितना उलझा सकता हो, उलझाने की कोशिश कर रहा है. वहां की सेना कश्मीर के सवाल को लेकर देश में अपनी साख बढ़ाती जा रही है और राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ एक ऐसा माहौल बना रही है, जो यह संदेश दे रहा है कि पाकिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व कभी कश्मीर का सवाल हल नहीं कर सकता.

कश्मीर के लोग पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन वे यह जरूर चाहते हैं कि पाकिस्तान के प्रभाव में या पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर से जुड़े जितने क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी वही मांग मानी जाए, जिसकी मांग वो भारत से कर रहे हैं और पाकिस्तान यही नहीं चाहता. पाकिस्तान अपने अधिकार क्षेत्र में कश्मीर के हिस्सों को किसी भी प्रकार की आजादी देना नहीं चाहता है. उसका उद्देश्य है कि वो भारत के साथ जुड़े कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान में मिला ले और इसलिए वो कश्मीरियों के स्वाभिमान की लड़ाई को बर्बाद करने पर तुला है. कश्मीर से अभी–अभी

पाकिस्तान से आप लड़िए, पाकिस्तान को आप नेस्तनाबूद कीजिए. पाकिस्तान के एजेंटों को पकड़िए और उन्हें कानून के दायरे में लेकर आइए. इसके लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो अंदरूनी तौर पर, रॉ बाहरी तौर पर उनकी मानिए, लेकिन कश्मीर को पाकिस्तान की गतिविधियों से मत जोड़िए. कश्मीर अलग सवाल है.

सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल लौटा है. कुछ स्वतंत्र पत्रकार वहां गए, जिन्होंने लौटकर कश्मीर के हालात को दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में बतलाने की कोशिश की. और तभी पाकिस्तान आधारित आतंकवादी ग्रुपों को लगा कि अगर अभी कुछ न किया गया तो कश्मीर के लोगों की मांग पर अगर भारतीय जनमत बनता है, तो उनका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा. इसलिए उन्होंने उड़ी के सेना के कैंप पर हमला कर दिया और एक जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया.

भारत और पाकिस्तान की सरकारों को ये समझना चाहिए कि क्या वो इतनी गैरजिम्मेदार या इतनी नासमझ हैं कि पचास लोगों के चाल में आकर दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा कर दें. कम से कम मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये विश्वास है कि वैसा गैरजिम्मेदाराना व्यवहार नहीं करेंगे. उन्हें चाहिए कि वे पाकिस्तान पर तत्काल दबाव डालें और नवाज शरीफ से कहें कि अगर वे अपने यहां संचालित होने वाले आतंकवादी समूहों पर नियंत्रण नहीं लगा पाएंगे तो फिर एक महाविनाश की स्थिति हो जाएगी क्योंकि उस समय किसी भी देश का जनमानस अपनी सरकार पर कुछ कदम उठाने के लिए भयानक दबाव बना सकता है. आज पाकिस्तान की सरकार का यह सबसे बड़ा कर्तव्य है कि अगर उसे अपनी सरकार वहां बचाए रखनी है और सेना को सत्ता से दूर रखना है तो आतंकवादी गिरोहों पर लगाम लगाए और उनके खिलाफ जनमत भी बनाए.

भारतीय सेना का गुस्सा जायज है. भारत के लोगों का गुस्सा जायज है. जब मैं कश्मीर की प्रतिक्रिया देखता हूं तो मुझे वो भी वैसी ही दिखाई देती है, जैसी बाकी हिस्सों में प्रतिक्रिया है. लेकिन कुछ सवाल हमारी जांच एजेंसी ने खड़े किए. अंदर के कौन से लोग हैं, जिन्होंने इन आतंकवादियों को सेना के उस कैंप की छोटी से छोटी जानकारी दे दी. कहां हथियार हैं, कहां अधिकारियों के घर हैं, कहां पर जवान सोते हैं और जिस रात ये कांड हुआ, विहार की बटालियन उस जगह पर ट्रांसफर होकर आई थी और उसे मोर्चा संभालना था, वो रात ड्यूटी बदलने की रात थी. शायद वो रात जवानों ने मनोरंजन में काटी हो और बेसुध होकर सो गए हों.

कैंप के आस–पास तार हैं, जिनमें बिजली चलती है और वहां जो सीमा वाली बाड़ है, एलओसी की, उसमें भी बिजली प्रवाहित होती है. इन तारों को काटकर, जिनमें हाई वोल्टेज बिजली का प्रवाह होता है, आतंकवादी अंदर कैसे घुसे या उसी समय बिजली सप्लाई तो बंद नहीं कर दी गई थी, जब वे अंदर घुसे. ये किसने किया? पहले खबर आई कि झेलम द्वारा आतंकवादियों ने सीमा पार किया. फिर खबर आई कि वो तार काटकर घुसे. पास की पहाड़ी पर बैठकर आतंकवादी शक्तिशाली दूरबीन से भारतीय कैंप की सारी गतिविधियां देख रहे थे. अब हम साधारण लोगों के मन में यह सवाल उठना आवश्यक है कि आपने ऐसी जगह अगर कैंप लगाया तो उन चीजों पर अपना निशाना क्यों नहीं साधा जहां से आप पर नजर रखी जा सकती है.

ये सवाल इसलिए मन में उठ रहे हैं क्योंकि हमारे अपने देश के सिस्टम में कहीं न कहीं कोई बड़ी खोट है. ऐसी कमी, जो देश का माथा हमेशा झुकाती है. सेना की कैंप पर हमला करना और हथियारों को नष्ट करना, इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को आग में जला देना, ये अंदर छुपे हुए उनके एजेंट के बिना संभव नहीं है. हम अपने घर को क्यों नहीं ठीक करते हैं?

और तब कुछ जनरलों का, आर्मी के रिटायर जनरल का ये कहना कि हमें पहले अपना घर ठीक करना चाहिए. अपने घर से मतलब कश्मीर को ठीक करना चाहिए. वहां राजनीतिक बातचीत करनी चाहिए. कश्मीर के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए और तब पाकिस्तान से युद्ध के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ये तो समझदार जनरल की प्रतिक्रिया है. देश में हमारी पत्रकार बिरादरी में बहुत से ऐसे नासमझ लोग हैं जिनके घर का कोई आदमी जिंदगी में कभी सेना में नहीं रहा, जिनके घर में कभी सीमा पर मौतें नहीं हुईं, वो इस समय पाकिस्तान से युद्ध के लिए आमादा हैं और एक माहौल बना रहे हैं. गैरजिम्मेदार सिरफिरे हर जगह होते हैं और तब भारत के भूतपूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह का ये बयान याद आता है कि ऐसे फैसले भावना में नहीं लिए जा सकते. ऐसे फैसलों के लिए पूरा विश्लेषण चाहिए. अपनी कमजोरियों को ठीक करना चाहिए और जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई करने का समय सेना पर छोड़ देना चाहिए. लोगों के मन को भड़काने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.

मेरा भी निवेदन है कि पाकिस्तान से आप लड़िए, पाकिस्तान को आप नेस्तनाबूद कीजिए, पाकिस्तान के एजेंटों को पकड़िए और उन्हें कानून के दायरे में लेकर आइए. इसके लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो अंदरूनी तौर पर, रॉ बाहरी तौर पर उनकी मानिए, लेकिन कश्मीर को पाकिस्तान की गतिविधियों से मत जोड़िए. कश्मीर अलग सवाल है. पाकिस्तान अलग सवाल है. कश्मीर के लोग हमारे लोग हैं. पाकिस्तान के आतंकवादी शिविर, आतंकवादी ग्रुप और पाकिस्तान की सरकार उसके साथ अलग तरह का व्यवहार होना चाहिए और वही व्यवहार सरकार को करना चाहिए.

एक आग्रह प्रधानमंत्री से अवश्य है कि कृपा कर अटल विहारी वाजपेयी जी के समय के लोगों से बात कीजिए और उनसे पूछिए कि अटल जी के दिमाग में कश्मीर के सवाल को हल करने के कौन से रास्ते थे? हमने जितना कश्मीर में देखा, उससे समझ में आया कि कश्मीर में बातचीत शुरू करना या कश्मीर के सवाल को हल करने का छोर वहीं कहीं है, जहां अटल विहारी वाजपेयी ने उसको छोड़ दिया था. कश्मीर का हर आदमी अटल विहारी वाजपेयी जी का प्रशंसक है. विश्वास मानिए, प्रधानमंत्री जी आप उन लोगों की राय से हटकर अगर अटल विहारी जी की राय का पालन करेंगे तो आप भी कश्मीर के लोगों के दिल में अपनी जगह बना लेंगे. कश्मीर के लोग आप पर अभी भी बहुत विश्वास करते हैं. ■

editor@chauthiduniya.com

भारत और पाकिस्तान की सरकारों को ये समझना चाहिए कि क्या वो इतनी गैरजिम्मेदार या इतनी नासमझ हैं कि पचास लोगों के चाल में आकर दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा कर दें. कम से कम मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये विश्वास है कि वैसा गैरजिम्मेदाराना व्यवहार नहीं करेंगे. उन्हें चाहिए कि वे पाकिस्तान पर तत्काल दबाव डालें और नवाज शरीफ से कहें कि अगर वे अपने यहां संचालित होने वाले आतंकवादी समूहों पर नियंत्रण नहीं लगा पाएंगे तो फिर एक महाविनाश की स्थिति हो जाएगी क्योंकि उस समय किसी भी देश का जनमानस अपनी सरकार पर कुछ कदम उठाने के लिए भयानक दबाव बना सकता है. आज पाकिस्तान की सरकार का यह सबसे बड़ा कर्तव्य है कि अगर उसे अपनी सरकार वहां बचाए रखनी है और सेना को सत्ता से दूर रखना है तो आतंकवादी गिरोहों पर लगाम लगाए और उनके खिलाफ जनमत भी बनाए.

मत-मतांतर

संश्लेषण ही हमारी परंपरा है

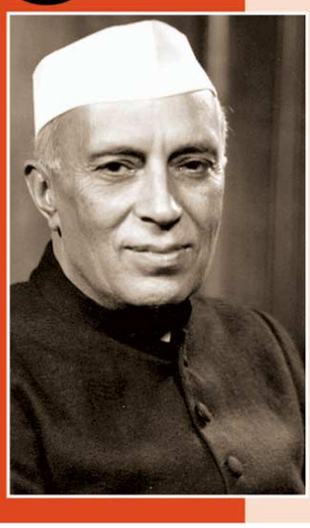

पंडित जवाहरलाल नेहरू

भारत क्या है? यह प्रश्न बार–बार मेरे मन में उठता है. हमारे इतिहास के प्रारंभिक दौर की जानकारी मुझे विस्मय में डाल देती थी. यह एक ऐसी साहसी और उद्यमशील जाति का इतिहास था, जो अन्वेषण की भावना और स्वतंत्र अनुसंधान की तीव्र इच्छा से प्रेरित थी और ज्ञात प्राचीनतम काल में भी एक परिपक्व और सहिष्णु सभ्यता होने का प्रमाण देती थी. जीवन और उसके आनंद व कष्टों को स्वीकार करते हुए यह सभ्यता परम और सार्वभौमिक तत्व की खोज करने वाली थी. उसने महान संस्कृत भाषा का विकास किया और इस भाषा, अपनी कलाओं और वास्तुकला के माध्यम से उसने सुदूर देशों तक अपना संदेश पहुंचाया. यहां उपनिषदों की रचना की गई, गीता और बुद्ध के संदेश दिए गए.

आज हमारे भीतर और हमारे देश में ये सब विशेषताएं विद्यमान हैं. हमने परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की है तो हमारे यहां गाय के गोबर के युग की संस्कृति भी जीवित है.

हमारे इस उथल–पुथल और क्रमभंग के युग में, हम दोनों ओर देख रहे हैं, हमारे आगे हमारा भविष्य है और पीछे हमारा अतीत है और हम दोनों ओर खिंच रहे हैं. हम इस द्वंद्व का समाधान किस प्रकार करें और किस प्रकार ऐसी व्यवस्था बनाएं कि हमारी भौतिक आवश्यकताएं भी पूरी हों और साथ ही हमारे चित्त और आत्मा का भी पोषण हो? हम अपने लोगों के सामने ऐसे कौन से नए सिद्धांत या नए युग के लिए अनुकूलित किए गए पुराने सिद्धांत प्रस्तुत करें, ताकि हम लोगों को जागृत और कर्म के लिए प्रेरित कर सकें?

दुनिया में अन्य स्थानों की भांति भारत में भी दो सशक्त भावनाओं का उदय हुआ है – राष्ट्रवाद का विकास और सामाजिक न्याय की तीव्र उत्कंठा. समाजवाद और मार्क्सवाद सामाजिक न्याय की इस इच्छा के प्रतीक बने और अपने वैज्ञानिक कलेवर के अलावा उन्होंने भावनात्मक स्तर पर भी जनसाधारण को अपनी ओर आकर्षित किया.

जीवन बदलती परिस्थितियों के प्रति सतत समायोजन की प्रक्रिया है. पिछले पचास वर्षों में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से हुए बदलावों ने सामाजिक बदलाव की इस आवश्यकता को और बढ़ा दिया है और अनैक्य या असमायोजन लगातार बढ़ रहा है. विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति निश्चित तौर पर दुनिया की अधिकतर आर्थिक समस्याओं, विशेष तौर पर दुनिया भर में सभी के लिए आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की समस्या को हल करने की क्षमता रखती है. इसके लिए अपनाए जाने वाले तरीकों को संबंधित देश या समुदाय की पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना होगा.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज प्रमुख समस्या विश्व शांति को लेकर है. हमारे पास एकमात्र उपलब्ध विकल्प यह है कि विश्व को यथास्थिति में स्वीकार किया जाए और एक–दूसरे के प्रति सहनशीलता बरती जाए. प्रत्येक देश को यह छूट होनी चाहिए कि वह दूसरे देशों के अनुभव से सीखते हुए अपने ढंग से अपना विकास करे और हम उस पर अपनी राय न थोपें. मूलतः, इसके लिए एक नए मानसिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है. पंचशील या पांच सिद्धांतों में यह तरीका सुझाया गया है.

राष्ट्र के भीतर भी संघर्ष उत्पन्न होते हैं. वयस्क मताधिकार की व्यवस्था वाली लोकतांत्रिक प्रणाली में इन टकरावों को सामान्य संवैधानिक तरीकों से हल किया जा सकता है.

भारत में हमें प्रांतीयता या भाषा के नाम पर टकराव के सबसे अधिक तकलीफदेह टकराव देखने को मिले हैं. मुख्यतः समस्या आज वर्ग के हितों के टकराव के कारण उत्पन्न होती है और ऐसे मामलों में निहित स्वार्थों को समाप्त करना आसान नहीं होता है. लेकिन हमने भारत में देखा है कि पुराने रजवाड़ों, बड़ी जागीरदारियों, तालुकादारों और जमींदारों के निहित स्वार्थों को शांतिपूर्ण तरीकों से खत्म किया जा चुका है, हालांकि इसके लिए हमें एक ऐसी सुस्थापित व्यवस्था को खत्म करना पड़ा, जो केवल कुछ चुनिंदा लोगों के हितों की ही हिमायत करती थी. जहां हमें यह समझना होगा कि वर्ग संघर्ष हैं, वहीं हमें यह भी समझना होगा कि इनसे निपटने के लिए शांतिपूर्ण तरीकों का प्रयोग न किए जाने का कोई कारण नहीं है. लेकिन ये तरीके तभी सफल होंगे जब हमारे सामने एक स्पष्ट लक्ष्य हो जिसे लोग आसानी से समझ सकें. ■

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रकाशित इंडिया 'टुडे एंड टुमौरो', आज़ाद मैमोरियल लेक्चर्स, नई दिल्ली, 22 तथा 23 फरवरी, 1959 से उद्धृत

feedback@chauthiduniya.com

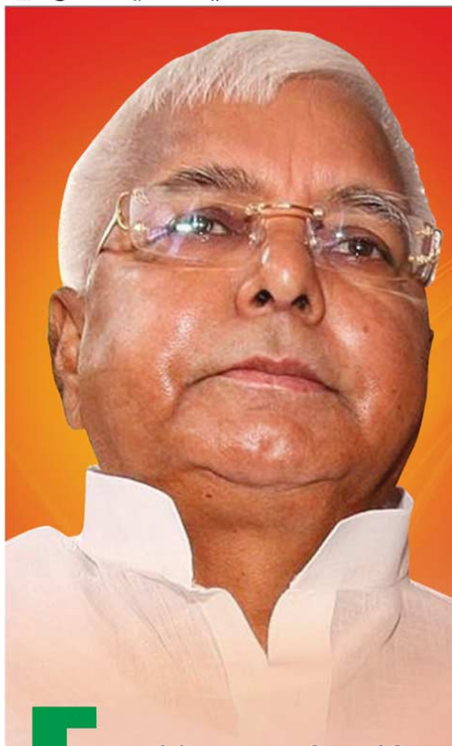

लालू के छिपे तीर

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की राजनीति उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के बाद क्या होगी? यह राजधानी के सत्ता गलियारे का आम सवाल है. आम तौर पर माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद कांग्रेस से उनके संबंध और ख़राब ही होंगे, तो नीतीश कुमार से भी सद्भाव-भरा रिश्ता नहीं रहेगा. पर, सूबे की मौजूदा राजनीतिक बनावट में नीतीश कुमार को सरकार चलाने के लिए राजद की जरूरत है. नीतीश कुमार के लिए राजद की अनिवार्यता कांग्रेस के उनके साथ अटूट संबंध और राजद में बिखराव से ही समाप्त हो सकती है. राजनीति के अदरखाने क्या हो रहा है, यह कहना कठिन है.

सरोज सिंह

राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद अपने राजद के नेताओं व अन्य संसाधन के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी को फिर कामयाब बनाने के लिए मेहनत करेंगे. बिहार में राजद का नया और प्रिय हमसफ़र नीतीश कुमार और दशकों पुरानी मददगार कांग्रेस उत्तर प्रदेश के राजनीतिक अखाड़े में उनके लिए अजनबी बन गई है. अगले संसदीय चुनाव (2019) में प्रधानमंत्री के किस दावेदार को उनकी पार्टी मदद करेगी, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, पता चलना आसान नहीं है. इससे संबंधित वह अपना पत्ता नहीं खोल रहे हैं. गैर भाजपा (गैर राजग) राजनीति से प्रधानमंत्री पद के कई उम्मीदवार हैं, जिनमें नीतीश कुमार भी एक हैं. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने से उनको खुशी होगी. उनकी नज़र में प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की फेहरिस्त में जद (यू) सुप्रीमो तो हैं, पर कहना कठिन है कि राजद के उम्मीदवार वे होंगे. इसके विपरीत कांग्रेस के शिखर नेता राहुल गांधी को लेकर वह निश्चित नहीं हैं. लालू प्रसाद कभी तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार की फेहरिस्त में राहुल गांधी के नाम को शुमार करना भूल जाते हैं, तो कभी राहुल गांधी के नाम आगे न करने के लिए कांग्रेस पार्टी को कोसते हैं. कुछ महीने पहले तक देश की राजनीति में गैर-सांप्रदायिक शक्तियों की एकता के लिए वह कांग्रेस की मजबूती जरूरी बता रहे थे. इसी तरह की स्थिति नीतीश कुमार को लेकर भी है. महागठबंधन सरकार में सबसे बड़े घटक दल होने के बावजूद राजद के नेता नीतीश सरकार को कई मसलों के जरिए निशाने पर लेते रहे हैं. लालू प्रसाद ने इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने पर पहले कभी गंभीरता से काम नहीं किया. अब शहाबुद्दीन को लेकर बयानबाज़ी के चरम पर पहुंच जाने और कांग्रेस के कड़े रुख के बाद वह नीतीश कुमार और जद (यू) विरोधी बयान-मुहिम पर रोक लगाने के लिए सक्रिय हुए. उनके नए रुख के बाद राजद के नेता नीतीश कुमार को लेकर फिलहाल ख़ामोश हैं. लेकिन यह बयान-युद्ध कब तक स्थगित रहता है, यह देखना है.

राजद सुप्रीमो की भावी राजनीति की दिशा को लेकर घनघोर संशय के बावजूद इतना तो तय मान लिया जाना चाहिए कि कांग्रेस के साथ उनके दल का मधुर काल ख़त्म जैसा हो गया है. दोनों दलों में दूरी काफी बढ़ गई है और इसमें कमी के आसार दिख नहीं रहे हैं. यह कहना थोड़ी जल्दबाज़ी होगी कि दोनों के बीच की खाई को पाटना असंभव है. पर, इतना तो तय है कि इस दूरी को ख़त्म या कम करने के लिए दोनों- कांग्रेस और लालू प्रसाद को अभूतपूर्व ही नहीं, अकथनीय मशक्कत करनी होगी. लालू प्रसाद की राजनीति को हाल-फिलहाल तक कांग्रेस का भरपूर समर्थन मिलता रहा था. राजनीतिक कारणों से अघोषित समर्थन और सहयोग का यह सिलसिला तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के कार्यकाल के आरंभिक दिनों में शुरू हुआ था, जो चार-पांच साल पहले तक चला. हालांकि इसका बदला लालू प्रसाद ने भी दिया. 1998 में केंद्र में राजनीतिक संकट के दौर में मुलायम सिंह यादव सहित अनेक राजनेताओं के विरोध के बावजूद सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की उन्होंने मुहिम चलाई थी. श्रीमती गांधी ने उनके इस उपकार को सदैव याद रखा. लेकिन कांग्रेस का निज़ाम बदला, तो नजरिया भी बदल गया. राहुल गांधी की राजनीति में चारा घोटाले के आरोपित (बाद में सज़ायाफ़्ता) लालू प्रसाद को लेकर बहुत सकारात्मक भाव नहीं था, तरज़ीह भी नहीं थी. किसी अदालत से दो साल या उससे अधिक समय के दोष-सिद्ध सज़ायाफ्ता को चुनाव से अलग रखने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के खिलाफ तैयार अध्यादेश के साथ राहुल गांधी के सलूक और फिर मनमोहन सरकार का उससे पीछे हट जाने के कारण लालू प्रसाद चुनावी राजनीति से बाहर हो गए-सत्ताधारी बनने के उनके सपने बियाबान में भटक गए. इतना ही नहीं, उस घटना के बाद बिहार में दो-दो आम चुनाव हुए, कांग्रेस और राजद ने साथ-साथ चुनाव लड़ा. इन चुनावों में राहुल गांधी ही नहीं, सोनिया गांधी के भी कार्यक्रम हुए. पर, इन सभी से लालू प्रसाद को अलग रखा गया या कांग्रेस उनसे अलग रही- एक साथ मंच पर आने से बचा गया. दूरी के साथ दोस्ती का यह दुर्लभ राजनीतिक उदाहरण है. बिहार विधानसभा चुनावों के समय कांग्रेस ने लालू प्रसाद को दरकिनार कर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का बेहतर उम्मीदवार बता दिया. उसके दबाव में ही नीतीश कुमार को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया गया.

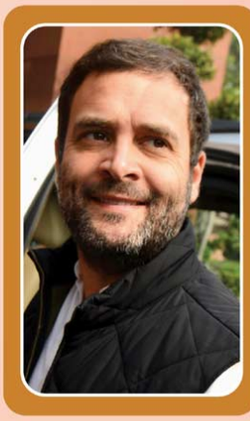

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की राजनीति उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के बाद क्या होगी? यह राजधानी के सत्ता गलियारे का आम सवाल है. आमतौर पर माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद कांग्रेस से उनके संबंध और ख़राब ही होंगे, तो नीतीश कुमार से भी सद्भाव भरा रिश्ता नहीं रहेगा. पर, सूबे की मौजूदा राजनीतिक बनावट में नीतीश कुमार को सरकार चलाने केलिए राजद की जरूरत है. नीतीश कुमार के लिए राजद की अनिवार्यता कांग्रेस के उनके साथ अटूट संबंध और राजद में बिखराव से ही समाप्त हो सकती है. राजनीति के अदरखाने क्या हो रहा है, यह कहना कठिन है. पर इन बातों की चर्चा हो रही है. वस्तुतः लालू प्रसाद के लिए यह काफी चुनौती भरा दौर है और इससे उबरने के उपाय वह खोज रहे हैं. इसमें अभी कोई सफलता मिलती नहीं दिख रही है. अब उनकी सारी उम्मीदें सर्वोच्च न्यायालय में लंबित चारा घोटालों के मामले पर और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव परिणाम पर टिक गई है.

मुख्यमंत्री केसवाल पर राजद सुप्रीमो चुनाव बाद फैसला के पक्षधर थे. कांग्रेस उपाध्यक्ष ने उनकी राजनीतिक रणनीति को पंक्चर कर दिया. सो, राहुल गांधी को लालू प्रसाद अपनी राजनीति में किस हद तक और किस गहराई में स्वीकार कर सकते हैं, इसे आसानी से समझा जा सकता है.

कांग्रेस नेतृत्व के इस रुख को राजद सुप्रीमो इतर ढंग से समझ रहे हैं और इसकी काट की तलाश में हैं. लालू प्रसाद की इस मानसिक अवस्था की अभिव्यक्ति हाल के उनके राजनीतिक आचरण में बहुत ही सफाई से हुई है और कांग्रेस नेताओं के आचरण में भी. लालू प्रसाद ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस उपाध्यक्ष के राजनीतिक अभियानों व वहां विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद उसकी संभावित राजनीतिक हैसियत को लेकर कुछ टिप्पणी की. इतना ही नहीं, अगले संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री पद के दावेदारों के तौर पर राहुल गांधी की दावेदारी को भी नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की. इन बयानात ने कांग्रेस को सतर्क ही नहीं, राजद सुप्रीमो के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार के लिए पेरित किया. उत्तर प्रदेश के मथुरा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजद सुप्रीमो ने कांग्रेस उपाध्यक्ष (वास्तविक तौर पर नंबर एक नेता) को जोकर कह दिया. हालांकि बाद में उन्होंने अपनी बात का खंडन किया और मीडिया को बलि का बकरा बनाने की नाकाम कोशिश की. लेकिन जो नुकसान होना था, वह तबतक हो चुका था. इसी तरह, मुलायम सिंह से लंबी बातचीत के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को कामयाब बनाने के लिए काम करने की घोषणा की. यहां तक तो सब कुछ ठीक ही रहा, लेकिन कांग्रेस के बारे में उनकी टिप्पणी ने पार्टी नेतृत्व को परेशान कर दिया. पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने यह कह दिया कि वहां लड़ाई तो सपा और भाजपा में है. भाजपा की हार चाहने वालों को सपा के साथ आना चाहिए, कांग्रेस तो संघर्ष से बाहर है और हद तो तब हो गई, जब देश में प्रधानमंत्री के भावी दावेदारों के नामों को गिनाते हुए उन्होंने मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, जयललिता आदि के तो नाम ज़ोरदार तरीके से लिए, किंतु राहुल गांधी के नाम की चर्चा तक नहीं की.

कांग्रेस के लिए पानी सर से गुज़र गया था. इसी बीच मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत पर रिहाई और उसके बयान से उठे विवाद व राजद नेताओं के मुख्यमंत्री पर परोक्ष हमले की कोशिश ने कांग्रेस को मौका दे दिया. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने राजद को इंगित कर बयान दे दिया कि जिन्हें नीतीश कुमार का कामकाज या उनका शासन पसंद नहीं है, वे चाहें तो गठबंधन से बाहर हो सकते हैं. गठबंधन में रह कर नेता को बदनाम करना राजनीतिक बेईमानी है. शहाबुद्दीन के बयानात से उठे बवंडर के बीच नीतीश कुमार के पक्ष और लालू प्रसाद के खिलाफ महागठबंधन के एक दल के नेता का यह सबसे कठोर व उत्तेजक बयान था. इसने अपना काम भी किया. राजद के नीतीश विरोधियों को शांत करने के लिए लालू प्रसाद को फरमान जारी करना पड़ा. इधर, प्रधानमंत्री के दावेदारों की सूची को लेकर उनकी सफाई भी आई. राजद सुप्रीमो ने सफाई दी-हमने तो उन्हीं नामों की चर्चा की है, जो खुल गए हैं. कांग्रेस ने अब तक राहुल गांधी के नाम की घोषणा नहीं की और मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं. फिर राहुल गांधी का नाम मैं कैसे ले सकता हूं! इतना होने के बाद भी लालू प्रसाद निश्चित नहीं हुए हैं- कांग्रेस को साधने की नए सिरे से कोशिश कर रहे हैं. हालांकि इसका कोई परिणाम फिलहाल आता दिख नहीं रहा है. पर, वह जानते हैं कि उनकी राजनीति को किसी राष्ट्रीय दल की छतरी चाहिए और अभी यह कांग्रेस ही हो सकती है. पर महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस क्या सोचती है.

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की राजनीति उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के बाद क्या होगी? यह राजधानी के सत्ता गलियारे का आम सवाल है. आमतौर पर माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद कांग्रेस से उनके संबंध और ख़राब ही होंगे, तो नीतीश कुमार से भी सद्भाव भरा रिश्ता नहीं रहेगा. पर, सूबे की मौजूदा राजनीतिक बनावट में नीतीश कुमार को सरकार चलाने के लिए राजद की जरूरत है. नीतीश कुमार के लिए राजद की अनिवार्यता कांग्रेस के उनके साथ अटूट संबंध और राजद में बिखराव से ही समाप्त हो सकती है. राजनीति के अदरखाने क्या हो रहा है, यह कहना कठिन है. पर इन बातों की चर्चा हो रही है. वस्तुतः लालू प्रसाद के लिए यह काफी चुनौती भरा दौर है और इससे उबरने के उपाय वह खोज रहे हैं. इसमें अभी कोई सफलता मिलती नहीं दिख रही है. अब उनकी सारी उम्मीदें सर्वोच्च न्यायालय में लंबित चारा घोटालों के मामले पर और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव परिणाम पर टिक गई है. सर्वोच्च न्यायालय में चारा घोटाले के लंबित मामलों की सुनवाई जल्द ही होनी है. इन मामलों में लालू प्रसाद को यदि राहत मिल जाती है, तो बिहार की राजनीति में अचानक उबाल आ जाएगा. ऐसा ही राहत नहीं मिलने की स्थिति में होगा. पर, तब राजनीति के करवट लेने में थोड़ा वक्त लगेगा. लालू प्रसाद ही नहीं, बिहार की राजनीति भी अदालत की ओर देख रही है. उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की हैसियत साफ़ हो जाएगी, तो बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल (यू) सुप्रीमो नीतीश कुमार के राष्ट्रीय राजनीतिक फलक पर छाने की चाहत की भी अग्निपरीक्षा होगी. इन दोनों के चुनावी प्रदर्शन लालू प्रसाद को अपनी रणनीति तैयार कर उसे सरजमीं पर उतारने में काफी मददगार होंगे. शहाबुद्दीन प्रकरण से महागठबंधन सरकार को जो भोग भोगना पड़ा हो, राजद सुप्रीमो की राजनीति को ताकत मिली है.उनको लेकर मुसलमानों में फैल रही उदासीनता पर ब्रेक लगा है. फिर भी, भावी चुनावी राजनीति को लेकर लालू प्रसाद का ऊहापोह अभी बना रह सकता है, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद तक. हालांकि यह सोचना सही नहीं है कि उनके सामने भावी राजनीति का कोई रोड-मैप नहीं होगा. वस्तुतः लालू प्रसाद हंसोड़ प्रकृति के गंभीर राजनेता हैं, पूरी राजनीति उनके दिमाग में बसी रहती है. सो संभव है, राजद को लेकर संशय का मौजूदा माहौल वह खुद बना रहे हों. वह कुछ भी कर सकते हैं, यह सभी मानते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

ईम्पोर्टेड केमिकल से तैयार, लैब टेस्टेड

पेन्ट डिस्टेम्पर
कोई भी हो
वॉल पुट्टी केवल ईटालियन वॉल पुट्टी

Laboratory Tested
Please Compare Lab Report

Made from Imported Chemicals
ईटालियन
व्हाईट
वॉल पुट्टी
Slight Costly but Superior

लैब रिपोर्ट अवश्य चेक करें ।
लैब रिपोर्ट हमारे सभी डीलर्स के यहां उपलब्ध है

प्रखण्ड स्तर या अपने क्षेत्र हेतू सप्लायर / डीलरशिप के लिए सम्पर्क करें ।
Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com

सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाऐ

सीमेन्ट
कोई भी हो परन्तु
वाटरप्रूफिंग केमिकल सिर्फ

मिस्टर केमिस्ट

सीमेन्ट कोई भी हो लेकिन वाटरप्रूफिंग केमिकल मिस्टर केमिस्ट ही हो, क्योंकि मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग केमिकल ईम्पोर्टेड केमिकल से बनाया गया है, प्रत्येक पैक पर नम्बर युक्त होलोग्राम से नकल से पूरी तरह सुरक्षित १, ५, १०, २० एवं २०० लीटर होलोग्रामिक पैक में अब आपके यहां भी उपलब्ध । मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाए ।

Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com

माय के बिसात पर शहाबुद्दीन का पासा

शहाबुद्दीन को लेकर नीतीश बनाम लालू की राजनीति में मुस्लिम मानसिकता का एक और महत्वपूर्ण एंगल भी है. राजद-जदयू गठबंधन के रूप में भले ही चुनाव लड़ा हो,लेकिन लालू यह मौका कभी नहीं छोड़ सकते कि मुस्लिम वोटों पर उनका वर्चस्व कम हो. अगर ऐसे में मुसलमानों का एक वर्ग शहाबुद्दीन की रिहाई में लालू की भूमिका तलाशता है, तो फिर शहाबुद्दीन की जमानत को अगर सुप्रीम कोर्ट रद्द करता है, तो इसके लिए वही वर्ग नीतीश की भूमिकता तलाश करेगा. इससे मुस्लिम वोटों के प्रति लालू की रणनीति ही सफल मानी जाएगी. यह बात तब आसानी से साबित हो सकेगी, जब हम उस संभावित स्थितियों की कल्पना करें जब लालू और नीतीश अलग हो कर चुनाव लड़ें तो मुसलमानों का बड़ा हिस्सा शहाबुद्दीन मामले को लेकर लालू के पक्ष में खड़ा दिखेगा.

इर्शादुल हक

10 सितंबर को जब राजद के विवादित नेता शहाबुद्दीन को जमानत पर रिहा किया गया, तो दो बातों पर बहुत तवज्जो नहीं दी गयी. इन में से एक थी- शहाबुद्दीन के स्वागत के लिए अनेक विधायकों समेत हजारों की भीड़ और सैकड़ों गाड़ियों के काफिले की तैयारी किसके कहने पर हुई थी. दूसरी बात यह थी कि रिहाई के बाद जब लालू प्रसाद व शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगाये जा रहे थे, तो अचानक नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ लोगों द्वारा नारेबाजी करने के पीछे क्या और किसकी रणनीति थी? इन दो सवालों के जवाब खोजना जरूरी है क्योंकि इन दो बातों के पीछे जिस सियासत का आकार उभर के सामने आता है, वही शहाबुद्दीन के सियासी महत्व का प्रतीक है. इन दोनों सवालों पर आम मन:स्थिति की चर्चा से पहले हमें दो अन्य विवादित नेताओं की विवादित रिहाई को याद कर लें, जिसने बिहार को झकझोर के रख दिया था. इनमें से एक थे पप्पू यादव, जिन्हें कम्युनिस्ट विधायक अजित सरकार की हत्या के आरोप के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था. और दूसरे थे रणवीर सेना के संस्थापक ब्रह्मेश्वर मुखिया, जिनके खिलाफ अनेक नरसंहार के आरोप थे, लेकिन उनके विरुद्ध कोई सुबूत नहीं पेश किया जा सका था. इन दोनों नेताओं की रिहाई के बाद ऐसा जश्न देखने को नहीं मिला था. जबकि शहाबुद्दीन की तरह ये दोनों नेता भी अपने-अपने समाजों के एक खास सेक्शन में लोकप्रिय थे.

पप्पू यादव और ब्रह्मेश्वर मुखिया से जुड़े मामलों को याद करने के बाद हम फिर शहाबुद्दीन मामले पर लौटते हैं, क्योंकि आखिर शहाबुद्दीन में वो कौन सी खास बात थी, जिनकी रिहाई पर शाहाना स्वागत की तैयारी की गयी थी. क्या शहाबुद्दीन ग्यारह साल जेल में बिताने के भी बाद इतने लोकप्रिय थे कि खुद ब खुद हजारों लोग उनके स्वागत में उमड़ पड़ते?

दरअसल 7 सितंबर को जब पटना हाईकोर्ट ने भागलपुर जेल में बंद शहाबुद्दीन की जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया, तो उसके बाद राजनीतिक गलियारों में दो दिनों तक शहाबुद्दीन के स्वागत की चर्चा फैलाई जाती रही. इस चर्चा को आगे बढ़ाने वालों में बिंदी यादव भी एक थे. आपराधिक छवि के ये वही बिंदी यादव हैं, जो राजद व जदयू दोनों के करीब रहे हैं और हाल ही में उनके बेटे की गिरफ्तारी रोडरेज की घटना के आरोप में हुई थी. यहां यह याद रखना जरूरी है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया व पप्पू यादव जब रिहा हुए, तो उनका सत्ता से कोई डायरेक्ट सरोकार नहीं था, जबकि शहाबुद्दीन जब रिहा हुए, तो वह कुछ महीने पहले ही राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बनाये जा चुके थे और उनका दल फिलहाल गठबंधन सरकार का सबसे बड़ा दल है. हालांकि शहाबुद्दीन की लोकप्रियता एक खास वर्ग में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी यह लोकप्रियता सीवान की सरहद तक सीमित रही है. सीवान के बाहर अपनी लोकप्रियता का प्रदर्शन खुद शहाबुद्दीन ने कभी किया भी नहीं. ऐसे में यह तय है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने शहाबुद्दीन के स्वागत की जबर्दस्त तैयारी की थी. हालांकि इसके लिए राजद ने कोई औपचारिक घोषणा नहीं की थी. मतलब स्पष्ट है कि ग्यारह साल के लंबी अवधि तक जेल में रहने वाले शहाबुद्दीन के स्वागत के लिए खुद ब खुद उनके समर्थक नहीं उमड़ पड़े थे. इसके लिए उनकी पार्टी ने एक खास रणनीति के तहत यह तैयारी की थी. और तब जैसे ही हजारों की भीड़ भागलपुर जेल के पास शहाबुद्दीन के स्वागत के लिए पहुंची, तो स्वाभाविक तौर पर शहाबुद्दीन अह्लादित हुए और पूरे जोश में उन्होंने लालू प्रसाद को अपना नेता बताया और लगे हाथों नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री घोषित कर

दिया. उनकी इस घोषणा से जनता दल बुरी तरह नाराज हुआ और इतना ही नहीं अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए जदयू ने अपने प्रवक्ता नीरज कुमार से कहलवाया कि शहाबुद्दीन अपनी जुबान पर लगाम रखें. उन्होंने यहां तक कहा कि बिहार सरकार ऐसी सुई चुभोती है, जिसमें दर्द तक नहीं होता. नीरज के इस बयान से राजद और जदयू के बीच की कड़वाहट बढ़नी थी, सो बढ़ ही गयी. लेकिन लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को दलीय स्तर पर कड़वाहट की अपनी सीमाएं मालूम हैं और इसीलिए दोनों ने बारी-बारी से कहा कि गठबंधन में कोई समस्या नहीं है. लेकिन शहाबुद्दीन के बहाने जो राजनीति की जानी थी, वह कर ली गयी. इसलिए ऊपर जिन दो सवालों की चर्चा की गयी है कि शहाबुद्दीन के स्वागत के लिए जो भीड़ उमड़ी थी, उसके पीछे किसकी रणनीति थी और उस समय नीतीश कुमार को नीचा दिखाने वाला बयान या नारेबाजी का क्या मकसद था. दरअसल शहाबुद्दीन के बहाने दोनों दल अपना शक्ति प्रदर्शन एक दूसरे के खिलाफ कर रहे थे, लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन की सीमाएं दोनों दलों के नीति निर्धारकों को पता थी. इसलिए दोनों दल इस मामले में एक दूसरे के खिलाफ शह-मात और जिच का खेल खेलते रहे. उधर नीतीश कुमार को इस मामले में अपनी छवि बचाने का तब मौका मिल गया, जब शहाबुद्दीन की जमानत को चुनौती देने के लिए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने चंदा बाबू की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की घोषणा कर दी. चंदा बाबू के तीन बेटों की हत्या का इल्जाम शहाबुद्दीन पर था. इसके बाद बिहार सरकार ने भी अलग से शहाबुद्दीन की जमानत को चुनौती देने का ऐलान किया. जदयू ने इसकी घोषणा के लिए दिल्ली में बैठे अपने वरिष्ठ नेता शरद यादव को चुना जो अब तक इस मामले में बिल्कुल खामोश थे. हालांकि गौर से देखें तो जदयू ने यह ऐलान मजबूरी में किया क्योंकि सात दिनों की लंबी चुप्पी के बाद उसने जमानत को चुनौती देने की घोषणा इसलिए की कि प्रशांत भूषण जब इसके लिए पहल कर चुके थे तो स्वाभाविक तौर पर राज्य सरकार को अपना पक्ष इस मामले में रखना ही पड़ता और तब उसके लिए फजीहत उठाने के अलावा कोई और रास्ता न बचता.

शहाबुद्दीन पर सियासत और उस मुद्दे पर राजद-जद यू के बीच शह-मात के खेल में लालू के लिए एक लंबी रणनीति का हिस्सा भी लगता है. शहाबुद्दीन भले ही आपराधिक छवि के नेता रहे हों, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जमानत के बाद उन्हें एक मुस्लिम फेस के रूप में हर किसी ने पेश करने की कोशिश की है. इस खेल में भाजपा भी शामिल है. शहाबुद्दीन की जमानत पर रिहाई के बाद सोशल मीडिया में इसकी बानगी देखने को भी मिली. मुसलमानों के एक वर्ग ने शहाबुद्दीन के खिलाफ विरोधी दलों और मीडिया के रवैये को मुस्लिम विरोध की मानसिकता के तौर पर लिया. इस वर्ग ने सोशल मीडिया में अपनी ऐसी ही प्रतिक्रिया दी भी. कइयों ने तो शहाबुद्दीन की रिहाई को शेर की रिहाई तक घोषित कर दी. उधर लालू प्रसाद को मुस्लिम फेस के रूप में राजनीति करने का भी मौका मिला. कुछ मुसलमानों ने शहाबुद्दीन की जमानत पर रिहाई के लिए लालू प्रसाद की भूमिका तलाशी. उनके इस तर्क को शहाबुद्दीन के उस बयान से और भी बल मिला, जिसमें उन्होंने जेल से छूटते ही लालू प्रसाद को अपना एक मात्र नेता घोषित कर दिया था.

शहाबुद्दीन को लेकर नीतीश बनाम लालू की राजनीति में मुस्लिम मानसिकता का एक और महत्वपूर्ण एंगल भी है. राजद-जदयू गठबंधन के रूप में भले ही चुनाव लड़ा हो लेकिन लालू यह मौका कभी नहीं छोड़ सकते कि मुस्लिम वोटों पर उनका वर्चस्व कम हो. अगर ऐसे में मुसलमानों का एक वर्ग शहाबुद्दीन की रिहाई में लालू की भूमिका तलाशता है, तो फिर शहाबुद्दीन की जमानत को अगर सुप्रीम कोर्ट रद्द करता है, तो इसके लिए वही वर्ग नीतीश की भूमिकता तलाश करेगा. इससे मुस्लिम वोटों के प्रति लालू की रणनीति ही सफल मानी जायेगी. यह बात तब आसानी से साबित हो सकेगी, जब हम उस संभावित स्थितियों की कल्पना करें, जब लालू और नीतीश अलग हो कर चुनाव लड़ें, तो मुसलमानों का बड़ा हिस्सा शहाबुद्दीन मामले को लेकर लालू के पक्ष में खड़ा दिखेगा.

शहाबुद्दीन के नाम पर सियासत का एक और अहम पहलू यह है कि वह अगर जेल से बाहर रह गये, तो उनका राजनीतिक रसूख मुसलमानों पर तेजी से बढ़ेगा, जो कि लालू के लिए मुफीद नहीं हो सकता. क्योंकि लालू यह तो चाहेंगे कि मुस्लिम फेस का लाभ उन्हें मिले, लेकिन मुस्लिम फेस उनके लिए कालांतर में चुनौती ही बन बैठे, ऐसा लालू प्रसाद क्यों गवारा करेंगे?■

feedback@chauthiduniya.com

CRM
TMT BAR
ISO 9001 - 2000 Certified Co.
IS:1786:2008
CM/L-5746178
भूकम्प रोधी
जंग रोधी
Fe-500
मुख्य खूबियाँ
• बचत
• मजबूती
• शानदार फिनीश
Mfg. : CITY ROLLING MILLS PVT. LTD., PATNA
HELPLINE : 0612-2216770

गॉल ब्लॉडर के प्रति सजगता जरूरी
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
डॉ. शिव नारायण सिंह एम.एस. सर्जरी,एमसीएच गैस्ट्रो इन्दिरा गांधी,आयु. संस्थान, पटना, वर्तमान-गया मेडिकल कॉलेज, सहायक प्रध्यापक

गया के अनुभवी सर्जन, डॉ. शिव नारायण सिंह, ने बातचीत के क्रम में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी और गॉल ब्लॉडर से होने वाली परेशानियों के सम्बन्ध में बातचीत की। डॉ. नारायण से जब हमने पुछा कि लोग सर्जन के पास कैसे पहुंचेंगे तो उन्होंने बताया कि ज्यादातर केस हमलोगों के पास रेफर किया हुआ ही आता है। किसी को परेशानी होने पर सबसे पहले लोग जेनरल फिजिशियन के पास जाते हैं और वो हमें रेफर करते हैं। सर्जन के पास आने वाले मरीजों में हाइड्रोसील, हर्नियां, अपेन्डिक्स, स्टोन, गॉल ब्लॉडर स्टोन, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट रहते हैं। डॉ. नारायण बताते हैं कि यह देखा गया है कि गंगा के किनारे रहने वालों में इस तरह की समस्या ज्यादा पायी जाती है। इससे बचाव के बारे में पुछने पर वो बताते हैं कि पित जब सही ढंग से नहीं बनता है तो ये प्रॉब्लम आती हैं। दूसरी ओर उनका मानना है कि महिलाओं में यह बीमारी ज्यादा देखी गयी है। ज्यादातर इस बीमारी का कारण वसा युक्त भोजन है। शुद्ध खाने का तेल नहीं मिल पाना भी गॉल ब्लाडर की एक मुख्य वजह है। रिसर्च में पाया गया है कि गॉल ब्लॉडर से ही गॉल ब्लॉडर कैन्सर हो जाता है। स्टोन का साइज 3 से मी से बड़ा है तो कैंसर का होने का चांस ज्यादा रहता है। सलाह – अपने दैनिक जीवन की दिनचर्या को सही रखें जिसमें सुबह की मॉर्निंग वाक, योगाभ्यास, या कसरत, के अलावा समय पर नाश्ता और खाना जिसमें वसा युक्त भोजन में कमी लायें, पानी ज्यादा पीयें ■ भारती

ACOBA CAP/SYP/INJ
Methylcobalmin, Lycopene, Multivitamin Multimineral, Ginseng & Antioxident
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
ASRFEN-P
Acedofenac+Paracetamol Serratiopeplidase Tab.
ECTALOPAM
Escilalopram oxalate & Clonazepam Tablets
SILIPLEX
Silymarin, Vitamin B-Complex & Lactic acid, Calcium, Bacillus Cap/Syp
NOKSIRA
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

दुद्धी और ओबरा विधानसभा सीट आदिवासियों को वापस करो...

अधिकार के लिए एकजुट आदिवासी

खूफी यायावर

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदिवासियों के लिए आरक्षित की गई दुद्धी और ओबरा विधानसभा सीट छीनकर मोदी सरकार ने देश में संवैधानिक संकट पैदा कर दिया है और खुलेआम सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना की है. ऐसी हालत में संविधान की रक्षा के लिए आदिवासी अधिकार मंच ने व्यापक और जुझारू संघर्ष का रास्ता अख्तियार कर लिया है. मंच की तरफ से 20 सितंबर को रॉबर्ट्सगंज कलेक्ट्रेट पर आदिवासियों की जोरदार सभा आयोजित हुई, विरोध प्रदर्शन हुआ, धरना दिया गया और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया. इसके पहले बभनी, धोरावल, दुद्धी, नगवां, म्योरपुर, ओबरा और चतरा में आदिवासियों का सिलसिलेवार सम्मेलन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया. मंच ने कहा है कि केंद्र सरकार ने आदिवासियों के अधिकार नहीं दिए, तो दुद्धी से लेकर दिल्ली तक संघर्ष होगा.

आदिवासी अधिकार मंच के संयोजक व आईपीएफ के प्रदेश महासचिव दिनकर कपूर और आदिवासी नेता पूर्व विधायक विजय सिंह गोंड़ ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान की रक्षा करने में विफल साबित हुई है. संविधान के उद्देश्य में ही कहा गया है कि सरकार भारत के हर नागरिक के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार की हर हाल में रक्षा करेगी. लेकिन इस सरकार ने संसद में 4 जुलाई 2014 को 'संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक (तीसरा) 2013' वापस लेकर आदिवासी समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित कर दिया. यह बड़ा सवाल है कि जिस समय मोदी सरकार संसद से बिल वापस ले रही थी, उस समय इस क्षेत्र के आदिवासी सांसद और भाजपा से जुड़े अन्य आदिवासी सांसद चुप्पी साधे बैठे थे. मोदी सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए अध्यादेश लाकर दुद्धी व ओबरा सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित करनी चाहिए. दिनकर कपूर ने कहा कि आदिवासी समाज को विकास की मुख्यधारा से काट दिया गया है. सरकार लगातार दलितों और आदिवासियों के बजट में कटौती कर रही है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी केंद्र सरकार ने मनरेगा की मजदूरी का चार माह से भुगतान नहीं किया. परिणामतः भीषण सूखे और वर्षा के कारण संकटग्रस्त ग्रामीण परिवार भुखमरी के शिकार हैं. वृक्षारोपण के लिए कैम्पा कानून बनाकर वनाधिकार कानून को खत्म करने में केंद्र सरकार लगी हुई है. सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली का यह दलित-आदिवासी बहुल पहाड़ी अंचल उत्तर प्रदेश का कालाहांडी बना हुआ है. आजादी के साठ साल बाद भी चुआड़, नालों और बांधों का प्रदूषित पानी पीकर ग्रामीण बेमौत मर रहे हैं. आज भी इन क्षेत्रों में गांवों में जाने को सड़कें नहीं हैं और बीमारी की हालत में खटिया पर लादकर लोग इलाज के लिए ले जाते हैं. मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही आदिवासियों और दलितों के विकास के लिए बजट में आवंटित होने वाली धनराशि में भी 32,105 करोड़ रुपये की भारी कटौती कर दी. आदिवासियों के लिए 2014-15 में आंवटित 26,714 करोड़ को घटाकर 2015-16 में 19,980 करोड़ और 2016-17 में 23,790 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इसके साथ ही आदिवासी जीवन के लिए जरूरी मनरेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य व छात्रवृत्ति के बजट में भी भारी कटौती कर दी गई है. दस लाख से भी अधिक आदिवासी समाज के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सरकार हनन कर रही है. वनाधिकार कानून के अंतर्गत आदिवासियों को मिलने वाली ज़मीन के 92,406 दावों में से 74,701 अर्थात 81 प्रतिशत दावे रद्द कर दिए गए हैं और मात्र 17,705 दावों में ही ज़मीन दी गई है. इसमें सोनभद्र जनपद के 65526 प्राप्त दावों में से 53506 दावे खारिज किए जा चुके हैं. इसमें भी सत्तर प्रतिशत दावे दुद्धी तहसील के आदिवासियों के हैं. उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी प्रदेश सरकार आदिवासियों ववनाश्रित जातियों को उनकी पुश्तैनी जमीन पर अधिकार देने को तैयार नहीं है. इससे उत्तर प्रदेश के आदिवासियों में घोर निराशा और आक्रोश व्याप्त है. इसके साथ ही सरकार वृक्षारोपण के लिए कैम्पा कानून बनाकर वनाधिकार कानून खत्म करने पर आमादा है.

> आदिवासियों ने समवेत रूप से यह आवाज उठाई है कि दुद्धी व ओबरा विधानसभा सीट को आदिवासी समाज के लिए आरक्षित करने के आदेश को हर हाल में लागू किया जाना चाहिए.

आदिवासियों ने समवेत रूप से यह आवाज उठाई है कि दुद्धी व ओबरा विधानसभा सीट को आदिवासी समाज के लिए आरक्षित करने के आदेश को हर हाल में लागू किया जाना चाहिए. इसके अलावा वनाधिकार कानून के तहत जमीन पर अधिकार देने, कोल, धांगर समेत सात अन्य जातियों को आदिवासी का दर्जा देने व गोंड़, खरवार समेत आदिवासियों का दर्जा पा चुकी 10 जातियों को चंदौली समेत पूरे प्रदेश में आदिवासी का आधिकारिक दर्जा देकर आबादी के अनुसार आदिवासियों को बजट में हिस्सा देने जैसे सवालों पर भी आदिवासी अधिकार अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया. आदिवासी अधिकार को लेकर हुए सम्मेलनों में हजारों की संख्या में जुटे आदिवासियों ने इस बात पर गहरा रोष जताया कि पिछले चौदह साल से केंद्र व प्रदेश में राज करने वाली भाजपा, कांग्रेस और सपा, बसपा की सरकारों ने आदिवासियों के अधिकार नहीं दिए. गोंड़, खरवार समेत दस जातियों को जब आदिवासी का दर्जा दिया गया था, उस समय केंद्र व राज्य में भाजपा की सरकार थी, पर उसने उनके लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं की. उसके बाद बनी सरकारों ने तो आदिवासियों के आरक्षण को ही रोकने की कोशिश की. 2010 में उच्च न्यायालय ने आदिवासियों के लिए पंचायत में आरक्षण देने का निर्णय दिया था, पर उस समय मायावती सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई और इसे स्टे करा दिया. बाद में आधे अधूरे मन से अखिलेश सरकार ने आंदोलन के दबाव में सीट आरक्षित की, पर इसमें भी बेईमानी हुई. कुशीनगर, जहां आदिवासी हैं ही नहीं, वहां आदिवासी आरक्षण दे दिया गया. भाजपा की मौजूदा सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर संसद से विधेयक वापस लेकर आदिवासी समाज के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया. आदिवासी अधिकार मंच के संयोजक दिनकर कपूर ने कहा कि यह आंदोलन मात्र आदिवासी समाज के अधिकार का ही नहीं है, बल्कि यह इस देश के हर उस आम नागरिक का आंदोलन है, जिसके अधिकार सरकार और सत्ता द्वारा छीने जा रहे हैं. मोदी सरकार दलित, आदिवासी व पिछड़े समाज के सामाजिक न्याय के अधिकार को खत्म करने में लगी हुई है, इसका व्यापक विरोध किया जाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

लोग उन्हें दंडनायक कहते हैं

डॉ. पंकज सिंह

जनता की जरूरतें जब प्रशासन पूरी नहीं करता और जब जनप्रतिनिधि भी जनता की जरूरतों के प्रति उपेक्षा बरतने लगता है, तो इन्हीं परिस्थितियों में समाज में दंडनायक उभर कर सामने आता है. ग्राहिमाम कर रही रायबरेली की जनता को भी एक दंडनायक का सहारा मिल गया है. रायबरेली के मशहूर होम्योपैथिक चिकित्सक और भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉ. राजीव सिंह जितने अपने मरीजों के प्रति संजीदा रहते हैं, उतनी ही सहृदयता आम लोगों के प्रति भी रहती है. आम गरीब लोगों की समस्याओं को सुलझाने, उत्पीड़न करने वाले या भ्रष्टाचारियों को दंड दिलवाने में डॉ. राजीव सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं. दर्जनों ऐसे सरकारी अधिकारी या कर्मचारी हैं, जिन्हें अपनी गैरजिम्मेदारी का दंडभोगना पड़ा है.

डॉ. राजीव सिंह से जब उनके पेशे और उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता के संतुलन पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा किचिकित्सा के लिए मैं पूरा समय देता हूं. शेष समय मेरा व्यक्तिगत है. उसमें मैं सोने के बजाय समाज सेवा करना अधिक सार्थक समझता हूं. ग्राम पंचायत कम्युनिकेशन प्लान के तहत लोगों की समस्याओं के बारे में व्यक्तिगत रूप से, इंटरनेट के जरिए, फोन या अखबार के माध्यम से जानकारी मिलती है. फिर उस पर कार्रवाई के लिए प्रशासन के संबंधित जिम्मेवार अधिकारी को अवगत कराकर लोगों की समस्याओं को दूर कराने का प्रयास करता हूं. इसके साथ-साथ लोगों को भी जागरूक करके समस्याओं से लड़ने के लिए प्रेरित करता हूं. आम लोगों को उनके अधिकार के बारे में जानकारी देता हूं. इसके लिए मैंने रायबरेली में अपने खर्च पर एक प्रॉब्लम क्लेक्टर रखा है, जो गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं इकट्ठा करके मुझे उसकी जानकारी देता है. तत्पश्चात कार्रवाई आगे बढ़ती है.

> डॉ. राजीव सिंह से जब उनके पेशे और उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता के संतुलन पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा किचिकित्सा के लिए मैं पूरा समय देता हूं. शेष समय मेरा व्यक्तिगत है. उसमें मैं सोने के बजाय समाज सेवा करना अधिक सार्थक समझता हूं.

ग्राम पंचायत कम्युनिकेशन प्लान के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि सभी वर्तमान व पूर्व प्रधानों की लिस्ट निकलवाकर उनसे टेलीफोन पर या उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करके वहां की समस्याओं को लिस्टिंग करना ही ग्राम पंचायत कम्युनिकेशन प्लान है. डॉ. सिंह कहते हैं कि आम लोगों से जुड़ी मूलभूत समस्याओं पर उनका अधिक जोर रहता है. मसलन, सड़क, पीएमजीएसवाई, सिंचाई, पुलिस से जुड़े मामले, आवास, पेंशन वगैरह. आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देते हुए डॉ सिंह कहते हैं कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति में जन-सुनवाई सबसे कारगर जरिया है. इसके अलावा शासन के अधिकारियों से व्यक्तिगत संवाद, ई-मेल, आरटीआई भी बेहतर माध्यम है. डॉ. राजीव कहते हैं कि जूझने से काम होता है. आमतौर पर लोग लड़ने से पहले ही थक जाते हैं. यदि कुछ लोग लड़ते भी हैं, तो जल्द ही निराश हो जाते हैं. आम आदमी को जन प्रतिनिधियों का साथ नहीं मिल पाता, इसलिए भी जनता की लड़ाई कमजोर पड़ जाती है. जनप्रतिनिधि ईमानदारी से अपना काम करे, तो निश्चित ही जनता की समस्याओं को आसानी से दूर किया जा सकता है.■

feedback@chauthiduniya.com

सपा का विवाद चरम पर, दो विरोधी दिशाओं में खिंच रही साइकिल की बुरी दशा

एक पहिया ईर-घाट दूसरा बीर-घाट...

प्रभात रंजन दीन

समाजवादी पार्टी और समाजवादी सरकार, दोनों चलती हुई तो दिख रही है, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों चलने का उपक्रम कर रही है. दोनों यह दिखाने का निरर्थक प्रयास कर रही है कि सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन असलियत यही है कि कुछ भी सामान्य नहीं चल रहा है. अब सरकार अलग है और पार्टी अलग. शिवपाल यादव सरकार में मंत्री हैं यह अखिलेश की विवशता है और अखिलेश यादव पार्टी में हैं, यह शिवपाल की विवशता है. दोनों एक दूसरे के समर्थकों को बाहर का रास्ता दिखा कर एक दूसरे को निकालने का मनोवैज्ञानिक सुख प्राप्त कर रहे हैं. शिवपाल अखिलेश विवाद में मुलायम भी पार्टी हैं और रामगोपाल भी. मुलायम शिवपाल की तरफ खड़े हैं और रामगोपाल अखिलेश की तरफ. रामगोपाल और अखिलेश ने विवाद के लिए 'बाहर का आदमी' अमर सिंह को दोषी बताया, तो मुलायम सिंह ने अमर को महासचिव बना कर 'अंदर के आदमी' की मान्यता दे दी. पार्टी के नेता कहते हैं कि अब तो बड़ा कन्फ्यूजन है, अंदर का आदमी कौन है और बाहर का आदमी कौन, इसका पता ही नहीं चल रहा. संशय का ऐसा माहौल बना हुआ है कि कोई भी नेता या कार्यकर्ता किसी से भी मिलने से कतरा रहा है कि पता नहीं कौन किस खेमे में डाल दे और अंदर वाला बाहर हो जाए और बाहर वाला अंदर. चुनाव के वक्त ऐसा डरावना माहौल है, तो परिणाम के भी भयानक ही होने का अंदेशा है. सियासी फायदे और नुकसान के बरक्स प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश सामाजिक तौर पर लाभ की तरफ हैं, क्योंकि ओछी सियासत देख-भांप रहे आम लोग अखिलेश की तरफ नैतिक पलड़ा भारी देख रहे हैं.

यों तो अखिलेश तनातनी के बीच ही सरकार चलाते रहे, लेकिन चुनाव नजदीक आने के साथ ही सारे तनाव सतह पर आ गए, क्योंकि 'कौन किसके साथ', इसे तय करने का यही सटीक समय था. कौमी एकता दल का सपा में विलय-प्रसंग लिटमस टेस्ट था. इस टेस्ट में ही अखिलेश का प्रतिकारी स्टैंड स्पष्ट हो गया. हालांकि बर्खास्त किए गए मंत्री बलराम यादव मंत्रिमंडल में फिर से वापस आ गए, लेकिन तनातनी और बढ़ती ही चली गई. अब शिवपाल ने आखिरी अस्त्र का इस्तेमाल किया. लखनऊ में नहीं, मैनपुरी जाकर सरकार के प्रति अपना शोक ज्ञापित किया और इस्तीफा देकर वृष्टि-छाया-क्षेत्र में चले जाने की इच्छा जताते हुए मुलायम के निर्णयों पर सारा दारोमदार रख दिया. शिवपाल की यह सही और सटीक चाल थी. 15 अगस्त को पार्टी के लखनऊ मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में ही मुलायम ने मुख्यमंत्री अखिलेश के समक्ष आपा खो दिया. मुलायम ने बिल्कुल खम ठोकते हुए कहा कि शिवपाल नहीं तो पार्टी नहीं. इसके बाद फिर से संधि का उपक्रम चला. लेकिन इन्हीं उपक्रमों में एक-दूसरे पर तीखे-मीठे कटाक्ष और व्यंग्यात्मक प्रहार भी जारी रहे. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अचानक आक्रामक तेवर दिखाते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक सिंघल को बाहर का रास्ता दिखा दिया. अभी सब हतप्रभ ही थे कि प्रदेश के खनन मंत्री गायत्री प्रजापति के भ्रष्टाचार की सीबीआई से जांच कराने का आदेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश को एक और मौका दे दिया. अखिलेश ने गायत्री प्रजापति को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया. अर्थ के इतने बड़े स्रोत पर सीधा हमला! नेतृत्व बिफर पड़ा. मुलायम अपना गुस्सा रोक नहीं पाए और कह ही डाला कि प्रजापति की बर्खास्तगी के बारे में उन्हें भी मीडिया से ही पता चला है.

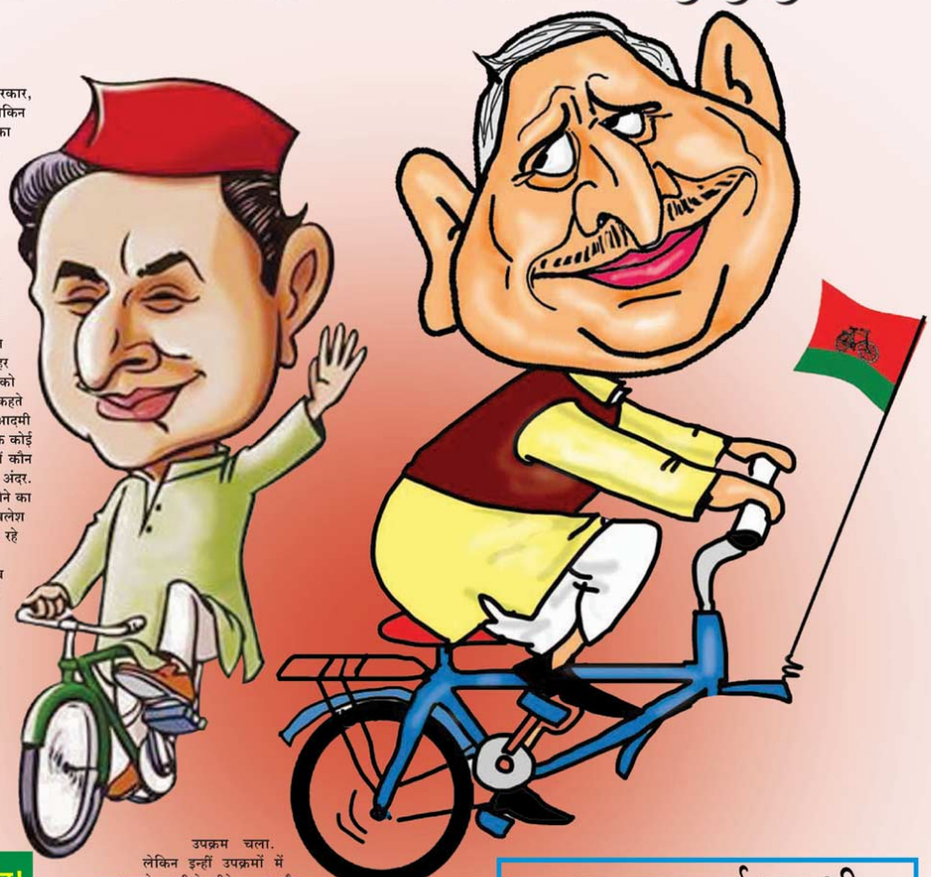

फिर तो एक दूसरे को औकात दिखाने की कार्रवाई चल पड़ी. मुलायम भी अब सीधे पार्टी बन गए. उन्होंने अखिलेश को सपा के प्रदेश अध्यक्ष से पद से हटा कर शिवपाल को अध्यक्ष बना डाला. इस पर अखिलेश ने मंत्रिमंडल से शिवपाल के महत्वपूर्ण विभाग छीन लिए. शिवपाल ने फिर से इस्तीफे का दाव चला. फिर संधि के लिए शिखर वार्ताएं होने लगीं. अखिलेश को समझौता करना पड़ा. उन्होंने शिवपाल के विभाग (लोक निर्माण छोड़ कर) लौटा दिए. लेकिन अखिलेश को प्रदेश अध्यक्ष का पद वापस नहीं मिला. अखिलेश प्रदेश संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बना दिए गए. सार्वजनिक तौर पर दिखाया जाने लगा कि विवाद निपट गया और संधि हो गई. कैमरे के सामने साझा-मुस्कान का प्रहसन भी खेला गया. लेकिन महाभारत तो चालू ही था. शिवपाल ने प्रदेश अध्यक्ष बनते ही अखिलेश के तमाम समर्थकों को पार्टी से निष्कासित करने का जैसे अभियान ही चला दिया. शिवपाल ने विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह यादव, आनंद भदौरिया और संजय लाठर समेत मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव दुबे और प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद एवाद, युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष बृजेश यादव और समाजवादी छात्रसभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव को पार्टी से बाहर निकाल दिया. प्रो. रामगोपाल यादव के भांजे और विधान परिषद सदस्य अरविंद सिंह यादव को पार्टी से बाहर निकाल कर शिवपाल आमने-सामने के युद्ध की शुरुआत पहले ही कर चुके थे. शिवपाल ने बाद में बयान दिया कि निकाले गए नेता सपा प्रमुख के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोपी हैं. इस निष्कासन से सपा के घरेलू विवाद ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया. सपा संगठन के प्रदेश भर के युवा नेताओं ने अखिलेश के समर्थन में अपने इस्तीफे दे दिए. सड़कों पर भी उग्र विरोध हुए.

इस बीच मुलायम ने राज्यसभा सदस्य अमर सिंह को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त कर विवाद को और भी गहरा कर दिया. एक दिन पहले ही राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव ने मीडिया के सामने यह बयान दिया था कि बाहरी आदमी अमर सिंह ही पार्टी में सारी गड़बड़ी के जिम्मेदार हैं. अखिलेश ने भी मीडिया के सामने बाहरी आदमी की पुष्टि की थी और कहा था कि अब वे अमर सिंह को अंकल नहीं बोलेंगे. मुलायम को यह नागवार गुजरा, उन्होंने आनन-फानन अमर सिंह को अंदर का आदमी बना कर रामगोपाल और अखिलेश दोनों का मुंह बंद कर दिया. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सपा का यह संक्रमण काल है. कौन किसके समक्ष आत्मसमर्पण कर देगा, किन शक्तियों के हाथ में सपा का नेतृत्व होगा और पार्टी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा यह सब तय होने का समय आ गया है. अखिलेश ने अपने कार्यकाल के आखिरी दौर में ही सही, अपना कद बड़ा दिखाने का काम तो किया ही है. मुलायम के पसंदीदा मंत्री गायत्री प्रजापति को बर्खास्त करना और शिवपाल के पसंदीदा मुख्य सचिव दीपक सिंघल को पद से बाहर कर देना यही बताता है. अखिलेश ने सियासत की दुनिया को यह भी दिखाया कि मुलायम सिंह जैसे कद्दावर नेता को भी चुनाव जीतने के लिए अमर सिंह की जरूरत महसूस होती है, लेकिन वे (अखिलेश) अकेले अपने और अपने कार्यकर्ताओं के बूते चुनाव जीतने का दम रखते हैं. शिवपाल जैसे कद्दावर मंत्री के विभाग छीन कर भी अखिलेश ने अपनी दृढ़ता और मजबूती का प्रदर्शन किया. शिवपाल जैसे नेता को भी अपने बचाव के लिए मुलायम का सहारा लेना पड़ा. इसे आम लोगों ने समझा और परखा है. सब कुछ हो जाने के बावजूद अखिलेश ने शिवपाल को लोक निर्माण विभाग जैसा दुधारू विभाग वापस नहीं दिया, उसे अपने पास ही रखा. ■

feedback@chauthiduniya.com

सपा के टूटने के बोल, भाजपा का क्या रोल!

राजनीतिक गलियारे की अंदरूनी खबर रखने वालों का यह भी कहना है कि सपा के विवाद को भाजपा हवा दे रही है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ऐसे तोड़फोड़ और तिकड़मों में माहिर माने जाते हैं. भाजपा के समर्थन से सुभाष चंद्रा के राज्यसभा का सदस्य बनने की खुशी में अमर सिंह ने दिल्ली में पंचसितारा भव्यता वाला कार्यक्रम क्यों रखा था? पार्टी-लाइन के पार जाती इस खुशी की वजह केवल मित्रता थी या भाजपा? फिर इस पार्टी में शरीक होने पर अखिलेश यादव इतने नाराज क्यों हो गए कि उन्होंने दीपक सिंघल को मुख्य सचिव के पद से फौरन खदेड़ भगाया! अखिलेश भी इस पार्टी में शरीक नहीं हुए, जबकि उनके पिता मुलायम और चाचा शिवपाल मौजूद थे. भाजपा बसपा में भगदड़ मचा चुकी है. बसपा के कद्दावर नेता भाजपा में शरीक हो चुके हैं. सपा ही अकेली ऐसी पार्टी बची थी, जिससे भाजपा को सीधा खतरा था. सपा में कलह-वाइरस से घबरा कर कई नेताओं के भाजपा में खिसकने की चर्चा है. सपा के कई नेताओं को यह आशंका है कि अखिलेश के हाथ से प्रदेश अध्यक्ष का पद चले जाने से उनका टिकट कट सकता है. लिहाजा, ऐसे नेताओं को भाजपा अपने पाले में लाने की तैयारी में है. विरोधी दलों को हतोत्साहित करने की अमित शाह की रणनीति बसपा के बाद सपा पर कारगर होती दिख रही है. कम संख्याबल वाली कांग्रेस का भी एक विधायक भाजपा में शामिल हो चुका है.

अभी हाल तक अखिलेश यादव और सरकार की उपलब्धियों का बखान करते सपा नेता अघा नहीं रहे थे. पूरी पार्टी अखिलेश के नेतृत्व में चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी और जोश में थी, लेकिन अचानक ब्रेक क्यों लग गया? अब पार्टी में चुनाव के बजाय 'कौन किस पाले में' की चर्चा क्यों हावी है? अब अखिलेश के विकास के नारे और चुनावी चेहरे पर पार्टी आलाकमान ने चुप्पी क्यों साध रखी है? इन सवालों का अर्थ तलाशा जाना चाहिए. सपा का महाभारत महज सियासी वर्चस्व की वजह से है, यह बता कर इस गंभीर मसले का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता. इस विवाद की जड़ में कोई सिद्धांत नहीं, कोई विचार नहीं, कोई वर्चस्व की लालसा नहीं, बल्कि इसके पीछे नियोजित रणनीति है, जिसका विषाणु बाहर से घर में दाखिल होकर घर के लोगों को बाहर कर रहा है. इसके पीछे गहरे राजनीतिक लक्ष्य हैं. यह विषाणु इतना घातक है कि जिस पिता ने शिवपाल आजम जैसे दिग्गजों की राय दरकिनार कर बेटे को मुख्यमंत्री पद पर बिठाया, वही अब उसे अपना विरोधी मान रहा है! वही पिता यहां तक कहने लगा कि अखिलेश के मुख्यमंत्री रहते हुए 2014 के लोकसभा चुनाव में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा! वही पिता अपने मुख्यमंत्री पुत्र पर यह सार्वजनिक आरोप लगाने से नहीं हिचका कि पार्टी और सरकार में कुछ भी ठीक नहीं है. अखिलेश का कोई नियंत्रण नहीं है! वही पिता यह बोल गए कि शिवपाल नहीं तो पार्टी नहीं! लब्बोलुबाब यह है कि सपा में कलह पसारने के लिए ऐसा ही संवेदनशील वक्त चुना गया, जब चुनाव सामने है. पार्टी के टूटने और बंटने की चर्चाएं मतदाताओं को तो बांटने का काम कर रही हैं. यह भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है. कुछ विश्लेषकों का यह भी चिंतन है कि चुनाव में कम सीटें मिलने पर भाजपा सपा के ही किसी एक धड़े को समर्थन देकर सरकार बनवा सकती है. पार्टी में अभी जिस तरह की कलह है, उससे चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने की दो-तीन महत्वाकांक्षाओं के टकराने की पूरी आशंका है, ऐसे में भाजपा किसी एक 'महत्वाकांक्षी' के साथ सत्ता निर्माण का 'खेल' कर सकती है. ■

एक सरपट चर्चा यह भी...

सपा में बड़ी तेज चर्चा है. छह अक्टूबर को आजमगढ़ रैली में मुलायम के सत्ता अधिग्रहण की घोषणा होगी. मुलायम के मुख्यमंत्रित्व और नेतृत्व में सपा चुनाव लड़ेगी. यह चर्चा भले ही चंडूखाने से निकली हो, लेकिन दौड़ सरपट रही है. यह भी शिगूफा उड़ रहा है कि अखिलेश मुख्यमंत्री का पद नहीं सौंपेंगे और विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर अपने 'केयर-टेकिंग' में चुनाव कराएंगे. चर्चा तो चर्चा है, लेकिन बहुत दमदार है. ■

चुन-चुन कर मारेंगे, भले ही चुनाव हारेंगे

'चुन-चुन कर मारेंगे, भले ही चुनाव हारेंगे' वाला हास्य संवाद सपा के गलियारे में खूब चल रहा है. यह चर्चा सरगर्म इसलिए भी है कि मुख्यमंत्री के पर कतरे जाने का सिलसिला तेजी से जारी है. मुलायम के आदेश पर अखिलेश यादव ने मंडी परिषद के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया. लोक निर्माण विभाग की तरह ही बड़े बजट वाले विभाग के रूप में मंडी परिषद की पहचान है. मुलायम के करीबी काशीनाथ यादव को मंडी परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है. अखिलेश को दरकिनार करके सपा में संगठनात्मक तौर पर बदलाव की गति तेज कर दी गई है. चार और विधायकों के निष्कासन की तैयारी है. संग्राम यादव, मुकेश श्रीवास्तव, राजू यादव और एमएलसी संतोष यादव सनी अब शिवपाल के निशाने पर हैं. इनके अलावा 60 अन्य लोगों को भी ठिकाने लगाने की भूमिका तैयार है. दरअसल, उन सारे सपाइयों को बाहर निकाला जा रहा है, जो अखिलेश के समर्थन में सड़कों पर उतर आए थे. उन्हें अनुशासनहीन करार दिया जा रहा है. ■

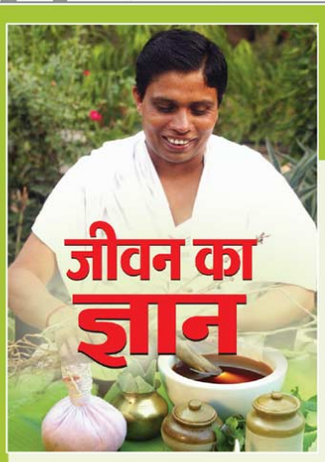

कटेरी

परिचय

इसका पौधा झाड़ी के रूप में जमीन पर फैला हुआ होता है. इसको देखने से ऐसा लगता है, जैसे कोई क्रोधित नागिन शरीर पर अनेकों कांटो का वस्त्र ओढ़े गर्जना करती हुई मानो कहती हो, मुझे कोई छूना मत. कटेरी में इतने कांटे होते हैं कि इसे छूना दुष्कर है, इसीलिए इसका एक नाम दुःस्पर्शा है. यह मूलतः उष्णकटिबंधीय एशिया में पाया जाता है तथा विश्व में दक्षिण-पूर्व एशिया, मलेशिया, मलाया, ऑस्ट्रेलिया एवं पॉलिनेशिया में भी पाया जाता है. भारत के उष्ण प्रदेशों में यह खरपतवार के रूप में सड़कों के किनारे एवं रिक्त स्थानों पर तथा हिमालय पर 2200 मीटर की उंचाई तक पाया जाता है. कटेरी की कई प्रजातियां होती हैं परन्तु मुख्यतया तीन प्रजातियों 1. छोटी कटेरी, 2. बड़ी कटेरी तथा 3. श्वेत कंटकारी का प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है.

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

- **शिरो रोग-** कटेरी क्वाथ, गोखरू क्वाथ तथा लाल धान के चावल से निर्मित ज्वरनाशक पेय का थोड़ी-थोड़ी मात्रा में दिन में तीन-चार बार सेवन करने से ज्वर द्वारा उत्पन्न पसलियों और सिर की पीड़ा का शमन होता है.
- कटेरीफल स्वरस को माथे पर लेप करने से मस्तक शूल का शमन होता है.
- **नेत्रपीड़ा-** कटेरी के 20-30 ग्राम पत्तों को पीसकर उनकी लुगदी बनाकर आंखों पर बांधने से आंखों का दर्द दूर होता है.
- **जुकाम-** मौसम के बदलने पर नजला, जुकाम व बुखार हो जाया करता है, उसमें पित्तपापड़ा, गिलोय और छोटी कटेरी सबको समान मात्रा में लेकर आधा ली पानी में पकाकर चतुर्थांश शेष काढ़ा पिलाने से बहुत लाभ होता है.
- **दंतशूल-** अगर दाढ़ बहुत दुःखती हो तो कटेरी के बीजों को धुआं लेने से तुरन्त आराम होता है. कटेरी की जड़, छाल, पत्ते और फल लेकर उनका काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से दंतशूल का शमन होता है.
- **कण्ठ रोग-** 10-20 मिली कटेरी फल स्वरस को पीने से गले की सूजन में लाभ होता है.
- **खांसी-** आधा से एक ग्राम कटेरी पुष्प चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर चटाने से बालकों की सब प्रकार की खांसी दूर होती है.
- समभाग छोटी कटेरी, गुडूची तथा सोंठ के 50 मिली क्वाथ में 2 ग्राम पिप्पली चूर्ण मिलाकर पीने से सांस फूलना, खांसी, अरुचि, शूल, अजीर्ण तथा ज्वर में लाभ होता है.
- **दमा-** कटेरी की प्रसिद्धि कफ के नाश करने के संबंध में बहुत अधिक है. कफ, ज्वर, दमा, छाती का दर्द इत्यादि रोगों में इसका बहुत प्रयोग होता है. जब छाती में कफ भरा हुआ हो तब इसका 20-30 मिली काढ़ा देने से बहुत लाभ होता है. इसके फलों के 20-30 मिली काढ़े में 500 मिग्रा भुनी हुई हींग और एक ग्राम सेंधा नमक डालकर पीने से भयंकर दमा में भी लाभ होता है.
- **उदरशूल-** कटेरी के फलों के बीज निकाल कर उनको छाछ में डालें तथा उबालकर सुखा दें, फिर उनको रातभर मट्ठे में डुबोएं तथा दिन में सुखा लें. ऐसा 4-5 दिन तक करके उनको घी में तलकर खाने से उदर-शूल तथा पित्तज विकारों का शमन होता है.
- कटेरी के 10-20 मिली स्वरस को मट्ठे में मिलाकर, कपड़े से छानकर पिलाने से पेशाब की रुकावट में लाभ होता है.
- कटेरी की जड़ और गिलोय को समभाग मिलाकर क्वाथ बना लें. 10-20 मिली क्वाथ को प्रातः सायं पिलाने से ज्वर तथा सर्वांगशूल का शमन होता है.
- कटेरी की जड़, सोंठ, बला-मूल, गोखरू तथा गुड़ को समभाग लेकर दूध में पकाकर, 20-40 मिली सुबह-शाम पीने से मल-मूत्र की रुकावट, ज्वर तथा सूजन का शमन होता है.

श्वेत कंटकारी के प्रयोग

- **शिरो रोग-** श्वेत कंटकारी के पांच से 10 मिली फल स्वरस में मधु मिलाकर सिर में लगाने से इन्द्रलुप्त में लाभ होता है.
- **दंतशूल-** श्वेत कंटकारी के बीजों का धूमपान के रूप में प्रयोग करने से दंतशूल तथा दंतकृमि में लाभ होता है.
- श्वेत कंटकारी के एक से दो ग्राम फल चूर्ण में मक्खन मिलाकर सेवन करने से कास में लाभ होता है.
- **हृदय विकार-** एक से दो ग्राम श्वेत कंटकारी मूल त्वक् चूर्ण का सेवन करने से हृदय विकारों में लाभ होता है.
- **अतिसार-** श्वेत कंटकारी के एक से दो ग्राम फल चूर्ण का सेवन छाछ के साथ करने से अतिसार में लाभ होता है.
- **अर्श-** श्वेत कंटकारी के फलों को कोशातकी के क्वाथ में पकाकर प्रयोग करने से अर्श में लाभ होता है.
- **त्वचा रोग-** श्वेत कंटकारी मूल को पीसकर लेप करने से कण्डू, क्षत तथा व्रण में लाभ होता है.

प्रयोज्यांग : पंचांग, मूल, पत्र, काण्ड, पुष्प, फल तथा बीज.
मात्रा : क्वाथ 20-25 मिली अथा चिकित्सक के परामर्शानुसार.

आचार्य बालकृष्ण

ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना...

84 वर्ष की आयु, शरीर अस्वस्थ, भूख लगभग समाप्त, लेकिन फिर भी पौधों को पानी देते रहना, गौशाला में चारा-गुड़ भेजना, परिवार के एक-एक सदस्य को फोन करके हालचाल पूछना, दूरदराज के कमजोर सगे संबंधियों को काम धंधे में लगाना, मिलने आने वालों से राजनीति के गिरते स्तर पर चर्चा करना, यही सब तो उस प्रेरक व्यक्तित्व का नित्यप्रति का रूटीन था. आज जब वे बैकुंठधाम की अपनी यात्रा पर सबको रोता बिलखता छोड़कर निकल चुके हैं, तो एक-एक घटनाक्रम मानस पटल पर चलचित्र की तरह चलते नजर आ रहे हैं.

पिताजी, श्री ईश्वर प्रकाश गुप्ता जी का जीवन संघर्षों से भरा रहा. 1969 से 1975 तक देशभर में घूम-घूम कर संघ साहित्य और पत्रिकाओं का प्रचार किया. आपातकाल (1975-77) के काल में सत्याग्रह में शामिल हुए और उसके बाद 10/10 के कमरे से राष्ट्रीय एडवरटाइजिंग एजेंसी की शुरुआत की. पूरी ईमानदारी और मेहनत की वह एक लंबी कहानी है, लेकिन कभी विचारों और उसूलों से समझौता नहीं किया. नियमित शाखा में जाना, 3-4 घंटे प्रतिदिन संघ कार्य में लगाना. यही दिनचर्या का हिस्सा थे. बाद में सेवा भारती के अनेक प्रकल्पों में काम किया और 1990 में केशव धर्मार्थ हॉस्पिटल शुरू किया. जिसका उद्घाटन श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था. पिताजी की अपने इस सेवा कार्य के प्रति इतनी निष्ठा थी कि कभी गर्मी, सर्दी और बरसात की परवाह नहीं करते थे. समय से जाना, मरीजों को दवाएं बांटना, उनके दुखदर्द की चर्चा करना इसी में पूरा समय लगाते रहे. हर वर्ष शरद पूर्णिमा पर हजारों दमा के मरीजों को निःशुल्क दवा बांटते थे. घर आने वालों को तुलसी के पौधे देना, उनकी आदत का विशेष हिस्सा था. विश्व हिंदू परिषद के स्व. अशोक सिंघल, पूज्य सुधांशु जी महाराज और अनेक साधू-संतों से उनकी अच्छी घनिष्ठता थी. हममें अच्छे संस्कार आएं, इसके लिए जो भी संभव हो पाता था, करते थे. हमें पंचतंत्र और लोककथाओं की पुस्तकें लाकर देते थे, ताकि शिक्षाप्रद कहानियों से सुविचार मिलें. साइकिल पर बैठाकर संघ की शाखा में ले जाते थे.

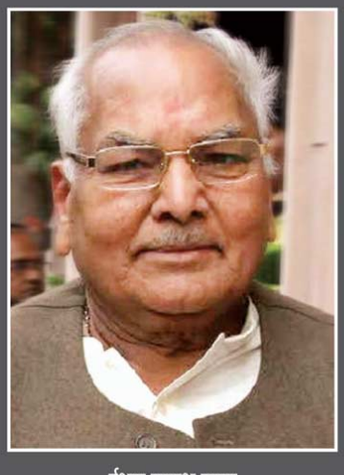

ईश्वर प्रकाश गुप्ता

पारिवारिक मूल्य और सिद्धांत बचे रहे, सदस्य अलग-अलग रहते हुए भी एक रहें, इसका हमेशा प्रयास करते थे. उन्होंने तय किया कि हर रविवार को दोपहर का भोजन हम तीनों भाइयों के परिवारों का एक स्थान पर होगा. कभी फार्म हाउस पर तो कभी घर पर. लाभ यह रहा कि पूरा 20-22 लोगों का परिवार एकत्र होने लगा. एक दूसरे के सुखदुख में सहभागी बनने का, बिजनेस संबंधी सहयोग लेने-देने का और प्रेम प्यार का सिलसिला शुरू हो गया जो अब तक भी चल रहा है. कभी किसी का मनमुटाव हुआ भी, जो स्वाभाविक रूप से हर जगह होता भी है, तो तुरंत हस्तक्षेप कर के हल करा देते थे. आज अधिकांश परिवारों में भाइयों में अनबन देखने को मिलती है, लेकिन पिताजी के दिखाए मार्ग पर चलकर कोई भी परिवार एकता की मिसाल बन सकता है.

कहते हैं पिता के पुरूषार्थ का लाभ भी बच्चों को मिलता है. पिताजी सच्चे गोभक्त थे. नियमित गौशाला जाते थे. वहां जाकर गायों को चारा-गुड़ खिलाते, होली-दिवाली पर कर्मचारियों को स्वेटर, शाल, कंबल, मिठाई आदि बांट कर आते थे.

अक्सर सब्जी, फल और नर्सरी से पौधे लेने स्वयं जाते थे. दुकानदार की कमजोर हालत देखकर उसे उधार पैसा भी दे देते थे और जब वह 4-6 महीने बाद ब्याज सहित लौटाता तो मुस्कुराकर ब्याज वापिस कर देते थे.

उन्होंने जीवन में अपनी माताजी (हमारी दादी जी) की काफी सेवा की थी. अपनी सफलता का श्रेय भी मां की सेवा को देते थे.

उस महामानव के संघर्षपूर्ण जीवन ने हम सबको सिखाया है जीवन में सिद्धांतों से कभी समझौता न करना, स्वयं को समाज के लिए समर्पित करना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना और पारिवारिक एकता को बनाएं रखना.

प्रकृति का नियम है पतझड़ और बसंत. पड़पौत्र और पड़पौत्री के रूप में नई पीढ़ी का आगमन भी वे देख चुके थे. ऐसे प्रेरणापुंज के जाने का अभाव कभी पूरा नहीं हो सकता. बैकुंठधाम से उनका आशीर्वाद और स्नेह हमेशा बरसता रहेगा. भले ही सशरीर वे नहीं होंगे, लेकिन उनकी आवाज हमेशा कानों में गूंजती रहेगी, उनकी उपस्थिति का अहसास कराती रहेगी. उनके लगाए पौधों के पत्तों की सरसराहट, फूलों की महक और आंगन में कबूतर, तोते और चिड़िया जो उनके द्वारा खिलाए जाने वाले दाने के लिए आते थे, उनका संदेशा लाते रहेंगे. उस महान कर्मयोगी देशभक्त व्यक्तिगत के चरणों में हम सबका शत्-शत् नमन.

-राकेश गुप्ता

साईं वंदना

श्री साईं-सच्चरित्र में कर्म-सिद्धांत

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

स्व. श्री गांविंद रघुनाथ दाभोलकर (हेमाडपंत) द्वारा रचित 'श्री साईं सच्चरित्र' के सैंतालीसवें अध्याय में श्री साईंनाथ महाराज द्वारा अपने एक भक्त को सुनाई गई एक कथा का उल्लेख है. बाबा ने उस कथा को अपने जीवन का अनुभव बतलाया, जिसमें के दो चरित्रों- वीरभद्रप्पा (सांप) और वासप्पा (मेंढक) के साथ पिछले जन्मों में उनका संबंध रहा था. जैसा कि कथा में है कि एक बार जब बाबा एक गांव में जा रहे थे, तो उन्हें एक मेंढक की दर्द भरी आवाज सुनने को मिली. उस पीड़ा भरी आवाज को सुनकर उन्हें दया आ गई. वे उस मेंढक को ढूंढते हुए एक नदी के किनारे पहुंचे और देखा कि उसे एक सांप निगलने की कोशिश कर रहा है. जो भी बाबा के संपर्क में आया, उसका भूत, वर्तमान और भविष्य जानने की बाबा में दिव्य क्षमताएं थीं. उस सांप और मेंढक की इस घोर/जानलेवा शत्रुता को देखकर बाबा ने उन्हें उनके पिछले जन्म के द्वेषपूर्ण संबंध का स्मरण कराते हुए उनको अलग करने का प्रयास किया. बाबा ने सांप यानि वीरभद्रप्पा से कहा कि उसने और मेंढक यानी वासप्पा ने अपने पूर्वजन्म में पारस्परिक शत्रुता के कारण एक-दूसरे को जान से मार डाला था. अपने पिछले जन्मों के पाप-कर्मों के फलस्वरूप वे इस जन्म में सांप और मेंढक के रूप में पैदा हुए और चूंकि एक-दूसरे के प्रति शत्रुता के विचार उनके इस जन्म में भी रहे, अतः इस रूप में फिर से लड़ने के लिए वे अनजाने ही प्रेरित हुए. बाबा ने सांप से मेंढक को छोड़ देने के लिए कहा ताकि उनके बीच पूर्वजन्म से चला आता रहा शत्रुता का बीज अगले जन्म तक न जाए. बाबा के वचन सुनकर सांप (वीरभद्रप्पा) ने मेंढक (वासप्पा) को छोड़ दिया, जो कि नदी में कूद कर गायब हो गया. इस प्रकार की कथाएं हिंदू लोक-गाथाओं में बच्चों को सुनाई जाने वाली सुंदर सांकेतिक नीतिकथा के रूप में देखने को मिलती हैं. पर इसको गहराई से देखने पर यह रहस्य उद्घाटित होता है कि श्री साईंनाथ महाराज भारतीय अध्यात्म-विज्ञान के कर्म के मौलिक सिद्धांत की ओर इंगित कर रहे हैं.

'कर्म-सिद्धांत' का पहला नियम यह है कि पूर्व जन्मों के अच्छे और बुरे कर्मों का फल अगले जन्म में अवश्य फलेगा.

जिनके साथ पिछले जन्मों में किसी का अच्छा संबंध होगा, तो वे अगले जन्म में मित्र बनेंगे और जिनके साथ पिछले जन्मों में बुरा संबंध होगा तो वे अगले जन्म में उनके शत्रु बनेंगे. दूसरा सिद्धांत यह है कि प्रकृति की अदृश्य शक्तियां अपने नियमानुसार उन दोनों को अवश्य मिला देंगी और पूर्व जन्म के कर्मानुसार उन दोनों के बीच अच्छी और बुरी घटना को घटित करेंगी. तीसरा सिद्धांत यह है कि 'माया' (प्रकृति) के खेल के कारण इनके संबंध किसी भी सामाजिक रिश्ते के रूप में बनेंगे, जैसे- मित्र-मित्र, भाई-भाई, पति-पत्नी, मालिक-नौकर, पिता-पुत्र, प्रेमी-प्रेमिका आदि. यहां तक कि ये संबंध मनुष्य-पशु/पक्षी या पशु-पशु के रूप में भी हो सकते हैं. बाबा ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि किसी भी प्राणी का किसी अन्य प्राणी से तब तक कोई संबंध नहीं हो सकता है जब तक कि पिछले जन्म में उनका आपस में कोई संबंध न रहा हो, चाहे उन्हे अपने पूर्व-जन्म की घटनाएं याद न हों. हम अपनी आम जिन्दगी में यह अक्सर अनुभव करते हैं कि बहुत बार, तथाकथित सामाजिक-संबंध अप्रिय/दुर्भावनापूर्ण मोड़ ले लेते हैं. हम यह भी अनुभव करते हैं कि कभी-कभी कोई व्यक्ति जिसके साथ हमारा सबसे अच्छा मित्र बन जाता है. मानव-समाज का इतिहास इस प्रकार के कटुतापूर्ण पारस्परिक सामाजिक संबंध नहीं हो, वह कभी-कभी हमारा सबसे अच्छा मित्र बन जाता है. मानव-समाज का इतिहास इस प्रकार के कटुतापूर्ण पारस्परिक विद्वेष के उदाहरणों से भरा पड़ा है, जिसमें पिता-पुत्रों, भाई-भाईयों, पति-पत्नियों का जीवन दूभर हो गया है. और उन्होंने एक-दूसरे का विनाश किया है. जब तक कोई व्यक्ति जन्म-जन्मांतर से चली आ रही इस वैमनस्य की मानसिकता या अशुभ भावनाओं को खत्म करने के लिए कुछ विशेष यत्न न करे, ऐसी ही स्थिति अगले कुछ जन्मों तक अवश्य ही रहेगी. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं ने आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

पैरालिम्पिक खेल

भारतीय खिलाड़ियों ने बढ़ाया देश का मान

रियो ओलम्पिक के दर्द को भले ही सिंधु व साक्षी ने थोड़ा कम किया हो, पर पैरालिम्पिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने स्वर्णिम सफलता के बलबूते पूरे देश को गौरव का एहसास कराया है. उनका प्रदर्शन इस बात का गवाह है कि अक्षम होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उसे ताकत के रूप में लेना भी बड़ी बात है. दिव्यांग या विकलांग होने बाद कुछ लोग जिंदगी की जंग हार जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अपने हुनर में इतना रम जाते हैं कि वह आए दिन नया इतिहास बनाने में विश्वास रखते हैं. पैरालिम्पिक खेलों में भी कुछ इसी तरह का देखने को मिला.

सैयद मोहम्मद अब्बास

अभी कुछ ही दिन पहले रियो ओलम्पिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे. ओलम्पिक की नाकामी का पोस्टमार्टम भी हो रहा है लेकिन उसी जगह पर पैरालिम्पिक खिलाड़ियों ने भारत का झंडा बुलंद कर दिया है. रियो ओलम्पिक के दर्द को भले ही सिंधु व साक्षी ने थोड़ा कम किया हो पर पैरालिम्पिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने स्वर्णिम सफलता के बलबूते पूरे देश को गौरव का एहसास कराया है. उनका प्रदर्शन इस बात का गवाह है कि अक्षम होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उसे ताकत के रूप में लेना भी बड़ी बात है. दिव्यांग या विकलांग होने बाद कुछ लोग जिंदगी की जंग हार जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अपने हुनर में इतना रम जाते हैं कि वह आए दिन नया इतिहास बनाने में विश्वास रखते हैं. पैरालिम्पिक खेलों में भी कुछ इसी तरह का देखने को मिला. इसका ताजा उदाहरण देवेंद्र झाझरिया का गोल्ड मेडल है. मरियप्पन थांगावेलू के ऊंची कूद में स्वर्णिम प्रदर्शन ने पूरे भारत को जश्न मनाने का मौका दिया है. इतना ही नहीं दीपा मलिक ने 4.61 मीटर शॉटपट फेंककर भारतीय पैरालिम्पिक खेलों के इतिहास में नया प्रतिमान स्थापित किया है. वरुण सिंह भाटी का पोलियो होने के बावजूद कभी हार न मानने का जज्बा भी पैरालिम्पिक खेलों में देखने को मिला. उन्होंने कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ा दिया है. हालांकि यह बात भी सत्य है कि पैरालिम्पिक खेलों को उतनी तवज्जो नहीं मिलती, जितनी आम खेलों को मिलती है.

इतिहास के पन्नों को पलटें तो ओलम्पिक से बेहतर प्रदर्शन करते हैं पैरालिम्पिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी. साल 1972 में हैडिलवर्ग पैरालिम्पिक खेलों में भारत के मुरलीकांत पेटकर ने तैराकी में स्वर्ण जीतकर भारत को इस खेल में नई पहचान दिलाई थी. बहुत कम लोग जानते हैं कि मुरलीकांत पेटकर टेबल टेनिस में भी भाग ले चुके हैं, लेकिन असली कामयाबी उन्हें तैराकी में मिली. 1984 में स्टोक मैंडाविल पैरालिम्पिक खेलों में भारत की तरफ से जोगिंदर सिंह बेदी ने एक सिल्वर और दो ब्रांज मेडल जीतकर पैरालिम्पिक खेलों में नया इतिहास बनाया. 2004 में देवेंद्र ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था. इतना ही नहीं राजिंदर ने पावरलिफ्टिंग में पदक अपने नाम किया, जबकि 2012 में गिरिशा ने ऊंची कूद में रजत पदक पर कब्जा किया था. यह बातें अतीत की थीं लेकिन वर्तमान में भी भारतीय खिलाड़ी हर दिन नया इतिहास बना रहे हैं. रियो पैरालिम्पिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन काबिले-तारीफ है. देवेंद्र झाझरिया की बात की जाए तो उन्होंने अपने दमदार प्रदर्शन से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. देवेंद्र ने 63.97 मीटर में भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया. राजस्थान के चुरू जिले के रहने वाले झाझरिया का बिजली के करंट लगने के कारण दायां हाथ खराब हो गया था लेकिन उन्होंने इसके बाद कड़ी मेहनत करते हुए स्कूली स्तर पर जानदार प्रदर्शन किया. इसके बाद जैवलिन थ्रो में वह लगातार कामयाबी की ओर बढ़ते रहे. राज्य स्तर पर वह कई बार चैम्पियन भी रहे. उनकी असली प्रतिभा साल 2004 के एथेंस में पैरा ओलंपिक खेलों में देखने को मिली जब उन्होंने वहां 62.15 मीटर के साथ नया रिकॉर्ड बना डाला. इससे पूर्व विश्व चैम्पियनशिप में वह स्वर्ण जीत चुके हैं. 2014 के एशियन गेम में सिलवर मेडल जीतकर उन्होंने अपना लोहा मनवाया था. 2001 में बुसान में आयोजित प्रतियोगिता में पहली बार गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने सनसनी फैला दी थी. देवेंद्र को इस शानदार सफलता के लिए 2005 में अर्जुन अवॉर्ड और 2012 में पद्मश्री भी दिया गया. दूसरी ओर मरियप्पन थांगावेलू एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं. दरअसल उनकी मां सरोजा सब्जी बेचकर किसी तरह से घर चलाती हैं. मरियप्पन जब पांच साल के थे एक सरकारी बस ने उन्हें टक्कर मार दी जिसमें उनका पैर खराब हो गया. 17 साल मुकदमा लड़ने के बाद दो लाख रुपये का मुआवजा मिला. पढ़ाई के दौरान मरियप्पन के हुनर को पहचाना गया और तराशा गया, जिसके बाद वे बड़े मंच पर चमक दिखा रहे हैं. अब जब रियो पैरालिम्पिक खेलों में उन्होंने पदक जीता तो उनके ऊपर इनामों की बौछार होने लगी है.

एक और पदक विजेता 45 साल की दीपा मलिक ने शॉटपुट में रजत पदक जीतकर साबित किया कि अगर हौसला हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है. दीपा चल फिर नहीं सकती हैं लेकिन रियो में उन्होंने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है. दीपा मलिक की जिंदगी देखें तो शायद उस सीमा पर कोई भी व्यक्ति टूट जाए. लेकिन उन्होंने अपने हौसले से जुग जीत लिया. दीपा रिटायर्ड कर्नल बिक्रम सिंह की पत्नी हैं. उन्हें तब लकवा मार गया था, जब उनके पति करगिल में देश के लिए युद्ध लड़ रहे थे. अनगिनत ऑपरेशनों के बावजूद उन्हें व्हीलचेयर पर जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, लेकिन उन्होंने शॉटपुट की दुनिया में अपना अलग मुकाम बना लिया है. कुल मिलाकर दिव्यांग खिलाड़ियों के जज्बे को सलाम करना चाहिए, जिन्होंने अपने प्रदर्शन की बदौलत देश का नाम रौशन किया है. ■

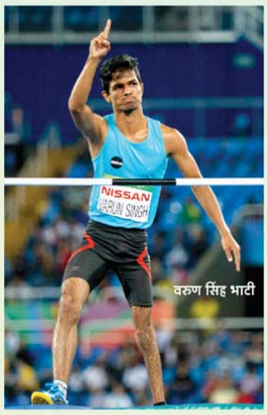

वरुण सिंह भाटी

देवेंद्र झाझरिया

मरियप्पन थांगावेलू

दीपा मलिक

जर्मनी की एंजेलिक कर्बर का यूएस ओपन में जलवा

खत्म हो गया सेरेना का दौर

एंजेलिक कर्बर

साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में कई बड़े उलट फेर देखने को मिले. नडाल से लेकर सेरेना विलियम्स को इस बार यूएस ओपन में निराशा हाथ लगी. दोनों ही खिलाड़ी खिताब के तगड़े दावेदार माने जा रहे थे. इतना ही नहीं सेरेना के लिए यह टूर्नामेंट उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और नम्बर-वन का ताज भी उनके हाथ से निकल गया. जोकोविच ने किसी तरह से फाइनल तक का सफर तय किया लेकिन नडाल की गाड़ी चौथे राउंड में ही पटरी से उतर गई. युवा फ्रांसीसी टेनिस खिलाड़ी लुकस पुइल ने 14 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता राफेल नडाल को चौथे दौर में हराकर प्रतियोगिता में सनसनी फैला दी. हालांकि बाद में वह खिताब तक नहीं पहुंच सके. वहीं जोकोविच को खिताबी जंग में स्विटजरलैंड के स्टेन वावरिंका से हार का मुंह देखना पड़ा. दूसरी ओर महिला वर्ग में भी चौंकाने वाला परिणाम देखने को मिले. जर्मनी की एंजेलिक कर्बर ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए फाइनल में 10वीं वरीयता प्राप्त चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब भी अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ ही एंजेलिक कर्बर ने विश्व टेनिस रैंकिंग में चोटी का स्थान भी हासिल कर लिया. यूएस ओपन के शुरुआती दौर में कई खिलाड़ियों ने खिताब जीतने का दावा किया था. बात अगर महिला वर्ग की बात की जाये तो सेरेना हर बार की तरह यहां भी टूर्नामेंट जीतने की पहली पसंद थी लेकिन उनकी बढ़ती हुई उम्र और खराब फिटनेस ने उनका साथ नहीं दिया. सेरेना का टेनिस करियर बेहद चमकदार रहा है. खासकर बड़े टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन देखने लायक होता है. यूएस ओपन की हार के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या अब उनका दौर खत्म हो गया है?

बात अगर यूएस ओपन की जाये तो जर्मनी की एंजेलिक कर्बर पूरे टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन किया. फाइनल में उन्होंने चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को कड़े मुकाबले में 6-3, 4-6, 6-4 से धूल चटाते हुए खिताब पर कब्जा किया. जर्मनी के लिए अरसे बाद किसी खिलाड़ी ने इतना दमदार प्रदर्शन किया है. इससे पूर्व जर्मनी के लिए स्टेफी ग्राफ चमकता हुआ सितारा हुआ करती थी. यह स्टेफी ग्राफ ही थी जिन्होंने टेनिस की दुनिया में जर्मनी का खूब मान बढ़ाया. 90 के दशक में स्टेफी ग्राफ लगातार खिताबों की झंडी लगा रही थी. उन्होंने एक नहीं 22 ग्रैंड स्लैम जीतकर एक नया इतिहास बनाया था. इतना ही नहीं वह नम्बर वन खिलाड़ी भी बनी. उनके जाने के बाद जर्मनी के पास खासकर महिला खिलाड़ियों में कोई बड़ा नाम नहीं था. अब एंजेलिक कर्बर में जर्मनी को नया स्टार खिलाड़ी मिल गया है. एंजेलिक कर्बर में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. 28 वर्षीय जर्मन खिलाड़ी ने इससे पूर्व ऑस्ट्रेलियन ओपन में सेरेना को हराकर पहला ग्रैंड स्लैम जीता था लेकिन विम्बल्डन फाइनल में सेरेना ने उन्हें करारी शिकस्त दी. इस बार उन्होंने यूएस ओपन सभी बाधाओं को पार करते हुए दूसरा ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया. किसी जर्मन खिलाड़ी 20 साल बाद यूएस में खिताब जीता है. 1996 में स्टेफी ग्राफ ने यहां जीत हासिल की थी. एंजेलिक कर्बर ने अपने टेनिस करियर की शुरुआत 2003 में की थी. उन्होंने अब दस डब्लूटीए खिताब अपने नाम किया है. इसके साथ ही एंजेलिक कर्बर 11 आईटीएफ खिताब जीता है. करियर में उन्होंने ग्रैंड स्लैम जैसी बड़ी प्रतियोगिता में ठीक-ठाक प्रदर्शन किया है. इस साल उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब भी अपने नाम किया था. हाल में खत्म हुए रियो ओलम्पिक में जर्मनी की तरफ से खेलती हुई सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रही है. 2016 उनके लिए बेहद सफलता भरा रहा है. उन्होंने इस साल दो ग्रैंड स्लैम जीतने के आलावा विम्बलडन के फाइनल में भी प्रवेश किया था लेकिन सेरेना ने उनके खिताब जीतने के सपने को तोड़ दिया था.

सेरेना विलियम्स

यूएस ओपन के शुरुआती दौर में कई खिलाड़ियों ने खिताब जीतने का दावा किया था. बात अगर महिला वर्ग की बात की जाये तो सेरेना हर बार की तरह यहां भी टूर्नामेंट जीतने की पहली पसंद थी लेकिन उनकी बढ़ती हुई उम्र और खराब फिटनेस ने उनका साथ नहीं दिया. खासकर बड़े टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन देखने लायक होता है. यूएस ओपन की हार के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या अब उनका दौर खत्म हो गया है?

इस बार यूएस ओपन के पुरुष वर्गों में भी कई बड़े उलटफेर देखने को मिले. नडाल व जोकोविच का जादू इस बार नहीं चल सका. स्टेन वावरिंका ने जहां खिताब जीता तो वहीं लुकस पुइल ने नडाल को कड़े संघर्ष के बाद पराजित किया. दरअसल जोकोविच और नडाल की तूती इस समय टेनिस जगत में बोलती है. स्विटजरलैंड के स्टेन वावरिंका ने हाल के दिनों अपने दमदार खेल से चोटी के कई खिलाड़ियों के पसीने छुड़ाये हैं. जूनियर स्तर पर अपनी छाप छोड़ने वाले स्टेन वावरिंका ने करियर में अब तक 15 खिताब जीते हैं. वावरिंका ने ग्रैंड स्लैम में भी अच्छा प्रदर्शन किया है. उन्होंने इस साल यूएस ओपन जीता जबकि इससे पूर्व वावरिंका ने 2014 ऑस्ट्रेलियाई ओपन व 2015 में फ्रेंच ओपन जैसे बड़े खिताब अपने नाम किया. वावरिंका के प्रदर्शन से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने करियर में कई बार बड़े खिलाड़ियों को धूल चटाई है. उनमें रोजर फेडरर को हार का मुंह देखना पड़ा है. दूसरी ओर जोकोविच का प्रदर्शन भले ही इस टूर्नामेंट में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा हो लेकिन उनके खेल में दम है. यह जोकोविच है जिन्होंने रोजर फेडरर व नडाल जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को अपने खेल से काबू में कर रखा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

ऐश्वर्या के इंटीमेट सीन पर क्या बोले अमिताभ?

इन दिनों करण जौहर निर्देशित फिल्म *ऐ दिल है मुश्किल* के टीज़र दिखाए जा रहे हैं. इसमें ऐश्वर्या के कुछ इंटीमेट सीन भी नज़र आ रहे हैं. हाल ही में इस बारे में अमिताभ बच्चन से पूछ लिया गया. अमिताभ ने मासूम सा जवाब दिया कि उन्होंने *ऐ दिल है मुश्किल* का टीज़र ही नहीं देखा. सोशल मीडिया पर एक्टिव अमिताभ ने टीज़र नहीं देखा, इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है. पिछले कुछ दिनों से चर्चा हो रही है कि *ऐ दिल है मुश्किल* में रणबीर और ऐश्वर्या के अंतरंग सीन को लेकर बच्चन्स नाराज़ हैं. हालांकि बच्चन्स से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ये बातें मनगढ़ंत हैं. बच्चन परिवार में सभी अभिनेता हैं और वे इस तरह की बातों से प्रभावित नहीं होते.

ऐश्वर्या राय बच्चन भी जानती हैं कि उन्हें अब किस तरह के दृश्य करना है. *ऐ दिल है मुश्किल* में उन्हें रणबीर को किस करना था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया.■

अभी बाकी है आमिर–अजय का धमाका

प्रवीण कुमार

साल 2016 ख़त्म होने में सिर्फ 4 महीने बचे हैं. लेकिन बॉक्स ऑफिस अभी भी बेहतरीन फिल्मों का इंतज़ार कर रही है. कोई शक नहीं कि फिल्मों के मामले में यह साल कुछ ख़ास नहीं रहा. जहां एक तरफ एक के बाद एक कई बड़ी फिल्में औंधे मुंह गिरी हैं. ताजा उदाहरण मोहनजोदड़ो का लिया जा सकता है. वहीं इस साल कम बजट की कुछ फिल्मों ने बाज़ी मारी. जिसमें नीरजा, सनम रे, बागी, जय गंगाजल, वज़ीर, हैप्पी भाग जाएगी आदि फिल्में शामिल हैं.

इस साल की फिल्मों की लिस्ट देखी जाए तो सलमान खान की फिल्म सुल्तान, अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट, रूस्तम और सोनम कपूर की नीरजा सबसे ज्यादा पसंद की गई. जबकि फैन, मोहनजोदड़ो जैसी बड़ी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धोखा दे दिया. लेकिन अभी भी कुछ फिल्मों से हमारी उम्मीद जुड़ी हुई है. इनमें आमिर खान की दंगल, अजय देवगन की फिल्म शिवाय, करण जौहर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल और शुशांत राजपूत की एम.एस. धोनी: दि अनटोल्ड स्टोरी शामिल है. उम्मीद है कि ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर पाएंगी. साल के अखिरी महीनों में कुछ बड़ी फिल्में जो रिलीज़ होने वाली हैं वह बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी या नहीं यह तो दर्शक ही बताएंगे जिसका वह बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहें है.

एम.एस. धोनी

नीरज पांडे के निर्देशन में बन रही इस फिल्म से फैंस को काफी उम्मीदें हैं. कोई शक नहीं कि यह फिल्म बॉलीवुड फैंस के साथ–साथ क्रिकेट फैंस को भी आकर्षित कर रही है. फिल्म में मुख्य किरदार सुशांत सिंह राजपूत निभा रहे हैं. एम.एस. धोनी 30 सितंबर को रिलीज़ हो चुकी है और फिल्म को अच्छा रिसपॉन्स मिल रहा है. यू–ट्यूब पर एम.एस. धोनी के ट्रेलर को 2016 में अब तक सबसे ज्यादा देखा गया है.

शिवाय

अजय देवगन की फिल्म शिवाय अपने ट्रेलर से ही धमाका कर चुकी है. फिल्म 28 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर रिलीज़ होगी. इस फिल्म से ख़ासकर देवगन फैंस को काफी उम्मीदें हैं. फिल्म का बजट भी लगभग 150 करोड़ रूपये बताया जा रहा है. इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन की भरमार है. इस फिल्म का क्रेज लंबे से दर्शकों के बीच चलता आ रहा है.

ऐ दिल है मुश्किल

शिवाय के साथ ही 28 अक्टूबर को रिलीज़ होगी करण जौहर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल. जिसमें रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय स्टारर यह फिल्म काफी सुर्खियां बटोर रही हैं.

डियर ज़िंदगी

गौरी शिंदे के निर्देशन में बन रही फिल्म ख़ासकर इसलिए चर्चा में है, क्योंकि पहली बार शाहरूख खान और आलिया भट्ट सिल्वर स्क्रीन पर साथ दिखेंगे. फिल्म 25 नवंबर को रिलीज़ होगी.

दंगल

आमिर खान की फिल्म दंगल 23 दिसंबर को रिलीज़ होगी. जब फिल्म आमिर खान की हो तो कुछ और कारण होने की जरूरत नहीं. दंगल इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्म है जिसका आमिर खान के फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहें है.■

भूल गईं 'बार बार देखो' की नाकामयाबी

कैटरीना को सलमान का तोहफा

सलमान के कहने पर ही कैटरीना को फिल्म से जोड़ा गया है. फिल्म के निर्माता–निर्देशक चाहते थे कि कैटरीना की जगह किसी नई हीरोइन को लिया जाए ताकि फिल्म में ताजगी नज़र आएं, लेकिन सलमान ने सवाल उठा दिया कि कैटरीना के फिल्म में रहने से दर्शक जुड़ाव महसूस करेंगे.

फैंटम, फितूर के बाद करण जौहर के बैनर यानि धर्मा प्रोडक्शन की कटरीना कैफ और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म *बार बार देखो* बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई जिससे कैटरीना की मायूसी और बढ़ गई. कैटरीना का इस फिल्म से बड़ी उम्मीदें थी पर फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई. अपने करियर को लेकर कैटरीना की चिंता और बढ़ गई. रणबीर कपूर के चक्कर में कैटरीना ने अपने करियर पर ध्यान देना छोड़ दिया था क्योंकि कैटरीना यह निश्चित मान कर चल रही थी कि रणबीर से ही उनकी शादी होगी, लेकिन रणबीर से ब्रेक अप के बाद उन्हें अपने करियर की सुध आई. इस दौरान दीपिका, आलिया, श्रद्धा कपूर जैसी एक्ट्रेसस कैटरीना से कही ज्यादा आगे निकल गई. लेकिन सलमान ने कैटरीना को ऐसा तोहफा दे दिया कि कैटरीना के चेहरे पर फिर मुस्कान तैर गई.

यश राज फिल्म्स ने *एक था टाइगर* के सीक्वल को बनाने के लिए घोषणा कर दी है. इस फिल्म का नाम *टाइगर जिंदा है* रखा गया है. हाल ही में यश राज फिल्म्स ने *टाइगर जिंदा है* का पोस्टर भी लांच कर दिया है और अच्छी बात यह है कि कैटरीना को लेकर यश राज ने फिल्म की घोषणा की है. इसमें वे सलमान खान के अपोजिट नज़र आएंगी. कहा जा रहा है कि सलमान के कहने पर ही कैटरीना को फिल्म से जोड़ा गया है. फिल्म के निर्माता–निर्देशक चाहते थे कि कैटरीना की जगह किसी नई हीरोइन को लिया जाए ताकि फिल्म में ताजगी नज़र आएं, लेकिन सलमान ने सवाल उठा दिया कि कैटरीना के फिल्म में रहने से दर्शक जुड़ाव महसूस करेंगे. कैटरीना के नाम की सलमान ने पुरजोर तरीके से वकालात की और इस सुपरस्टार की बात को मानने के सिवाय कोई चारा नहीं था. कैटरीना के करियर को जिंदा रखने के लिए एक बड़ी और जोरदार फिल्म की जरूरत थी जो *टाइगर जिंदा है* से पूरी हो गई.■

टाइगर जिंदा है

सलमान खान अब समझ गए हैं कि यदि अपनी फिल्मों को हिट बनाना है तो प्रयोग से घबराना नहीं होगा. बजरंगी भाईजान और सुल्तान सलमान की फॉर्मूला फिल्मों से हट कर थी जिसे बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिली. सुल्तान में सलमान पहलवान बन गए. पहली बार उन्होंने अपने किसी किरदार के लिए इतनी मेहनत की और नतीजा अच्छा रहा. फिल्में ब्लॉकबस्टर रही.

फिल्म में सलमान 17 से 70 साल तक की उम्र में नज़र आएंगे.

सुल्तान की ब्लॉकबस्टर टीम, सलमान खान और अली अब्बास ज़फर, फिर साथ काम करने जा रहे हैं. यश राज फिल्म्स ने *टाइगर जिंदा है* बनाने की घोषणा की है. अब वे *टाइगर जिंदा है* के लिए 70 वर्ष के बूढ़े के रूप में नज़र आएंगे. कहा जा रहा है कि फिल्म में सलमान 17 से 70 साल तक की उम्र में नज़र आएंगे. इसके लिए उन्हें अपने वजन, हेअर स्टाइल और मेकअप में काफी परिवर्तन करना पड़ेगा और सलमान इसके लिए तैयार भी हैं.

टाइगर जिंदा है वहीं से शुरू होगी जहां पर एक था टाइगर ख़त्म हुई थी. इसमें टाइगर की जिंदगी में आने वाले उतार–चढ़ाव दिखाए जाएंगे. साथ ही उसके अतीत की झलकियां भी नज़र आएंगी. फिल्म की शूटिंग मार्च 2017 में शुरू होगी और इसे क्रिसमस 2017 पर प्रदर्शित किया जाएगा.■

रणबीर कपूर के चक्कर में कैटरीना ने अपने करियर पर ध्यान देना छोड़ दिया था लेकिन रणबीर से ब्रेक अप के बाद उन्हें अपने करियर की सुध आई.

फ्लैश बैक

जब बबीता को फिल्मी दुनिया छोड़नी पड़ी

बबीता का करियर सिर्फ सात साल लंबा है, लेकिन उन्होंने इस छोटे–से सफर में भी नामी सितारों के साथ काम किया है. साधना और बबीता रिश्ते में चचेरी बहनें हैं. आरके नय्यर का पारस–स्पर्श पाकर साधना सिंड्रेला की तरह फिल्मों में चमक गईं.

बबीता के पिता अभिनेता हरि शिवदासानी अच्छे खिलाड़ी थे. एक फ्रेंच महिला उनकी दीवानी हो गई और उनसे शादी कर ली. इस तरह पिता सिंधी और मां योरपीयन होने से बबीता विदेशी मेम की तरह गोरी–चिट्टी थीं और नाक–नक्श आकर्षक होने से फिल्मों में काम मिलने में उन्हें जरा भी परेशानी नहीं हुई.

हरि शिवदासानी एक स्टूडियो के मालिक थे. घाटे के चलते उनका स्टूडियो बिक गया. बाद में वे अनेक फिल्मों में चरित्र अभिनेता के रूप में काम करते रहे.

बबीता के घर निर्माता जीपी सिप्पी का आना–जाना था. उन्होंने स्क्रीन टेस्ट लेकर बबीता को नए नायक राजेश खन्ना के साथ फिल्म *राज* में पेश किया. फिल्म *राज* नहीं चली, मगर बबीता को लगातार काम मिलता गया. इसकी एक वजह यह भी रही कि उस दौर की ए–ग्रेड नायिकाएं वहीदा रहमान, माला सिन्हा, वैजयंतीमाला, शर्मिला टैगोर बहुत ज्यादा व्यस्त थीं. इसलिए नई नायिकाओं बबीता, साधना, मुमताज को फिल्मों में अवसर मिलते रहे.

मनोज कुमार की फिल्म पहचान में बबीता उनके साथ थीं. फिल्म सुपरहिट हुई. अभिनय में कमजोर होने के बावजूद बबीता को शम्मी कपूर, राजेन्द्र कुमार, धर्मेन्द्र, जीतेन्द्र जैसे सितारों के साथ काम मिला. इन सितारों की वजह से फिल्में चलीं और बबीता का करियर भी पटरी पर चल पड़ा.जीतेन्द्र के साथ दक्षिण में बनी फिल्म फर्ज ने सफलता के कई रिकॉर्ड कायम किए. इसमें बबीता नायिका थी. प्रकाश मेहरा की *हसीना मान जाएगी* में बबीता की कॉमेडी को काफी सराहा गया. बबीता में अभिनेत्री से ज्यादा गुण मैनेजमेंट के रहे हैं. उन्होंने अपना करियर

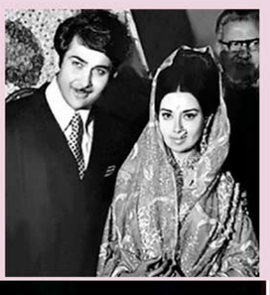

चतुर व्यवसायी की तरह चलाया.

सन् 1971 में बबीता ने कपूर खानदान में प्रवेश करते हुए राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर से शादी कर ली. खानदान के नियम अनुसार कोई बहू फिल्मों में काम नहीं कर सकती थी. लिहाजा बबीता को भी फिल्मी दुनिया छोड़ना पड़ी.

आरके बैनर की फिल्म *कल आज और कल* में उन्होंने कपूर खानदान की तीन पीढ़ियों (पृथ्वीराज, राज और रणधीर) के साथ काम किया. शादी के बाद बची हुई फिल्में पूरी की और फिर परिवार बढ़ाया. करिश्मा और करीना का जन्म हुआ. वैवाहिक जीवन में तनाव रहने लगा. बबीता अपनी बेटियों को लेकर अलग रहने चली गईं.

बबीता ने परदे के पीछे रहकर अपनी बेटियों के करियर बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है. करिश्मा ने फिल्मों में सफलता के परचम लहराए और दूसरी बेटी करीना इस समय बॉलीवुड की टॉप स्टार्स में से एक हैं.

बबीता मुंबई के वृद्धाश्रमों में जाकर दीन–दुखियों की सेवा करती हैं. हर जरूरतमंद की मदद करना उनका स्वभाव बन गया है. दोनों बेटियों की परवरिश में बबीता ने बहुत त्याग किया है. उस त्याग की बेशुमार कीमत आज उन्हें मिल भी रही है.■

प्रियंका चोपड़ा और सरोज खान फेमपावरमेंट अवॉर्ड से सम्मानित

बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और फिल्म निर्माता शोभा कपूर और कोरियोग्राफर सरोज खान को चुने हुए क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया है. फेमपावरमेंट वीमेन अचीवर्स नाम से प्रख्यात इन पुरस्कारों की शुरुआत मॉलिक्यूल कम्युनिकेशंस द्वारा जी.टीवी के साथ मिलकर की गई है. हाल ही में यह पुरस्कार प्रदान किए गए.

पुरस्कार से सम्मानित अन्य महिलाओं में खेल के क्षेत्र में हेतल दवे, कॉरपोरेट के क्षेत्र में शिखा शर्मा, पत्रकारिता के क्षेत्र में शैली चोपड़ा, शिक्षा के क्षेत्र में गीतांजलि बाबर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रीति श्राफ, मनोरंजन के क्षेत्र में शानू शर्मा, फाइन आर्ट के क्षेत्र में आरोही सिंह, युवा उद्यमी के क्षेत्र में अनीषा सिंह और साहित्य के क्षेत्र में एस. प्रसन्नश्री शामिल हैं.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com